R.N.I. NO.HIN/2002/8718 www.akshnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

वर्ष 19, अंक-18
16 से 30 जून 2021
पृष्ठ-48
मूल्य 25 रूपये

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

● तीसरी लहर से निपटने को तैयार ● नाथ की एकला चलो नीति...!

डूबती अर्थव्यवस्था को चाहिए ऑक्सीजन

Anu Sales Corporation
STart Max
We Deal in
Pathology & Medical
Equipment
Add: Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
M.: 9329556524, 9329556530
Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

राजपथ

10-11 सियासी मुलाकातें

देश की राजनीति में मप्र भाजपा को सबसे सक्रिय संगठन माना जाता है। विगत दिनों जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर ढलने लगी, मप्र के नेताओं की सियासी मुलाकातें बढ़ने लगी। दिल्ली से लेकर भोपाल तक लगभग...

लालफीताशाही

13 काम मिला... भुगतान नहीं

जल संरक्षण के कामों को केंद्र बिंदु में रखने वाले मनरेगा में भुगतान एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। इस योजना की क्षमता को बीते वर्ष 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन के बाद बेहतर तरीके से पहचाना गया था।

समस्या

15 चंबल में अब भी डकैत

चंबल में अभी डकैतों की सक्रियता कम नहीं हुई है। चंबल के किनारे छुपकर मप्र-राजस्थान में सक्रिय डकैत गुड्डा गुर्जर के बाएं हाथ बॉलिस्टर गुर्जर को पुलिस ने पकड़ा है। उसके खिलाफ मुरैना, शिवपुरी और श्योपुर में 13 मामले दर्ज हैं।

अवैध खनन

20 माफिया के निशाने पर अफसर

दतिया जिले के सेंवढ़ा अनुभाग में अवैध रेत उत्खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां आए दिन घटनाएं हो रही हैं। कभी हमला, तो कभी हमले की धमकी। डरे सहमे अफसर भी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। बावजूद जिम्मेदार प्रशासनिक अमले द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

आवरण कथा

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए जद्दोजहद करते लोगों और श्मशानों में लंबी कतारें चर्चा का विषय बनी रहीं। वहीं कोविड की दूसरी लहर अर्थव्यवस्था को लगातार कमजोर करती गई। आज स्थिति यह हो गई है कि सरकार के पास कोई ठोस नीति नजर नहीं आ रही है, जिससे डूबती अर्थव्यवस्था को उबारा जा सके। उधर, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से उद्योग-धंधे रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे हैं। यानी देश के सामने बड़ी चुनौती है।

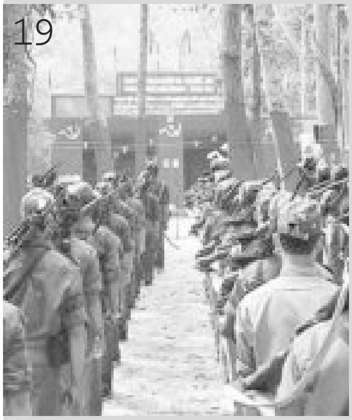

राजनीति

30-31 नहीं दिख रहा भविष्य

2014 में सत्ता जाने के बाद कांग्रेस को कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसके पास युवाओं की एक ऐसी टीम थी जो भविष्य में कांग्रेस को बड़ा आधार दे सकती थी। लेकिन सोनिया और राहुल गांधी के उपेक्षा से युवाओं की यह टीम बिखरने लगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब जितिन प्रसाद...

छत्तीसगढ़

34 कैंप के खिलाफ 40 गांवों के लोग

ओवाद प्रभावित सुकमा जिले के सिलगेर में पुलिस फायरिंग में तीन आदिवासियों की मौत के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। बीजापुर और सुकमा जिले के कलेक्टरों के साथ बैठक के बाद भी आदिवासी अपनी जमीन से कैंप हटाए...

महाराष्ट्र

36 पवार की पावर पॉलिटिक्स

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी रणनीति के काम से ब्रेक ले चुके प्रशांत किशोर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के बीच गत दिनों तकरीबन 4 घंटे की लंबी मुलाकात हुई। शरद पवार के मुंबई स्थित सिल्वर ओके बंगले में हुई इस मीटिंग...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

कोरोना का रोना कब तक...?

किसी शायर का एक शेर है...

किसी की मौत देती है किसी को जिन्दगी यूं भी।
वही जलती है चूल्हे में जो लकड़ी सूख जाती है...।।

कोरोना संक्रमण ने देश-दुनिया का हाल कुछ ऐसा ही कर डाला है। कोरोना की पहली लहर थमने के बाद लोग राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि दूसरी लहर छा गई। यह लहर इतनी घातक थी कि लोगों को मौत नजर आने लगी। लेकिन अब दूसरी लहर का असर कम पड़ने के साथ ही बंदी-पाबंदियों में ढील देना शुरू हो गया है। यह अब अपरिहार्य हो गया है। क्योंकि लंबे समय से कारोबारी गतिविधियां बंद पड़ी हैं। अर्थव्यवस्था को भारी चपत लग रही है। आम लोगों को मुश्किलों से दो-चार होना पड़ रहा है। ऐसे पाबंदियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के अलावा कोई रास्ता बचता भी नहीं है। इसीलिए दिल्ली, महाराष्ट्र, उप्र, मप्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्य अपने-अपने हिसाब से प्रतिबंधों में ढील दे रहे हैं। आखिर कब तक कोरोना का रोना चलता रहेगा। कोरोना के कारण देश और राज्यों की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, वहीं बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी बढ़ गई है। सरकार के साथ ही आमजन के सामने चुनौती है कि कोरोना का रोना छोड़कर अब कैसे नए लक्ष्य और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ें। हालांकि तीसरी लहर की भी चेतावनी हो गई है। ऐसे में हमें कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। सच तो यह है कि महामारी का खतरा कहीं से कम नहीं पड़ा है। अभी सिर्फ असर कम हुआ है। राहत की बात इतनी ही है कि संक्रमण की दर कम हुई है। मरीजों के स्वस्थ्य होने की दर भी 95 फीसदी से ऊपर है। मौतों के आंकड़े भी नीचे आ रहे हैं। ऐसे में सावधानी के साथ काम-धंधे फिर से शुरू करने में कोई हर्ज नहीं। इससे तो हालात सामान्य बनाने में मदद ही मिलेगी। बंदी और पाबंदियों से सबसे ज्यादा मुश्किल रोजाना कमाने-खाने वाले तबके को हो रही है। इनमें दिहाड़ी मजदूरों से लेकर रेहड़ी-पटरी लगाने वाले तक हैं। छोटे-मोटे कारोबारी हैं। बंदी की सबसे ज्यादा मार इसी तबके पर पड़ी है। एक करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। एक मोटा अनुमान यह है कि इस बार डेढ़ महीने की बंदी से देश को 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मौजूदा हालात में फूंक-फूंक कर ही कदम उठाने की जरूरत है। एक साथ सारी गतिविधियों को खोल देने से फिर से बड़ा जोखिम पैदा हो सकता है। इसलिए हर जगह के हालात को देखते हुए ही ढील देना उचित होगा। गौरतलब है कि इस बार दिल्ली सरकार ने 50 फीसदी क्षमता के साथ मेट्रो चलाने की छूट दी है। मॉल और बाजार सम-विषम आधार पर खुलेंगे, ताकि बाजारों में भीड़ न बढ़े। राज्यों के सामने अब दोहरी चुनौती है। कारोबार गतिविधियां शुरू करते हुए जनजीवन को पटरी पर लाना है और संक्रमण को भी फैलने से रोकना है। छोटे-बड़े कारोबार ही राज्यों के राजस्व का स्रोत होते हैं। इसी से अर्थव्यवस्था चलती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हालात सामान्य बनाने में लोगों की भूमिका सबसे अहम है। ढील का मतलब यह कतई नहीं कि अब सब कुछ सामान्य हो चला है। जरा-सी छूट मिलते ही लोग किस कदर बेपरवाह हो जाते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। यह नहीं भूलना चाहिए कि तीसरी लहर का खतरा सामने है। ऐसे में महामारी से बचाव के लिए जरूरी नियमों का सख्ती से पालन ही हमें संकट से बचाएगा। वरना फिर से घरों में कैद होने की नौबत आ सकती है।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 19, अंक 18, पृष्ठ-48, 16 से 30 जून, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
W ebsite : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता**:- इंद्रकुमार,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़**:- संजय शुक्ला, मार्कण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ** :- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुति सिंलटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

गांवों पर फोकस जरूरी

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मप्र सरकार ने जनता को सहभागी बनाकर एक मिसाल पेश की है। ट्रेसिंग और टेस्टिंग में जनता का भरपूर सहयोग मिला है। कोरोना संक्रमण गांवों में फैल रहा है। वहां इसका सामना बिना जनशक्ति और जनसहयोग के नहीं किया जा सकता।

● **वर्षा मीणा,** भोपाल (म.प्र.)

खाद का संकट

मप्र में किसानों के सामने खाद का संकट आने के आसार हैं। अभी किसान फसल के लिए खेतों में तैयारी कर रहे हैं। खाद की मांग जून से तेजी पकड़ रही है। सरकार को किसानों की परेशानी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि उन्हें पुराने दामों में खाद मिल सके।

● **राकेश सिंह,** सीहोर (म.प्र.)

बढ़ रहे निवेशक

देशभर के साथ मप्र में भी बीते एक साल में निवेशकों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। मप्र सरकार ने कोरोना संक्रमणकाल में अधिक से अधिक निवेश करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नीतिगत फैसले लिए हैं। इस कारण निवेशकों के लिए मप्र आकर्षण का केंद्र बना है।

● **दिनेश राय,** इंदौर (म.प्र.)

महंगाई की मार

पिछले दो साल से कोरोना ने न केवल भारत और विश्व की हेल्थ पर असर डाला है, बल्कि विश्व की आर्थिक स्थिति को भी डांवाडोल कर दिया है। भारत की आर्थिक स्थिति की विश्व में अपकमिंग इकोनॉमी या ऐसे राष्ट्रों में गिनती होती है जहां आर्थिक उन्नति की अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन कोरोना ने इस आर्थिक उन्नति पर बड़ा बुरा प्रभाव डाला है। कोरोना ने आम आदमी की कमर तोड़ दी, खासतौर से पिछले दो साल से। नौकरी का अभाव तो है ही साथ ही जिनकी नौकरियां है उनकी तनख्वाह कट चुकी है। मंहगाई शेषनाग की तरह फन फैला रही है। देखते ही देखते पेट्रोल 100 पार कर गया। डीजल भी जल्दी ही पेट्रोल के भाव को पकड़ने वाला है। ऐसे ही चलता रहा तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा।

● **चेतन चौहान,** ग्वालियर (म.प्र.)

जनसंख्या पर ध्यान...!

प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर देश ही नहीं पूरी दुनिया के औसत से ज्यादा है। देश के अन्य राज्यों से तुलना करें तो जनसंख्या वृद्धि में मप्र पांचवें नंबर पर आता है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का टीएफआर मप्र से कम है। जनसंख्या नियंत्रण देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि की दर ज्यादा है। इन राज्यों में मप्र भी शुमार है। परिवार नियोजन में प्रदेश के सिर्फ पांच फीसदी पुरुषों की रुचि है।

● **प्रशांत शर्मा,** ग्वालियर (म.प्र.)

तीसरी लहर के लिए सतर्कता जरूरी

देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप जारी है। इस बीच राहत की खबर आ रही है कि अब संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में नए मामले घटने लगे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, उप्र, मप्र, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में थोड़ा सुधार दिख रहा है। हालांकि अब भी कोराना का खतरा टला नहीं है। सरकार और जनता दोनों को चौकन्ना रहना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार तीसरी लहर और खतरनाक होने की संभावना है। इसलिए देश की जनता को अभी और नियमों में बंधकर रहना होगा।

● **शिवेंद्र मेहतो,** नई दिल्ली

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

योगी की बढ़ती मुसीबतें

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों चौतरफा दबाव में बताए जा रहे हैं। हिन्दुत्व के पोस्टर बॉय बन देश की राजनीति में अपना दबदबा बनाने वाले योगी का बढ़ता कद लंबे अर्से से दिल्ली दरबार को खटकने लगा था। भाजपा आलाकमान योगी आदित्यनाथ से नाखुश है जैसी चर्चा लंबे अर्से से दिल्ली-लखनऊ के सत्ता गलियारों में चटखारे लेकर कही-सुनी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गुजरात में काम कर चुके पूर्व आईएएस एसके शर्मा को यकायक ही उप्र विधान परिषद् का सदस्य बना पार्टी नेतृत्व ने इन चर्चाओं को खासी हवा देने का काम किया। कोरोना की दूसरी लहर में उप्र की बदतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से जनता की भारी नाराजगी, पंचायत चुनावों में भाजपा का खराब प्रदर्शन और पार्टी सांसदों-विधायकों का तेजी से बढ़ रहा योगी विरोध पार्टी आलाकमान को मुख्यमंत्री के पर कतरने का मौका दे रहा है। ऐसे में खबर गर्म है कि जल्द ही राज्य भाजपा संगठन और योगी मंत्रिमंडल में कुछ बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। पिछले दिनों संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले संग भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठकी, मुख्यमंत्री का गत सप्ताह राज्यपाल आनंदीबेन संग लंबी मुलाकात करना इन चर्चाओं की पुष्टि करता नजर आ रहा है।

सिद्धू को कमान देने की तैयारी

पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से नाराज विधायकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। राज्य विधानसभा के चुनाव मात्र 8 माह बाद होने हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान इन दिनों प्रदेश संगठन में एका बनाने की कवायद तो कर रहा है लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का अड़ियल रूख इस प्रयास को परवान नहीं चढ़ते दे रहा है। अमरिंदर सिंह पार्टी आलाकमान तक की सुनने को तैयार नहीं हैं। राज्य के प्रभारी महासचिव हरीश रावत ने पिछले दिनों नवजोत सिंह सिद्धू को जैसे-तैसे मनाया लेकिन अमरिंदर सिंह को रावत इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए कि वे सिद्धू को वापस मंत्रिमंडल में शामिल कर लें। कुछ समय तक खामोश रहने के बाद अब सिद्धू एक बार फिर से कैप्टन पर हमलावर हो चुके हैं। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अब प्रदेश संगठन में हालात सामान्य करने के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी बना डाली है। इन दिनों यह कमेटी राज्य के सभी विधायकों से एक-एक कर मिल रही है। जानकारों का दावा है कि कैप्टन के अड़ियल रूख से सख्त नाराज सोनिया इस कमेटी की रिपोर्ट आने के पश्चात प्रदेश कांग्रेस की कमान सिद्धू को सौंपने का मन बना चुकी हैं। यदि ऐसा होता है तो यह देखना खासा दिलचस्प होगा कि अमरिंदर सिंह इस फैसले को स्वीकारेंगे या फिर बगावत कर अलग क्षेत्रीय दल बनाने का प्रयास करेंगे।

बगैर मुखिया शीर्ष पुलिस बल

दिल्ली दरबार में इन दिनों इस बात की खासी चर्चा है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही देश की बड़ी जांच एजेंसियों एवं सुरक्षा बलों में समय रहते शीर्ष पदों पर नियुक्तियां न किए जाने का अघोषित नियम बन चुका है। सीबीआई के निदेशक की सेवानिवृति के तीन माह बाद नया निदेशक पिछले दिनों नियुक्त किया गया। हालांकि परंपरा ऐसे किसी भी पद पर तैनात अधिकारी की सेवानिवृति से पहले ही उसके उत्तराधिकारी को नियुक्ति किए जाने की रही है। ठीक इसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण आतंक निरोधक एजेंसी एनआईए का पद भी खाली चल रहा है। मई 31 को इसके पिछले प्रमुख वायएस मोदी रिटायर हो चुके हैं। तब से अभी तक सीआरपीएफ के महानिदेशक का इस एजेंसी का कार्यवाहक मुखिया बना काम चलाया जा रहा है। सीआरपीएफ के महानिदेशक का पद भी रिक्त पड़ा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुखिया को अभी तक सरकार नियुक्ति नहीं कर पाई है। इससे पहले बीएसएफ, एनएसजी समेत कई प्रमुख एजेंसियों के पद लंबे अर्से तक रिक्त रखे गए। चर्चा है कि केंद्र अपने करीबी अफसरों की नियुक्ति करने के चलते लंबे अर्से तक इन पदों को रिक्त रख रही है ताकि उन वरिष्ठ अफसरों के दावों को खारिज किया जा सके जिनका कार्यकाल जल्द समाप्त होने वाला है।

शशिकला रिटर्न्स

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के राज में उनकी खासी करीबी शशिकला की तूती बोला करती थी। लेकिन लंबी बीमारी के बाद जयललिता की मृत्यु ने सारे समीकरण बदल डाले। शशिकला मुख्यमंत्री बनने की कगार पर पहुंच चुकी थीं कि भ्रष्टाचार के एक मामले में मिली चार बरस की सजा ने उन्हें कारावास पहुंचा डाला। राज्य विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अपनी सजा काट वापस लौटी शशिकला ने यकायक ही राजनीति से अलविदा कह सबको चौंका दिया। कयासबाजियों का जमकर दौर चला। कहा गया कि भाजपा के बदाव में आकर वे वाकआउट करने को मजबूर हो गई थीं। लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने राजनीति में कमबैक का मन बना लिया है। सूत्रों का दावा है कि डीएमके की शानदार जीत से पस्त अन्नाद्रमुक का कैडर पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और उपमुख्यमंत्री पनीरसेल्वम के स्थान पर शशिकला की वापसी चाह रहा है। स्वयं शशिकला ने भी दोबारा से पार्टी की कमान संभालने की कवायद शुरू कर दी है।

महाराज के काज

उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपने बयानों से राज्य सरकार को संकट में डाल रहे हैं। सतपाल महाराज मुख्यमंत्री रावत की कोई परवाह नहीं करते। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में कुंभ के समय मुख्यमंत्री ने संतों के सामने वादा किया था कि उत्तराखंड के चार धामों के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार द्वारा बनाया गए देवस्थानम बोर्ड के बारे में पुनर्विचार किया जाएगा और इस बोर्ड से 51 मंदिर बाहर किए जाएंगे। लेकिन दो महीने बाद सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री के तीर्थ पुरोहितों को शांत करने के खेल को एकाएक यह कहकर बिगाड़ दिया कि देवस्थानम बोर्ड के बारे में राज्य सरकार कोई विचार नहीं कर रही है ना ही कोई विचार करेगी। इस पर उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों में तीखी प्रतिक्रिया हुई। महाराज की ऐसी कार्यप्रणाली से प्रदेश सरकार के साथ ही संगठन भी परेशान है। लेकिन महाराज तो महाराज हैं, वे किसी की सुनने को तैयार नहीं हैं।

बड़े साहब का याराना

प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के बड़े साहब का याराना इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। साहब के बारे में ख्यात है कि वे किसी से मिलते-जुलते नहीं हैं। उनकी अब तक की नौकरी में ऐसा देखने को भी मिला है कि वे लोगों से कम ही मिलते हैं। लेकिन पिछले कुछ माह से साहब के व्यवहार में बदलाव आ गया है। साहब कई प्रतिष्ठित लोगों से खुलकर न केवल मिल रहे हैं, बल्कि दोस्ती भी गांठ रहे हैं। प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों साहब के ऐसे ही दो दोस्तों की चर्चा खूब हो रही है। एक दोस्त देश की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो दूसरे दोस्त पत्थरों के कारोबारी हैं। सूत्र बताते हैं कि साहब की दोस्ती इस मुकाम पर पहुंच गई है कि उनके दोस्त जो भी कहते हैं वे उसे करने से मना नहीं करते हैं। सूत्रों का कहना है कि साहब की दोस्ती का उनके व्यवसायिक मित्र जमकर फायदा भी उठा रहे हैं। पत्थरों का काम करने वाले व्यवसायी को आवंटित एक पेट्रोलपंप भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, वह पेट्रोलपंप राजधानी के बीचोंबीच या यूं कहें कि शहर के दिल में आवंटित हुआ है। जिस क्षेत्र में पेट्रोलपंप के लिए भूखंड आवंटित हुआ है वह क्षेत्र संवेदनशील माना जाता है। उसके आसपास घनी आबादी बसी हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर व्यवसायी को उक्त जगह पेट्रोलपंप के लिए जमीन कैसे आवंटित की गई है।

हिस्से के लिए माननीय नाराज

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक मंत्री की नाराजगी खासी चर्चा में है। सूत्रों के अनुसार उनकी नाराजगी की वजह यह है कि प्रदेश की कुछ बड़ी योजनाओं में उनको हिस्सा नहीं मिल पाया है। इसकी भड़ास मंत्रीजी कैबिनेट की बैठक में भी निकाल चुके हैं। दरअसल, मंत्रीजी को पहले ही जानकारी मिल गई थी कि कुछ बड़ी योजनाएं बन रही हैं। मंत्रीजी को आस थी कि योजना को अमली जामा पहनाने से पहले उनको उनके हिस्से के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौरतलब है कि हमेशा सुर्खियों में रहने के आदी मंत्रीजी यारबाज माने जाते हैं। उनकी यारी पत्रकारों से इस कदर है कि जब वे सुबह टहलने निकलते हैं तो उनके साथ पत्रकार रहते हैं, जब वे नाश्ता करते हैं तब भी उनके साथ पत्रकार रहते हैं और फिर रात को जब टहलते हैं तब भी उन्हें पत्रकार घेरे रहते हैं। यानी माननीय चारों याम पत्रकारों के साथ गुजारते हैं। ऐसे में माननीय को पहले ही पता चल गया था कि कुछ बड़ी योजनाएं बन रही हैं और उन योजनाओं में लाभ-हानि का प्रतिशत क्या रहेगा। लेकिन मंत्रीजी को लाभ-हानि से अलग रखकर जब योजना की घोषणा की गई तो वे नाराज हो गए और उसके विरोध में उतर गए हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि उनका हिस्सा आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा।

तबादले के लिए स्वीमिंग थैरेपी

प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल की कवायद चल रही है। हालांकि अभी सूची आई नहीं है, लेकिन अफसर मालदार विभाग और जगह पाने के लिए स्वीमिंग थैरेपी का सहारा ले रहे हैं। स्वीमिंग थैरेपी की चाह वाले अफसरों की सत्ता, संगठन और संघ के दर पर माथाटेकी चल रही है। सूत्रों का कहना है कि कई अफसर तो ऐसे हैं जो मनमाफिक विभाग और जगह पाने के लिए मुंहमांगी लक्ष्मी दान करने को तैयार हैं। अफसरों की लालसा को देखते हुए कई दलालनुमा लोग भी सक्रिय हो गए हैं। वे अफसरों को सत्ता, संगठन और संघ के दिग्गजों के पास ले जा रहे हैं। इनमें से कईयों ने तो मुंहमांगी रकम चढ़ा दी है। लेकिन उनकी मंशा पूरी होती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि मंत्रालय की चौथी मंजिल पर किसी की नहीं सुनी जा रही है। दरअसल, इस समय प्रदेश में चौथी मंजिल सबसे ताकतवर है। सरकार को चौथी मंजिल पर इस कदर भरोसा है कि वहां के अफसर जिस चीज को मना कर दें, वह होना मुश्किल है। ऐसे में अब वे लोग परेशान होकर घूम रहे हैं, जिन्होंने अपने मनमाफिक तबादले के लिए मोटी चढ़ोत्तरी दी है। हालांकि जिन लोगों को उन्होंने लक्ष्मी का दान दिया है, वे अभी भी दम भर रहे हैं कि समय आने दो सूची में नाम शामिल हो जाएगा। लेकिन उन अफसरों को यह बात भलीभांति मालूम है कि चौथी मंजिल की मंशा के विपरीत प्रशासन में कुछ भी होना असंभव है। अब देखना यह है कि किसको स्वीमिंग थैरेपी का लाभ मिलता है।

वन-टू-वन क्यों?

विगत दिनों प्रदेश कैबिनेट की बैठक राजधानी के पास के एक शहर के एक रिसोर्ट में आयोजित की गई। बैठक में एक मंत्री की कार्यप्रणाली चर्चा में रही। इसकी वजह यह है कि मंत्रीजी बार-बार मांग कर रहे थे कि मंत्रियों से मुख्यमंत्री वन-टू-वन चर्चा करें। मंत्रीजी की बार-बार मांग से परेशान होकर एक मंत्री जो पूर्व में संगठन महामंत्री रह चुके हैं, उन्होंने वन-टू-वन को सिरे से खारिज कर दिया। उधर, मंत्रीजी की वन-टू-वन चाह की जब पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि मंत्रीजी अपने विभाग के बड़े अफसर से खुश नहीं हैं। वह चाहते हैं कि उक्त अफसर उनके आसपास भी नहीं रहें। दरअसल, उक्त अफसर माननीय की मंशा पर पानी फेर देते हैं। माननीय चाहते हैं कि विभाग में उनकी चले और वे मनमाने तरीके से काम करके लक्ष्मी बटोरें। इसके लिए मंत्रीजी जो भी प्रस्ताव देते हैं, उसे उक्त अधिकारी नियमों का हवाला देकर रद्द करा देते हैं। ऐसे में माननीय चाहते थे कि उनकी मुख्यमंत्री से वन-टू-वन हो तो वे अपनी बात उनके सामने रख सकें और अधिकारी से मुक्ति पा सके।

मप्र के खेमका

2014 बैच के एक युवा आईएएस मप्र का खेमका बन गए हैं। यानी जिस तरह हरियाणा के तेज तर्रार आईएएस अशोक खेमका का बार-बार तबादला होता रहा, उसी तरह मप्र कैडर के इस युवा आईएएस का 54 माह में 8 बार तबादला हो चुका है। दरअसल, उक्त अफसर जहां भी पदस्थ होते हैं, वहां वे अपनी कार्यप्रणाली और ईमानदारी के कारण जनता के प्रिय तो बन जाते हैं, लेकिन वरिष्ठों और नेताओं की आंख की किरकिरी बन जाते हैं। इसलिए उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर महाराष्ट्र जाने का आवेदन दे दिया है। उन्होंने आवेदन में लिखा है कि पारिवारिक कारणों से 3 साल के लिए महाराष्ट्र में प्रतिनियुक्ति पर रहना चाहता हूं। हालांकि प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इस बात की खूब चर्चा है कि उक्त अफसर मप्र की कार्यप्रणाली में फिट नहीं बैठ रहे हैं। अपनी बेबाक छवि के कारण वे कई बार सीमाएं लांघ जाते हैं। गत दिनों आईएएस एसोसिएशन के वॉट्सएप ग्रुप में कुछ गलत बातें लिख दीं। जिस पर उन्हें समझाइश दी गई और बाद में ग्रुप से बाहर कर दिया गया। इससे भी उक्त अफसर नाराज हैं और पलायन के मूड में हैं।

अक्स का आईना

कांग्रेस महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहती है तो मैं उसका आत्मविश्वास नहीं तोड़ूंगा, लेकिन उसे केरल और असम के नतीजे नहीं भूलना चाहिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी आज जिस स्थिति में है, उस पर मंथन जरूर होना चाहिए।

● **संजय राऊत**

पश्चिम बंगाल की जनता और मैं भलीभांति जानते हैं कि राज्य का हित किसमें है। इसलिए जो लोग भाजपा के झांसे में फंसकर टीएमसी छोड़ गए थे, अगर वे पुन: पार्टी में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन जिन लोगों ने पार्टी के साथ विश्वासघात करके भाजपा का दामन थामा है, उन्हें टीएमसी में कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। टीएमसी सजग और सतर्क है।

● **ममता बनर्जी**

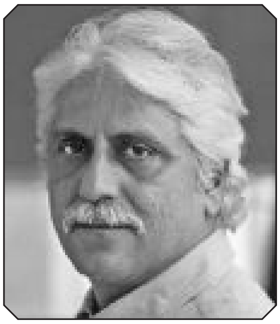

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए प्लेइंग-11 चुनना मुश्किल होगा। कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री को काफी सोच-समझकर टीम का चयन करना होगा। इसकी वजह यह है कि टीम में सभी खिलाड़ी प्लेइंग-11 के दावेदार हैं। लेकिन पिच की स्थिति को देखकर संतुलित टीम चुनने की चुनौती भारत के सामने है।

● **अयाज मेमन**

कांग्रेस और भाजपा गुजरात में अपनी-अपनी दुकानें चला रही हैं। जब-जब भाजपा को जरूरत पड़ी कांग्रेस ने उसे माल सप्लाई किया। दोनों पक्षों के बीच 27 साल की पुरानी दोस्ती है, जो निभाई जा रही है। आज कांग्रेस भाजपा की जेब में है।

● **अरविंद केजरीवाल**

मैंने बॉलीवुड में आने का सपना कभी नहीं देखा था। मैं साइंटिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन नियति मुझे बॉलीवुड में लेकर चली आई। दरअसल, लखनऊ में कॉलेज के दौरान फेयरवेल पार्टी में मुझे मिस कॉलेज चुना गया। उसके बाद मैंने मिस लखनऊ कॉम्पीटिशन में पार्टिसिपेट किया। मिस लखनऊ बनने के बाद मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूं। साइंटिस्ट बनने का सपना पीछे छूटने लगा और मैं मॉडलिंग में आगे बढ़ती गई। इसी दौरान मुझे तेलुगू फिल्म लोफर में काम मिला और हिंदी फिल्म एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी ने मुझे बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। अब तो बॉलीवुड ही मेरा घर और सपना है।

● **दिशा पाटनी**

वाक्युद्ध

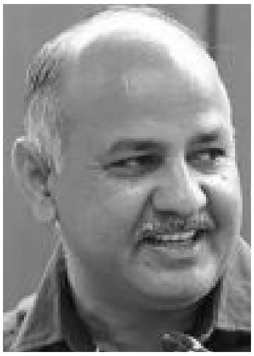

केंद्र सरकार को सिर्फ राज्यों के साथ झगड़ा करना आता है। बात-बात में केंद्र सरकार राज्यों पर निशाना साध रही है। केंद्र सरकार के मंत्री दिल्ली सरकार को गालियां दे रहे हैं। ये उनके संस्कार हैं। केंद्र ने सभी निर्णय सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ने के बाद लिए हैं। भाजपा तो अब भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है।

● **मनीष सिसोदिया**

चाहे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हो या अन्य विपक्षी पार्टियां, किसी को भी जनता की फिक्र नहीं है। अगर केंद्र सरकार हस्तक्षेप न करे तो राज्य योजनाओं का क्रियान्वयन भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। कोरोना संक्रमणकाल में सभी विपक्षी राज्य सरकारों की कार्यप्रणाली चिंतनीय रही। इसलिए केंद्र को सक्रिय होना पड़ा।

● **मनोज तिवारी**

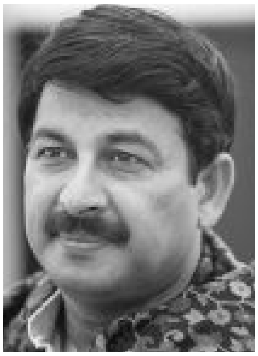

तीसरी लहर से निपटने को तैयार

कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर की तबाही से सबक लेते हुए मप्र सरकार ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली है। हर मोर्चे पर सरकार की तैयारी दुरुस्त हो रही है।

मप्र में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर घातक रही। हालांकि शासन-प्रशासन के प्रयास से कोरोना की दूसरी लहर समाप्त हो चली है। लेकिन तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। ऐसे में सरकार ने तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने, उसके प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए पुख्ता रणनीति पर काम किया जा रहा है। वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए अनुमान है कि अगले तीन या चार माह में तीसरी लहर आने की आशंका है। अनलॉक के परिणामस्वरूप गतिविधियों के बढ़ने और सावधानी का पालन नहीं करने से तीसरी लहर की संभावना बढ़ेगी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां दुरुस्त करनी शुरू कर दी हैं।

प्रदेश में तीसरी लहर का सामना करने के लिए आवश्यक अधो-संरचना तैयार की जा रही है और व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। स्वास्थ्य अधो-संरचना को सुदृढ़ करने के लिए गतिविधियां जारी हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था, बेड बढ़ाने, आईसीयू वार्ड निर्माण, पैरामेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, प्रदेश में वर्तमान समय में ऑक्सीजन युक्त बेड 14071 हैं, जिन्हें 31 अगस्त तक बढ़ाकर 19130 करना है। वहीं बाल चिकित्सा वार्ड में ऑक्सीजन युक्त 1023 बेड हैं, जिन्हें बढ़ाकर 2247 करना है। वहीं 30 सितंबर तक आईसीयू बेड 5021, पीआईसीयू बेड 1050 करने का लक्ष्य है। काटजू अस्पताल में 200 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया है, जहां 150 ऑक्सीजन बेड और 50 आईसीयू बेड हैं। अभी हाल ही में बीना रिफाइनरी में 200 बेड तथा बुदनी में 300 बेड के कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया गया।

कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अस्पतालों में वेंटीलेटर्स सहित अन्य सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाओं की व्यवस्था रखी गई है। कोरोना मरीज को दी जाने वाली सारी दवाओं का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित अन्य दवाओं का भी पूरा स्टॉक रखा गया है। सरकार की पहली कोशिश है कि तीसरी लहर आए नहीं। अगर तीसरी लहर आती है तो किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए सरकार ने व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी हैं। प्रदेश में इस समय 606 संजीवनी एम्बुलेंस हैं, वहीं 1002 के लिए नया टेंडर निकाला जाएगा। प्रदेश में 820 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस है और 1050 के लिए नया टेंडर निकाला जाएगा।

प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ ही चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की भर्ती की जा रही है। मई में 1020 स्टाफ नर्स की भर्ती की गई है। इसके अलावा 429 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती हुई है। अगस्त तक 2913 नर्सों की भर्ती होनी है। तीसरी लहर में बच्चों के अधिक प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अतः बाल रोग विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने, पैरामेडिकल स्टाफ को बच्चों के इलाज, टीकाकरण और अन्य प्रक्रियाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों के लिए आईसीयू वार्ड, ऑक्सीजन बेड्स आदि बढ़ाने, पर्याप्त उपकरण, दवाओं और उपचार सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में कार्य जारी हैं।

उधर, तीसरी लहर को रोकने के मुद्दे पर चर्चा के लिए 14 जून को सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कैबिनेट के साथ चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन करना आवश्यक है। इसके लिए ग्राम, वार्ड स्तर पर वातावरण निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय भाषा में स्लोगन, नारों, आकर्षक वाक्यों का उपयोग किया जाएगा। बैनर, होर्डिंग्स, वॉल-पेंटिंग से लोगों को मास्क लगाने, दूरी बनाने आदि के लिए प्रेरित किया जाएगा। वॉइस मैसेज, वीडियो मैसेज के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित किया जाएगा। तीसरी लहर से बचाव में टीकाकरण भी बहुत प्रभावी है। सरकार का फोकस इस दिशा में है। प्रदेश में टीकाकरण गतिविधियों को विस्तार देने की आवश्यकता है। इसे प्रदेश में अभियान का रूप देकर रिकार्ड समय में पूर्ण करना है। वैक्सीनेशन सुरक्षा चक्र है। प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान का अभिनव मॉडल प्रस्तुत करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में एक से 3 जुलाई के मध्य वैक्सीनेशन के लिए त्रि-दिवसीय महा अभियान प्रारंभ किया जाएगा।

● राजेंद्र आगाल

अस्पतालों में 20 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट शुरू

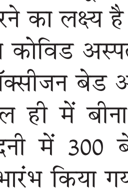

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मप्र को ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इस क्रम में कोविड-19 के उपचार में प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति की समस्या के निराकरण के कारगर उपाय के तौर पर लगाए जा रहे पीएसए ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल और कम्युनिटी हॉस्पिटल में 111 हवा से ऑक्सीजन बनाने की अनूठी टेक्नोलॉजी पर आधारित पीएसए (प्रेशर स्विंग, एडजॉर्प्सन) ऑक्सीजन प्लांट लगाने के आर्डर दिए गए थे। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में अब तक 20 प्लांट लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने बताया कि पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को समय पर लगाने के लिए संबंधित निर्माता कंपनियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि 15 जून तक 25, 30 जून तक 40, 30 जुलाई तक 81, 30 अगस्त तक 91 और 30 सितंबर तक पूरे 111 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना अस्पतालों में कर दी जाएगी। इनसे अस्पताल के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में उपलब्ध ऑक्सीजन बेड और आईसीयू आदि को ध्यान में रखते हुए जरूरत की ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, इसी अनुक्रम में क्षमता के पीएसए प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसमें 100 लीटर प्रति मिनिट से लेकर 1500 लीटर प्रति मिनिट की क्षमता वाले पीएसए प्लांट शामिल हैं। पीएसए प्लांट्स की स्थापना 10 बिस्तर के आईसीयू अस्पतालों से लेकर 150 बिस्तर (आईसीयू) वाले अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। उन्होंने बताया कि पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मद से प्राप्त राशि से की गई है।

देश की राजनीति में मप्र भाजपा को सबसे सक्रिय संगठन माना जाता है। विगत दिनों जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर ढलने लगी, मप्र के नेताओं की सियासी मुलाकातें बढ़ने लगी। दिल्ली से लेकर भोपाल तक लगभग हर दिन मुलाकातों का दौर चलता रहा। इससे प्रदेश की राजनीति में तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे। कोई मुख्यमंत्री बदल रहा था तो कोई प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन सारी मुलाकातें मात्र औपचारिकता बनकर रह गई हैं। कयासों का दौर भले ही थक गया है, लेकिन मुलाकातों का दौर अब भी जारी है।

सियासी मुलाकातें

महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जबसे भाजपा का दामन थामा है, वे मप्र की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गए हैं। कोई उन्हें भावी मुख्यमंत्री तो कोई भावी प्रदेश अध्यक्ष, तो कोई केंद्रीय मंत्री के तौर पर देख रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि सिंधिया जब अपने प्रदेश यानी मप्र आते हैं तो हलचल सी मच जाती है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने के बाद ये हलचल कुछ ज्यादा हो रही है। शायद उनके मप्र आने की खबर से ही राजधानी भोपाल में सियासी मुलाकातों का दौर तेज हुआ था। दरअसल, भाजपा के पुराने नेताओं में एक अंजाना सा भय है कि सिंधिया अगर मप्र में सक्रिय रहे तो उनका कद छोटा हो जाएगा। इसलिए मप्र भाजपा का हर एक सदस्य यही चाहता है कि सिंधिया को दिल्ली में एडजस्ट किया जाए।

उधर, सिंधिया के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की अटकलों के बीच भोपाल में उनकी मुख्यमंत्री शिवराज से लेकर संघ दफ्तर में हाजिरी ने सरगर्मी और बढ़ा दी है। इसे सिंधिया के सत्ता और संगठन में मजबूत होती पकड़ के तौर पर देखा जा रहा है। सिंधिया ऐसे समय भोपाल आए जब भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति का ऐलान किया गया है। सबसे अहम यह कि कार्यसमिति में सिंधिया समर्थकों का दबदबा है। पार्टी की तरफ से जो सूची जारी की गई है उसमें 162 सदस्य और 217 आमंत्रित सदस्यों में 68 सिंधिया समर्थकों को जगह दी गई है। 23 स्थाई सदस्यों में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान समेत ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी शामिल किया गया है। सूची में सिंधिया सातवें नंबर पर हैं। समर्थकों के दबदबे के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये पहला दौरा सबसे ज्यादा सुर्खियों में है।

भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया गत दिनों पहले मप्र के दौरे पर थे। इस वजह से कुछ दिन सूबे में सियासी मुलाकातों के नाम रहे। बता दें कि लंबे वक्त के बाद भोपाल दौरे पर आए महाराज न केवल संगठन के पदाधिकारियों से मिले बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने सीएम हाउस भी गए। इसके बाद शाम को उनकी मुलाकात संघ कार्यालय समिधा में संघ के मध्य क्षेत्र के प्रचारक दीपक विसपुते से भी हुई।

ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक दिन में एक साथ संगठन, सरकार और संघ के पदाधिकारियों से हुई इस मुलाकात के बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिरकार इन सियासी मुलाकातों के मायने क्या हैं? हालांकि जानकार मान रहे हैं कि प्रदेश कार्यसमिति के ऐलान के बाद इन मुलाकातों के सीधे तौर पर मायने कहीं ना कहीं निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियां हो सकती हैं। वजह जो भी हो लेकिन दिनभर चली मुलाकातों पर सिंधिया से लेकर भाजपा के नेताओं तक ने एक सुर में एक ही जवाब दिया कि भाजपा एक परिवार है और परिवार के सदस्यों में मुलाकातों के दौर चलते रहते हैं।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से मुलाकात करने के बाद दोपहर करीब 3:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम हाउस पहुंचे जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक की। सिंधिया और मुख्यमंत्री की मुलाकात के दौरान ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन मंत्री हितनन्द शर्मा भी सीएम हाउस पहुंचे। इसके बाद इन सभी की भी एक साथ बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियों को

सिंधिया को मंत्री बनाकर मप्र से दूर रखेगी भाजपा

राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भी मप्र का दौरा करते हैं भाजपा के अंदर विरोध और विद्रोह की आग सुलगने लगती है। ऐसे में भाजपा आलाकमान ने सिंधिया को मप्र से दूर रखने के लिए उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने का निर्णय लिया है। 15 महीने पहले पाला बदलकर भाजपा में शामिल होने वाले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि उन्हें रेल मंत्री बनाया जा सकता है। इनके पिता स्व. माधवराव सिंधिया रेल राज्यमंत्री रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान सिंधिया को जहां रेल मंत्रालय सौंपे जाने की चर्चा है, वहीं प्रदेश की राजनीति में भी फेरबदल की चर्चा चल पड़ी, जिसमें केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की केन्द्रीय मंत्रिमंडल से वापसी कराकर उन्हें संगठन में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। प्रदेश से चार सांसद केन्द्रीय मंत्री हैं, जिनमें थावरचंद गेहलोद, प्रहलाद पटेल, फग्गनसिंह कुलस्ते और नरेन्द्रसिंह तोमर शामिल हैं।

लेकर चर्चा की गई है। हालांकि इस बारे में किसी ने औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। सिंधिया भोपाल में भाजपा के लगभग सभी बड़े नेताओं से मिले लेकिन खास बात यह रही कि उन्होंने मप्र के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात नहीं की जिसको लेकर भी सियासी माहौल गर्म रहा।

दमोह में मिली हार के बाद भाजपा में सियासी मेल-मुलाकातों का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की बंद कमरे में हुई बातचीत ने कांग्रेस को बोलने का मौका दे दिया, तो शर्मा की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। ठीक बाद प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और सहसंगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी सीएम हाउस पहुंच गए। इतना ही नहीं तीनों सीएम हाउस आने से पहले संघ कार्यालय भी गए थे। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी भाजपा की छवि को सुधारने के लिए मैदान में उतर गया है। सूत्रों की माने तो यह किसी बड़े फेरबदल या पार्टी में बदलाव की ओर इशारा करता है। इसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा और शिवराज पर निशाना साधा है।

बताया जाता है कि पूरे दिन चली सियासी मुलाकात का असर प्रदेश कार्यसमिति के गठन, कोर ग्रुप, प्रदेश चुनाव संचालन समिति और अनुशासन समिति के नए नामों को लेकर हो सकता हे। माना जा रहा है कि सरकार एक बार फिर पार्टी की छवि लोगों में सकारात्मक बनाने के लिए आर्थिक और कृषि सुधार समेत लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर कुछ समितियां बनाकर राज्य सरकार के कामकाज के साथ संतुलन बिठाकर उसे पार्टी स्तर से नीचे तक ले जाने का काम करेगी। प्रदेश की सियासत में भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का तीन दिवसीय मप्र का दौरान खासा सुर्खियों में है।9 जून को राजधानी में एक के बाद एक बैठकें करने के बाद सिंधिया 10 एवं 11 जून को ग्वालियर-चंबल के प्रवास पर रहे। इस दौरान वे भाजपा के उन नेताओं के घर शोक व्यक्त करने पहुंचे जिनके परिवार में पिछले तीन महीने के भीतर कोई गुजर गया हो। सिंधिया गत दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं कभी सिंधिया परिवार के कट्टर विरोधी रहे जयभान सिंह पवैया के घर उनके पिता के निधन पर शोक जताने पहुंचे। सिंधिया के पवैया के घर पहुंचने से ही ग्वालियर-चंबल की सियासत का पारा चढ़ गया है।

सिंधिया पवैया के घर करीब 33 मिनट तक रहे। पवैया से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि पुरानी बातों को भूलकर अब मिलकर काम करेंगे। उन्होंने इसे पारिवारिक मुलाकात बताया है। जबकि पवैया ने इसे राजनीतिक मुलाकात बताया है और कहा कि एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता के घर शोक जताने आते ही हैं। बतौर पवैया वे दुख की घड़ी में सिंधिया परिवार के पास जाते रहे हैं। राजमाता सिंधिया के निधन के समय वे गए थे।ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया के निधन की खबर सुनकर वे श्योपुर में अपना कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली गए थे। वहां से उनकी पार्थिव देह के साथ ग्वालियर आए थे। हालांकि सिंधिया पहली बार पवैया के घर पहुंचे। पवैया जब मप्र सरकार में मंत्री थे, तब उनकी बेटी के शादी के दिन ही पुत्र का करंट लगने की वजह से निधन हो गया था। तब पवैया पर दुख का पहाड़ टूटा था। तब सिंधिया पवैया के घर शोक जताने नहीं पहुंचे थे।

सियासत में पवैया की छवि महल विरोधी नेता की है। जल संसाधन विभाग के उपयंत्री की नौकरी छोड़ने के बाद पवैया ने सियासत में कदम रखा। वे बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक हैं और **भाजपा के कट्टर हिंदूवादी** चेहरा हैं। पवैया महल के खिलाफ जितने मुखर होते गए, सियासत में उनका कद उतना ही बढ़ता गया। सिंधिया के भिंड, ग्वालियर और मुरैना में नेताओं के घर जाकर शोक जताने पर पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने चुटकी ली है। सिंह ने कहा कि सिंधिया वजूद तलाशने के लिए घर-घर जा रहे हैं। सिंधिया के इस बदले रूप को देखकर कांग्रेसी भी हैरान हैं।

● **कुमार राजेन्द्र**

लंच भी, डिनर भी

भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल दौरे के दौरान लंच से लेकर डिनर डिप्लोमेसी तक देखने को मिली। वह 9 जून को दोपहर करीब 1 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सीधे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के चार इमली स्थित बंगले पहुंचे। वहां पर भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन मंत्री हितनन्द शर्मा पहले से मौजूद थे। इन तीनों के साथ सिंधिया की बंद कमरे में मुलाकात हुई और फिर एक साथ वहीं पर लंच भी किया। खास बात यह रही कि इस दौरान सिंधिया और वीडी शर्मा की गर्मजोशी से मुलाकात हुई। इसके बाद रात के वक्त करीब 8:30 बजे सिंधिया पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के 74 बंगला स्थित बंगले पर पहुंचे जहां उन्होंने डिनर किया। गोपाल भार्गव ने शॉल और श्रीफल देकर सिंधिया को अपने घर से विदा किया।

शिवराज की कुर्सी पर नहीं है कोई खतरा

मप्र में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर एक बार फिर भाजपा के दिग्गज नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा सरकार की अस्थिरता की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मप्र में कोई भी अस्थिरता नहीं है। भाजपा सरकार स्थाई रूप से काम कर रही है, यहां भाजपा का बहुमत है। भाजपा ही तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान का नाम तय किया तो वे मुख्यमंत्री हैं। यही नहीं, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी कहना है कि भाजपा में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। पूरी पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मप्र के भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में एकसाथ खड़ी है। वहीं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी कहना है कि कांग्रेस भाजपा की एकता और अखंडता को बयानों से तोड़ना चाहती है।भाजपा के नेता एक-दूसरे से मेल-मुलाकात कर रहे हैं, यह बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। हम बता दें शिवराज सिंह चौहान ही मप्र के मुख्यमंत्री रहेंगे। कयास लगाने वाले लगाते रहें।

आपदाकाल में पुलिस ने अपने कार्यों से लोगों के मन में विश्वास की नींव डाली है। आंतरिक सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाली पुलिस आज कोरोना वायरस के साथ संघर्ष कर रही है।

विश्वास की नींव

पिछले सालभर से अधिक समय से लगभग पूरे देश में कोरोना संक्रमण जनित आपदा के कारण अधिकांश लोगों की दिनचर्या में व्यापक बदलाव आया है। बाहर घूमने-फिरने की प्रक्रिया लगभग ठप है।

जहां तक संभव हो रहा है, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा घर से ही काम की छूट दी गई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच एक बार फिर अधिकांश लोग अपने-अपने घरों में रह रहे हैं। लेकिन देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो वास्तव में कोरोना योद्धा कहलाने योग्य है और जो लॉकडाउन के दौर में भी अधिकांश समय सड़कों पर ही रहा। निश्चित रूप से हम पुलिस प्रशासन की ही बात कर रहे हैं जिसने कोरोना प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सड़कों पर मोर्चा संभाल रखा है।

ऐसे में इंटरनेट मीडिया के विभिन्न मंचों के जरिए हमने अनेक ऐसे वीडियो भी देखे हैं जिनमें कई बार आम जनता भी पुलिस को बुरा-भला कहते नजर आई। दरअसल पुलिस द्वारा मास्क लगाने और शारीरिक दूरी कायम रखने के कोविड प्रोटोकाल के लिए रोकने-टोकने पर कई लोग पुलिस की एक नकारात्मक छवि को गढ़ने का प्रयास करते रहे हैं। जबकि यह वास्तविकता है कि कोरोना की वीभत्स आपदा के दौरान देश में लगातार कोरोना योद्धा के रूप में डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों ने सराहनीय कार्य किया है। हालांकि आम जन मानस की मानसिकता में अब धीरे-धीरे बदलाव आ रहे हैं। विगत वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन योद्धाओं के कार्यों की सराहना की थी और इनके सम्मान में देशवासियों से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने की बात कही थी। वास्तव में इस महामारी के दौर में देश के इन कोरोना योद्धाओं ने अतुलनीय कार्य किया है और अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस वैश्विक महामारी के दौर में जहां वर्तमान में भारत सर्वाधिक प्रभावित देश बन चुका है, वहीं इसके साथ देश में एक डर का माहौल भी बना हुआ है। ऐसे में इसके खिलाफ जारी जंग के बीच उन पहलुओं को देखना रोचक होगा जिसकी बदौलत हम इस जंग को जीत सकते हैं या उसकी उम्मीद करते हैं।

कोरोना माहामारी से जारी जंग में सबसे महत्वपूर्ण है कानून व्यवस्था और उससे उपजे संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करने में पुलिस प्रशासन की भूमिका। यह उल्लेखनीय है कि देश में किसी भी सामूहिक चिंता या तनाव को कानून व्यवस्था के अनुपालन के समानांतर दुरुस्त किया जा सकता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की बढ़ती सकारात्मक भूमिका ने देश को संकट से निकालने की दिशा में अपना अहम योगदान दिया है। देश में अब तक जागरूकता के अभाव में पुलिस प्रशासन की नकारात्मक छवि गढ़ी गई थी। यह सच है कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन की पहचान कठिन समय में होती है और पुलिस प्रशासन के मामले में भी ऐसा ही हुआ। पुलिस प्रशासन की यह सकारात्मक छवि केवल आज के समय ही देखने को नहीं मिली है, बल्कि विगत कई वर्षों में विभिन्न आपदाओं, घटनाओं के दौरान भी सामने आई है। इस बार इनकी सकारात्मक छवि न केवल कोरोना योद्धा के रूप में सामने आई है, बल्कि कानून व्यवस्था के अनुपालन से लेकर पीड़ित लोगों की मदद और सामान्य सामाजिक, मानवीय जिम्मेदारियों के निर्वहन के रूप में भी देखने को मिली है।

देश के विभिन्न भागों में अपनी जान की परवाह किए बगैर आज पुलिसकर्मी लोगों की मदद कर रहे हैं, संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता फैला रहे हैं और कानून व्यवस्था का अनुपालन भी सुनिश्चित कर रहे हैं। संक्रमण के भयावह जोखिम के बीच काम कर रहे पुलिसकर्मियों को सामान्य पेशेवर जीवन में कई तरह की समस्याएं भी आ रही हैं। हमारे समाज के बीच के ही कुछ लोग अपनी कुंठा निकालने के लिए भी पुलिसकर्मियों के साथ उलझ जाते हैं। लिहाजा समाज में व्याप्त मानसिकता को बदलने की जरूरत है। इसके साथ ही, उन सभी समस्याओं के समाधान की भी जरूरत है जिसके कारण पुलिसकर्मियों को बेहद सीमित संसाधनों तथा कष्टप्रद स्थितियों में काम करना पड़ता है। कोरोना के आरंभिक चरण से लेकर अब तक हजारों पुलिसकर्मी और उनके निकट संबंधी संक्रमित भी हुए, किंतु उनका जज्बा और कर्तव्य के प्रति समर्पण कम नहीं हुआ।

● **अरविंद नारद**

400 पुलिसकर्मियों की गई जान

ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के पहले प्रसार काल के दौरान अगस्त 2020 तक करीब 77 हजार पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए थे और करीब 400 पुलिसकर्मियों ने इस वजह से अपनी जान गंवाई। हालांकि कोरोना के टीकाकरण के बाद से संक्रमण की संख्या में कमी आई है और पुलिसकर्मियों के मृत्यु दर में भी कमी आई है। किंतु इसके बाद भी जिस प्रकार पूरे देश में ये पुलिसकर्मी अभी भी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं वह निश्चित रूप से सराहनीय है। इन निष्ठावान पुलिसकर्मियों के प्रति हमारी, समाज की और सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। साथ ही, राज्य सरकारों को भी चाहिए कि पुलिस प्रशासन के आधुनिकीकरण के प्रति गंभीरता से काम करें। उनके पेशेवर जीवन को सुगम, सक्षम और सुरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करें।

काम मिला...भुगतान नहीं

जल संरक्षण के कामों को केंद्र बिंदु में रखने वाले मनरेगा में भुगतान एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। इस योजना की क्षमता को बीते वर्ष 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन के बाद बेहतर तरीके से पहचाना गया था। बीते वित्त वर्ष में मनरेगा ने न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दी थी बल्कि यह योजना एक करोड़ से अधिक प्रवासी और स्थानीय श्रमिकों के लिए आजीविका का प्रमुख साधन बनकर सामने आई थी। इस वर्ष कोविड की दूसरी खतरनाक लहर के दौरान अप्रैल और मई महीने में देश के अधिकांश राज्य तालाबंदी में रहे। लेकिन राज्यों की ओर से मनरेगा के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाई दिया। इसकी एक वजह भुगतान न मिलने की वजह से श्रमिकों का मोहभंग और दूसरी वजह यह थी कि ऐसे कोई नियम और मानक नहीं तैयार हो पाए जो कोरोना संक्रमण के जोखिम को कम करते हुए श्रम को जारी रख पाते। भारत में मनरेगा के तहत भुगतान में देरी का मामला बीते पांच वर्षों में बढ़ता गया है। देश में मनरेगा के तहत भुगतान में 16 से 30 दिनों की देरी का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है।

बीते वर्ष देशव्यापी लॉकडाउन के दरमियान जितना काम मनरेगा में मांगा और दिया गया, वैसा बीते पंद्रह वर्षों में नहीं देखा गया था। उप्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम जैसे राज्यों में कार्यदिवस की संख्या भी काफी बढ़ाई गई थी। लेकिन इन राज्यों ने विलंब भुगतान में शीर्ष जगह बनाई है। वहीं इस वर्ष इन राज्यों में मनरेगा के तहत कार्यदिवसों में भी बड़ी कमी दिखाई देती है। देश में कोविड की पहली लहर के दौरान वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत अप्रैल महीने में कुल 17.57 करोड़ कार्यदिवस अनुमानित था और इस अनुमान का 80 फीसदी यानी 14.16 करोड़ ही कार्यदिवस सृजित हो पाया था। जबकि 2020 मई महीने में 67.63 करोड़ कार्यदिवस अनुमानित था और इस अनुमान के मुकाबले 105 फीसदी यानी 71.13 करोड़ कार्यदिवस सृजित किया गया।

कोविड की पहली तालाबंदी के बाद आर्थिक संकट काफी गहरा हुआ और वित्त वर्ष 2021-22 के अप्रैल महीने में कार्यदिवस सृजन का अनुमान 2020-21 के मुकाबले करीब दोगुना 33.57 करोड़ रखा गया और अप्रैल माह में कुल 34.10 करोड़ कार्यदिवस सृजित हुए। लेकिन मई महीने में स्थिति खराब हो गई। मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के मई महीने में भी कुल 79.94 कार्यदिव कुल 54.13 करोड़ कार्यदिवस सृजित किए गए। मनरेगा के तहत अप्रैल-मई में कुल सृजित कार्यदिवस का यह आंकड़ा स्पष्ट तौर पर बताता है कि अप्रैल महीने में कार्यदिवस बीते वित्त वर्ष के मुकाबले बेहतर रहा लेकिन मई महीने में बीते वित्त वर्ष के मुकाबले बड़ी गिरावट आई है। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में मनरेगा की बदौलत ग्रामीण भारत ने देश की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया था।

मनरेगा योजना गरीब आबादी वाले राज्यों के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका फायदा उन राज्यों ने अधिक उठाया, जहां बेहतर सुशासन था। इन राज्यों ने मनरेगा का पैसा अधिक से अधिक खर्च किया, लेकिन गरीब आबादी वाले राज्य मनरेगा का फायदा नहीं उठा पाए। कोविड-19 लॉकडाउन (अप्रैल से जुलाई 2020) के दौरान मनरेगा में काम पाने वाले लोगों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 50 फीसदी अधिक थी, लेकिन अति गरीब आबादी वाले 6 राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मप्र, ओडिशा, उप्र) में यह संख्या और भी अधिक लगभग 81 फीसदी थी। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव फुगल मोहापात्रा और पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन द्वारा लिखे गए अध्याय में कहा गया है कि मनरेगा से मिलने वाले रोजगार के मामले में अति गरीब राज्यों (एचपीएस) की तुलना यदि अन्य राज्यों से की जाए तो इन गरीब राज्यों में 2014-15 के बाद से रोजगार सृजन बढ़ा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के हिसाब से ये आंकड़ें अभी भी कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की खासी कमी है। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार खासकर गैर कृषि कार्यों की भारी कमी देखी गई। ऐसे में मजदूरी करने वाले परिवारों को केवल मनरेगा के अलावा कोई काम नहीं मिला। बेशक अति गरीब आबादी वाले राज्यों में मनरेगा के तहत काम की मांग अधिक होती है और काम भी अधिक होता है, लेकिन यहां मनरेगा का खर्च बहुत अधिक नहीं होता। 2014-15 में मनरेगा के तहत कुल खर्च राशि में से 30.29 फीसदी इन 6 गरीब राज्यों में किया गया। जो 2019-20 में बढ़कर 32.28 फीसदी हो गया और अप्रैल से जुलाई 2020 में 35.35 फीसदी रहा।

● जितेंद्र तिवारी

ग्रामीण भारत के लिए जरूरी है मनरेगा

ग्रामीण भारत में मजबूत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की कमी है, इसलिए मनरेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना ग्रामीण गरीबों के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि इसके डिजाइन और ऑपरेशन में कुछ कमियां भी हैं, जिनको दूर करके लोगों की आजीविका को और बढ़ाया जा सकता है। खासकर अति गरीब प्रदेशों में मनरेगा को मजबूती से लागू किया जाना चाहिए और जिन राज्यों में अति गरीब आबादी अधिक है, वहां इसे गरीबी दूर करने के लक्ष्य से जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा, यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि मनरेगा में काम कर रहे सभी लोगों को 15 दिन के भीतर मजदूरी मिल जाए। तीसरा, एक मजबूत निरीक्षण प्रणाली विकसित करनी होगी, जिससे मनरेगा के तहत बन रही परिसंपत्तियों की गुणवत्ता का फीडबैक मिल सके।

करोड़ों की धान बर्बाद

मप्र ने अनाज उत्पादन में अभी तक 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड पाया है, लेकिन विडंबना यह है कि गोदामों की कमी के कारण हर साल लाखों मीट्रिक टन अनाज खुले में पड़े-पड़े सड़ जाता है। इस बार तो किसानों से खरीदे गए धान के रखरखाव में जिम्मेदारों ने लापरवाही की पराकाष्ठा पार कर दी। कटनी और शहडोल जिले में ओपन केप में रखा 81.86 करोड़ का 3.38 लाख क्विंटल धान सड़ने का मामला सामने आया है। 22 मई को मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में राइस मिल एसोसिएशन कटनी ने चेताया है कि वर्ष 2020-21 में खरीदकर ओपन केप में रखा 14 लाख क्विंटल धान भी बारिश में बर्बाद हो सकता है। इसके बावजूद अधिकारी हरकत में नहीं आए। जबकि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को कहा था कि सड़ रहे अनाज को गरीबों में बांट दिया जाना चाहिए।

शहडोल जिले की लालपुर हवाई पट्टी स्थित अस्थाई केप में 2020-21 में रखे धान को सहेज पाने में प्रशासन नाकाम रहा। यहां रखा करीब 10 हजार क्विंटल धान सड़ चुका है। नमी की अधिकता के कारण धान अंकुरित होकर बोरियों से बाहर आ गए हैं। एक साल में धान लगातार खराब होता रहा और अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। धान खराब होने की वजह नान के साथ फूड विभाग और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की लापरवाही को माना जा रहा है। खरीदी के समय ही अनेक स्थानों की धान भीग चुका था, जिसे नमी हालत में ही रखवा दिया गया।

नान व फूड ने पड़ताल नहीं की। अस्थाई केप के लिए बनाए गए चबूतरे में नियमानुसार इलाहाबादी व फ्लाईऐश ईंटों का उपयोग होना

मप्र में किसान अपना खून-पसीना लगाकर अनाज का बंपर उत्पादन कर रहा है, लेकिन सरकार उस अनाज के रखरखाव की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इस कारण हर साल करोड़ों रुपए के अनाज बर्बाद हो रहे हैं।

चाहिए था, लेकिन सागर के जिस ठेकेदार को काम मिला। उसके द्वारा स्थानीय स्तर से गुणवत्ताहीन ईंट का उपयोग किया गया, जिससे नमी बोरियों में जाती रही। नान प्रबंधक राकेश चौधरी ने कहा, कुछ लॉट की धान खराब हुई। जो भी नुकसान हुआ उसके लिए वेयर हाउस से वसूली की जाएगी।

वर्ष 2019-20 में किसानों से खरीदा गया 80 करोड़ रुपए की 3.28 लाख क्विंटल धान नान की लापरवाही के चलते बर्बाद हो गया। मझगवां बड़वारा, मझगवां फाटक एवं सलैया फाटक में रखी धान की मिलिंग से मिलर्स ने भी हाथ खींच लिए। जब मिलर्स ने मिलिंग से इनकार कर दिया, तब शासन ने खुले बाजार में बेचने के लिए टेंडर कॉल किए, लेकिन धान की दशा देखकर कोई आगे नहीं आया। नियमानुसार 3 माह के भीतर धान का उठाव कर लिया जाना था, लेकिन नान के तत्कालीन अधिकारियों ने ओपन केप की धान का ठीक से रखरखाव नहीं किया, जिससे बारिश में फसल बर्बाद हो गई।

बताया गया है कि शासन ने उस समय समर्थन मूल्य पर 1800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा था। जबकि परिवहन, भंडारण, खरीदी का कमीशन एवं अन्य खर्च मिलाकर धान की कीमत 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच जाती है। ओपन केप मझगवां में 2 लाख 79 हजार क्विंटल, मझगवां फाटक ओपन केप में 13 हजार क्विंटल, सलैया फाटक ओपन केप में 36 हजार क्विंटल धान रखा है। नान के जिला प्रबंधक मधुर खुर्द ने कहा, वर्ष 2019-20 में खरीदी गई धान की नीलामी के लिए शासन ने दो बार टेंडर कॉल किए थे, लेकिन किसी ने रुचि नहीं ली। अब शासन स्तर से फिर से टेंडर जारी किए जाएंगे।

● श्याम सिंह सिकरवार

30 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की मिलिंग अटकी

धान की मिलिंग कर चावल निकालने को लेकर सरकार और मिलर्स के बीच रेट पर सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में 30 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की मिलिंग अटकी हुई है। प्रदेश से बाहर के मिलर्स से मिलिंग कराने के फैसले के बाद भी सफलता नहीं मिली है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को रेट व अन्य मामलों के लिए कैबिनेट की अनुमति का इंतजार है। बारिश शुरू होने से धान खराब होने की आशंका भी बढ़ गई है। धान की क्वालिटी को लेकर मिलर्स और सरकार के बीच ठनी हुई है। सरकार धान से 67 प्रतिशत चावल लेती है अर्थात् एक क्विंटल धान से 67 किलो चावल। वहीं, मिलर्स का कहना है कि यहां धान की क्वालिटी ऐसी नहीं है कि उससे इतना चावल निकाला जा सके। इसे लेकर मिलर्स ने सरकार से प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग की है। सरकार ने इसे 25 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। इसके बावजूद मामला अटका हुआ है। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह, कृषि मंत्री कमल पटेल, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और आयुष राज्यमंत्री राम किशोर कांवरे की मंत्रिमंडलीय उपसमिति भी बनाई है। फिर भी कोई हल नहीं निकला। वर्ष 2020-21 में कुल 37.26 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। जबकि वर्ष 2017-18 में यह मात्रा केवल 16.60 मीट्रिक टन थी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई कहते हैं कि धान की खरीदी बढ़ने के साथ उसकी मिलिंग में भी दिक्कत आई। अभी प्रदेश में कुल 804 मिलर्स हैं। वर्तमान में मिलिंग की अधिकतम क्षमता 35 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन है। बची हुई धान की मिलिंग के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। टेंडर पर भी अभी फैसला नहीं हुआ है। रेट बढ़ाने व अन्य मामलों को मंत्रिमंडल की अनुमति के लिए भेजा है।

चंबल में अब भी डकैत

चंबल में अभी डकैतों की सक्रियता कम नहीं हुई है। चंबल के किनारे छुपकर मप्र-राजस्थान में सक्रिय डकैत गुड्डा गुर्जर के बाएं हाथ बॉलिस्टर गुर्जर को पुलिस ने पकड़ा है। उसके खिलाफ मुरैना, शिवपुरी और श्योपुर में 13 मामले दर्ज हैं। उस पर 20 हजार रुपए का इनाम भी था। एक जमाने में चंबल में माधौसिंह, मोहर सिंह, मलखान सिंह व पानसिंह तोमर जैसे डकैत हुआ करते थे। गुड्डा गुर्जर और केशव गुर्जर दो गिरोह अब भी सक्रिय हैं। इनकी तलाश उप्र पुलिस को भी है।

मुरैना के एएसपी रायसिंह नरवरिया ने बताया कि 11 जून की शाम 7 बजे पुलिस को मुखिबर से सूचना मिली कि आरोपी बामौर के ग्राम चक पहाड़ी के जंगल में किसी से मिलने आने वाला है। फिलहाल, गांव के एकांत में बने हाईस्कूल में छुपा हुआ है। सूचना पाते ही एसपी ललित शाक्यवार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसिंह नरवरिया एवं एसडीओपी बामौर को कार्रवाई के लिए कहा। पुलिस की टीम शाम 7 बजने से पहले ही चक पहाड़ी गांव पहुंची। गाड़ियों को घटनास्थल से काफी दूर ही खड़ा कर पैदल बामौर गांव पहुंची और शासकीय हाईस्कूल को घेर लिया। वहां मुखबिर के बताए हुलिया पर एक व्यक्ति हाथ में बंदूक लिए बैठा था। पुलिस की आहट पाते ही उसने जंगल की तरफ भागने की कोशिश की। जिस पर पुलिस ने घेरा डालकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम बालट्टर उर्फ बॉलिस्टर गुर्जर, पिता- ओछे सिंह गुर्जर, निवासी ग्राम दुधारी बताया। बॉलिस्टर गुड्डा गैंग का सक्रिय इनामी डकैत है।

बॉलिस्टर गुर्जर के पास से पुलिस ने एक 315 बोर की बंदूक और तीन जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके खिलाफ मुरैना, शिवपुरी व श्योपुर में 13 मामले हत्या व लूट के दर्ज हैं। बॉलिस्टर गुर्जर को पकड़ने के लिए मुरैना, जौरा, सुमावली, निरार और पहाड़गढ़ की पुलिस तलाश कर रही थी। उसे श्योपुर की चिलवानी थाने की पुलिस भी डकैती के मामले में तलाश रही थी। बॉलिस्टर गुर्जर ने पुलिस को बताया कि उसके बड़े भाई दशरथ गुर्जर पर भी श्योपुर व मुरैना में इनाम घोषित है। वह भी गुड्डा गैंग का सदस्य है।

केशव गुर्जर पिछले 10 वर्षों से फरार है। इसके खिलाफ मुरैना व राजस्थान में हत्या, डकैती, अपहरण व लूट के लगभग 20 मामले रजिस्टर्ड हैं। इसके ऊपर राजस्थान पुलिस ने दो लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। मप्र पुलिस ने 25 हजार रुपए इनाम घोषित कर रखा है। इसकी गैंग में 8 से 10 लोग शामिल हैं। यह सभी लोग एक जगह पर बहुत कम मिलते हैं। यह अलग-अलग रहकर भी अपराध करते हैं। जब बड़ा अपराध करते हैं तो एक साथ करते हैं तथा छोटे गैंग से लोगों को शामिल कर लेते हैं। यह गैंग चंबल नदी के आसपास के जंगलों, जैसे पहाड़गढ़, धौलपुर व मुरैना के बीच के जंगल में अधिक मूवमेंट करती है। पुलिस ने बताया कि इनके अभी तक न पकड़े जाने के पीछे मुख्य कारण इनके परिचित लोगों के गांव हैं, जो इनकी शरणस्थली बने हुए हैं। गांव के लोग ही इन डकैतों को राशन, सामान व अन्य सुविधाएं मुहैया कराते हैं। यहां तक कि इन्हें असलहा भी मुहैया कराया जाता है।

बामौर थाना के प्रभारी संतोष यादव ने बताया कि मेरे साथ गुड्डा गुर्जर गिरोह की मुठभेड़ एक माह पहले हुई थी। वह बहुत चालाक है। उसकी मुखबिरी नहीं लग पाती है। मुठभेड़ में हमारी गोली उसके पैर में लगी थी लेकिन वह भाग निकला। उसकी तलाश में हम बराबर, दबिश दे रहे हैं। मुरैना के एसपी ललित शाक्यवार ने कहा कि मुझे ज्वाइन किए मात्र 10 दिन बीते हैं। इतने कम दिनों में हमने एक बड़े डकैत को पकड़ने में सफलता हासिल की है। हमें थोड़ा समय चाहिए, जल्द ही केशव व गुड्डा गैंग का सफाया हमारी पुलिस कर देगी।

● लोकेंद्र शर्मा

पांच साल से पुलिस की पकड़ से दूर गुड्डा गुर्जर

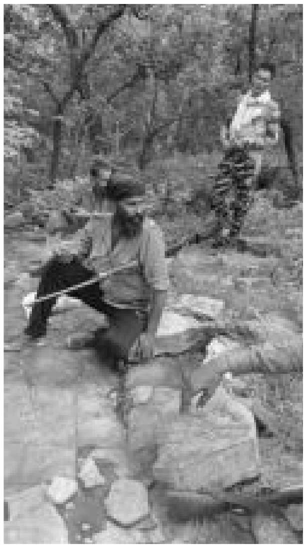

चंबल का दूसरा सबसे बड़ा डकैत गिरोह गुड्डा गुर्जर का है। इस गैंग का मुखिया गुड्डा गुर्जर है। इस पर मप्र पुलिस ने 60 हजार रुपए इनाम रखा है। इस पर भी हत्या, अपहरण, डकैती व लूट सहित लगभग 15 मामले दर्ज हैं। इस गैंग का मूवमेंट राजस्थान के धौलपुर, मुरैना व श्योपुर में अधिक रहता है। गुड्डा और केशव दोनों ही क्षेत्र चंबल से जुड़े हैं। इनका गैंग चंबल नदी के किनारे बने गांवों में अधिक रहता है। एक महीने पहले गुड्डा गुर्जर गैंग से बामौर थाना पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। यह मुठभेड़ मुरैना के जौरा क्षेत्र के अंर्तगत करैरा बांध पर हुई थी। मुठभेड़ में पुलिस की टीम का नेतृत्व बामौर थाना टीआई संतोष यादव कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी एक गोली गुड्डा गुर्जर के बाएं पैर में ऊपर की तरफ लगी थी। गोली लगने से वह घायल हो गया था। उसके साथ सामान ढोने वाले लोग भी चल रहे थे। पुलिस पीछा कर रही थी, उसी वक्त कुछ ग्रामीण उधर से निकले, जिससे पुलिस को फायरिंग रोकनी पड़ी थी। इसी बात फायदा उठाकर व रात का समय होने के कारण वह भाग गया।

अपने अक्खड़पन के कारण सत्ता गंवा चुके कमलनाथ अब एकला चलो की नीति पर काम कर रहे हैं। उनकी यह नीति पार्टी के अन्य कद्दावर नेताओं को तनिक भी नहीं भा रही है। इसका असर यह हो रहा है कि पार्टी में विद्रोह की आग सुलगने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ पार्टी में ही एक वर्ग आवाज उठाने लगा है। उधर, कमलनाथ किसी की सुनने को तैयार नहीं हैं और अपने मन की कर रहे हैं।

नाथ की एकला चलो नीति...!

करीब 5 साल पहले तक केंद्र की राजनीति में कद्दावर नेता रहे कमलनाथ ने जबसे मप्र कांग्रेस की कमान संभाली है, तबसे पार्टी में उनका ही राज चल रहा है। आलम यह है कि 15 साल बाद मिली सत्ता 15 माह में छिन जाने के बाद भी कमलनाथ ने अपनी राजनीति में कोई बदलाव नहीं किया है। वे अपनी एकला चलो की नीति पर काम कर रहे हैं। उनकी इस नीति के कारण प्रदेश में कांग्रेस के अन्य जितने भी कद्दावर नेता हैं, वे हाशिए पर चले गए हैं। यही नहीं कद्दावर नेताओं के क्षेत्र में कमलनाथ की सक्रियता भी बढ़ रही है। इससे उनके खिलाफ पार्टी में माहौल निर्मित हो रहा है।

दरअसल, अपने करीबी नेताओं पर विश्वास करके सत्ता गंवा चुके कमलनाथ अब राजनीति में हर कदम फूंक-फूंककर रख रहे हैं। जिस तरह दूध का जला मट्ठा भी फूंक-फूंककर पीता है, उसी तरह कमलनाथ काम कर रहे हैं। उनकी कार्यप्रणाली से यह साफ है कि अब उनको किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए वे अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रदेश की सियासत में सक्रियता दिखा चुके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अब जिलों पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत जिलों में प्रभारी नियुक्त करने के साथ हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी के संगठन वाले 56 जिलों में प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है, इनमें ज्यादातर वे चेहरे हैं जो कमलनाथ के करीबी हैं। सबसे अहम प्रदेश का विंध्य इलाका है, जहां अजय सिंह को दरकिनार करते हुए कमलनाथ ने अपने करीबियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी है।

रीवा जिले की कमान भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को दी गई है। अजय सिंह के प्रभाव वाले जिले सीधी में सईद अहमद को प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भोपाल में लखन घनघोरिया, जबलपुर में हिना कावरे, इंदौर में रवि जोशी, सागर में पीसी शर्मा, ग्वालियर में अवनीश भार्गव, विदिशा में सुनील सूद, रायसेन में देवेंद्र पटेल, हरदा में निलय डागा, खरगोन में गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, उज्जैन में बाला बच्चन, सिंगरौली में आनंद अहिरवार, सीधी में सईद अहमद, झाबुआ में हमीद काजी, खंडवा में मनोहर बैरागी, मंदसौर में बटुक शंकर जोशी, रतलाम में प्रियव्रत सिंह, गुना में जयवर्धन सिंह और राजगढ़ में राजकुमार पटेल को प्रभारी बनाया गया है।

गहलोत और पायलट की जंग में मध्यस्थता करेंगे कमलनाथ

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही जंग को समाप्त कराने की जिम्मेदारी मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को दी गई है। सूत्र बताते हैं कि आलाकमान ने कमलनाथ को फ्री हैंड दे दिया है कि वे राजस्थान के दोनों कद्दावर नेताओं के बीच मध्यस्थता कर मामले का पटाक्षेप करें। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं में कमलनाथ की अच्छी पैठ है। आलाकमान को विश्वास है कि नाथ की बात कोई नहीं टालेगा। इसलिए कमलनाथ को सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जंग में मध्यस्थ की भूमिका दी गई है। कमलनाथ दोनों नेताओं के लगातार संपर्क में हैं। सूत्रों का कहना है कि आलाकमान से मिले निर्देश के बाद से ही कमलनाथ राजस्थान के दोनों कद्दावर नेताओं के संपर्क में हैं।

पीसीसी की तरफ से जिलों में नियुक्त गए प्रभारियों के जिम्मे प्रदेश कांग्रेस दफ्तर और जिला इकाइयों के बीच समन्वय बनाने का होगा। पीसीसी की तरफ से जारी होने वाले दिशा-निर्देशों का जिला स्तर पर पालन कराने गतिविधियों को संचालित करने और संगठन को मजबूत बनाने पर होगा। जिला प्रभारी जिलों में होने वाली गतिविधियों और पार्टी नेताओं के कामकाज की रिपोर्ट पीसीसी को सौंपेंगे।

बहरहाल, जिलों का दौरा करने के बाद अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए कमलनाथ ने जिला प्रभारियों की नियुक्ति की है। 2018 के चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कमलनाथ गुट, दिग्विजय सिंह गुट और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के नाम से पहचानी जाती थी, लेकिन सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद अब प्रदेश में कमलनाथ ने पार्टी की पकड़ मजबूत कर ली है। जिलों में ये नियुक्तियां 2023 तक के लिए हुई हैं। मतलब साफ है स्थानीय स्तर पर मुद्दों के साथ उम्मीदवार तय करने तक में जिला प्रभारियों की अहम भूमिका होगी। कांग्रेस के 56 जिलों में प्रभारी नियुक्त करने को लेकर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस ने जिला प्रभारियों को नियुक्त कर बड़े नेताओं की निगरानी शुरू कर दी है। क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित नेतृत्व की उपेक्षा कांग्रेस पार्टी में हो रही है। जिला प्रभारियों की नियुक्ति से कांग्रेस की अंतर्कलह आने वाले दिनों में चरम पर दिखाई देगी।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब संगठन को कसने में जुट गए हैं। इस महीने से संगठन में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो सकता है। मांडवी चौहान के निधन से खाली हुए महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर जल्द ही

नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में कमलनाथ की प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से भी चर्चा हो चुकी है। कमलनाथ चाहते हैं कि मैदान में महिला कांग्रेस की सक्रियता ज्यादा नजर आए क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। महंगाई के मुद्दे पर महिलाओं से संवाद कर उनको कांग्रेस के पाले में लाया जा सकता है। कमलनाथ किसी युवा चेहरे को महिला कांग्रेस की कमान दे सकते हैं। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जिनका नाम चल रहा है उनमें नूरी खान, रश्मि पवार, कविता पांडे, यास्मीन शेरानी, अंजू जायसवाल, प्रतिभा रघुवंशी और विभा बिंदु डामोर के नाम शामिल हैं।

भाजपा नेताओं को क्या कहा जाए। कमलनाथ की जुबान से देश के लिए चंद अपमानजनक शब्द क्या निकल गए, भाजपाइयों ने आसमान सर पर उठा लिया। हद तो तब हो गई, जब खुद शिवराज सिंह ने गुस्से में उन्हें 'मानसिक बीमार' बता दिया। न भाई न! यह कमलनाथ के साथ ज्यादती है। क्या उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ बोला है जिस पर भाजपाई इतना बवाल कर रहे हैं? अब तो मान लेना चाहिए कि कमलनाथ इतने मासूम हैं कि वह अपने शब्दों के प्रभाव का आंकलन नहीं कर पाते। उन्हें कौन समझाए कि यदि वह और उनकी पार्टी नरेंद्र मोदी और भारत को एक-दूसरे का पर्याय मान रही है तो भी भारत को 'बदनाम देश' कहने में हिचकना चाहिए।

कमलनाथ कोई छोटे-मोटे नेता नहीं हैं। वह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। प्रदेश में वह अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, यद्यपि उनकी गिनती कांग्रेस के शीर्षस्थ राष्ट्रीय नेताओं में होती है। ऐसे नेता को सोच-समझकर बोलना चाहिए, पर कमलनाथ हर महीने दो महीने में अपनी जुबान से बम फोड़ने के अभ्यस्त हैं तो इसे उनकी मासूमियत या गंदी आदत मानकर नजरअंदाज किया जा सकता है। वरिष्ठता के साथ नेता परिपक्व हो जाते हैं कि जुबान से क्या उगलना है और क्या पचा लेना है, पर कमलनाथ सचमुच मासूम ठहरे। वह इतनी बात नहीं समझ पाए कि भारत को 'बदनाम देश' कहने से आम देशवासियों को कितनी तकलीफ होगी। भाजपाई तो फिराक में रहते ही हैं सो तुरंत ले उड़े। भाजपा पहले ही आरोप लगा रही है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, कांग्रेस विदेशी शक्तियों के एजेंडे पर काम कर रही है। अधिकतर लोग इसे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप मानकर नजरअंदाज करते रहते हैं, पर जब कमलनाथ जैसा कद्दावर नेता कैमरे पर कहे कि भारत महान नहीं, बदनाम देश है तो फिर आम आदमी भाजपा के आरोप में सच्चाई सूंघने लगता है।

दिग्विजय के बयान से एक बार फिर कांग्रेस बैकफुट पर

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस सरकार आने पर धारा 370 को बहाल करने का बयान देकर कोरोना संकट एवं महंगाई से घिरी भाजपा एवं मोदी सरकार को बैठे-बैठाए बड़ा मुद्दा पकड़ा दिया है। पूरी भाजपा दिग्विजय पर हमलावर हो गई है। दरअसल, क्लब हाउस पर चैट के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मुस्लिम बहुल राज्य में एक हिंदू राजा था। दोनों ने साथ काम किया। दरअसल, कश्मीर में सरकारी सेवाओं में कश्मीरी पंडितों को आरक्षण दिया गया था, इसलिए अनुच्छेद-370 को रद्द करना और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा कम करना अत्यंत दुखद निर्णय है। हमें निश्चित रूप से इस मुद्दे पर फिर से विचार करना होगा। इसे फिर से लाएंगे। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर कांग्रेस पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस ने दिग्विजय के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। इस बीच दिग्विजय के छोटे भाई एवं कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह भी उनके बयान के विरोध में हो गए हैं। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि धारा 370 हटाना अब संभव नहीं है।

दरअसल, जब कोई कद्दावर नेता कुछ बोलता है तो उसे पार्टी लाइन मान लिया जाता है। यह बात तब और असरदार हो जाती है जब पार्टी अपने नेता के विवादास्पद बयान पर मौन हो जाए। कहावत है कि मौन स्वीकृति का संकेत होता है। जब कमलनाथ ने कहा कि भारत महान नहीं, बदनाम देश है। न्यूयॉर्क में लोग हिंदुस्तानी ड्राइवर की टैक्सी में नहीं बैठते तो यह संभावना जताई जा रही थी कि कांग्रेस इसे कमलनाथ का निजी विचार ठहराकर इससे अपना पल्ला झाड़ लेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। कमलनाथ के इस मासूम बयान का वीडियो कई दिनों से वायरल है। इसके लिए भाजपाई चरणबद्ध शैली में उन्हें 'मानसिक रोगी' से लेकर 'सोनिया गांधी का चाटुकार' तक ठहरा रहे, पर पार्टी इस पर मौन है।

जाहिर है, लोग इसका भी अपने-अपने ढंग से मतलब निकाल रहे हैं। कमलनाथ की एक और अच्छी या बुरी आदत है कि वह कदम आगे बढ़ाने के बाद आसानी से पीछे नहीं खींचते। कुछ महीने पहले 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बीच का वाकया याद करिए, जब उन्होंने सार्वजनिक सभा मंच पर भाजपा की महिला उम्मीदवार, जो दलबदल से पहले खुद उनकी सरकार में मंत्री थीं, को 'आइटम' कह दिया था। जुबान फिसलने के हादसे अन्य नेताओं से भी हो जाते हैं, पर चतुर नेता तुरंत शब्द वापस लेकर और माफी मांगकर मामला रफा-दफा कर देते हैं, पर कमलनाथ तो मासूम ठहरे। अड़ गए कि माफी नहीं मांगेंगे।

बहरहाल, चुनाव के बीच जब मामला राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ने लगा और महिला आयोग जैसे संगठन मैदान में उतरने लगे तो उन्होंने घोर मजबूरी में **बस खानापूर्ति के लिए** कुछ शब्द कहे जिन्हें माफी मांगना नहीं कहा जा सकता। शायद उनकी वरिष्ठता का लिहाज करके किसी ने मामले को आगे तूल नहीं दिया। बहरहाल, लगता नहीं कि उस वाकये से उन्होंने कोई सबक लिया। बोलने में उनकी मासूमियत इस हद तक जारी है कि उन्होंने भारत को बदनाम देश ठहरा दिया। याद नहीं पड़ता कि भारत के बारे में ऐसी निम्नस्तरीय टिप्पणी कभी पाकिस्तान या चीन ने भी की हो, पर कमलनाथ तो मासूम ठहरे। उनके दिल की बात बिना सोचे-समझे उनकी जुबान से बाहर निकल गई। इसके कई दिन बाद भी उन्हें यह अहसास नहीं हुआ कि देश का राजनीतिक और सामाजिक इतिहास उनके इस बयान के आधार पर उन्हें किस तरह याद करेगा।

● **सुनील सिंह**

ऐसे तो लेट होगा अटल प्रोग्रेस-वे

अटल प्रोग्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। जब भी सर्वे शुरू होता है किसान विरोध में उतर जाते हैं। दरअसल, कभी जमीन के बदले दोगुना जमीन देने तो कभी एनएचएआई एक्ट के माध्यम से जमीनों के अधिग्रहण की चर्चा सुनकर किसान असमंजस में हैं। अब तो गुस्साए किसानों ने सर्वे कंपनी की टीम के प्रतिनिधियों से यहां तक कह दिया कि हमारी जमीन पर फीता किस अधिकार से लगा रहे हो। पहले मुख्यमंत्री या कलेक्टर का आदेश लाओ तब पुश्तैनी जमीन पर पैर रखना। जमीन के बदले जमीन कहां और कितनी दोगे।

दरअसल, मार्च 2022 से पहले अटल प्रोग्रेस-वे का निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को मुरैना जिले के सबलगढ़ के बरौठा से पोरसा के चापक गांव तक शुरू करना है। प्रोग्रेस-वे निर्माण के लिए 72 गांव के 1300 किसानों की 489 हैक्टेयर जमीन उपयोग में ली जाना है, इसलिए राजस्व विभाग की प्राथमिकता किसानों की निजी जमीन के अधिग्रहण की है। दो दिन पहले भोपाल के कंसलटेंट एलएन मालवीय ग्रुप के सर्वेयर एलाइनमेंट चेक करने के लिए **सबलगढ़ के बरौठा गांव** पहुंचे तो उन्होंने किसानों की निजी जमीन की नाप-तौल की।

जमीन पर फीता देखकर किसानों ने आपत्ति लेते हुए कहा कि उनसे बिना पूछे जमीन की नाप-जोख क्यों की जा रही है। किसानों को बताया गया कि अटल प्रोग्रेस-वे के लिए रूट की लाइन तैयार की जा रही है। प्रोग्रेस-वे किसानों के खेतों के बीच से निकलेगा, इसलिए जमीन को नापकर देखा जा रहा है। इस पर किसानों ने कहा कि पुश्तैनी जमीन तब तक नहीं देंगे जब तक यह खुलासा नहीं हो जाएगा कि जमीन के बदले कितनी जमीन कहां मिलेगी।

श्योपुर से भिंड तक जाने वाला अटल प्रोग्रेस-वे मुरैना जिले के सबलगढ़ बार्डर के गांव बरौठा से शुरू होकर कैमाराकलां, अटार, डिगवार खेरा, चिन्नौनी, खांडौली, मसूदपुर, गोरखा, ऐसाह, जौंहा, डडौली, रिठौना, रछेड़, रुधावली व चापक होता हुआ भिंड पहुंचेगा। चंबल के बीहड़ों को समतल करने पर किसानों के लाखों रुपए खर्च, जमीन के अधिग्रहण को लेकर मुख्यमंत्री ने अब तक कोई नीति राजस्व अफसरों को नहीं भेजी। सबलगढ़ के घुर्र गोदोली के किसानों का कहना है कि वह बीहड़ में पट्टे की जमीन 20 साल से जोत रहे हैं। हाईवे उनके खेतों से निकलेगा इसके लिए जमीन के बदले जमीन देने की बात की जा रही है। लेकिन अधिकारी हमारी जमीन तो चिन्हित कर रहे हैं लेकिन सरकारी जमीन कहां देंगे, यह बताने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में बिना जाने हम अपनी जमीन कैसे व क्यों दें। खांडौली के किसान सरवन सिंह ने बीहड़ की जमीन को समतल करने पर दो लाख रुपए व्यय किए हैं। उनकी जमीन को प्रोग्रेस-वे के लिए अधिग्रहित करने की बात चल रही है। किसान का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उपचुनाव में कहा था कि जमीन के बदले किसानों को दोगुना जमीन दी जाएगी। यदि दूनी समतल जमीन मिलेगी तो ही इस जमीन को सड़क बनाने के लिए दिया जाएगा अन्यथा नहीं। क्योंकि बदले में मिलने वाली जमीन को समतल कराने का खर्चा कौन वहन करेगा। अंबाह के किसान भीकम सिंह तोमर का कहना है कि गांव से सड़क निकलेगी, हमें क्या खास फायदा होगा इसे बताने कोई नहीं आया। राजस्व अधिकारी जमीन देने के लिए सहमति लेने के लिए चर्चा जरूर कर रहे हैं। हमारी एक हैक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो गया तो हमारे पास बचेगा क्या। हम तो कुल 2 हैक्टेयर जमीन के काश्तकार हैं। जमीन के दाम अच्छे मिलेंगे तो जमीन देने पर विचार करेंगे। नकद पैसा मिलेगा उससे पास में कोई दूसरी सिंचित जमीन खरीद लेंगे।

अटल प्रोग्रेस-वे के लिए किसानों की निजी जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई को लेकर सबलगढ़ से जौरा विधानसभा क्षेत्र के वह किसान चिंतित हैं जो बीहड़ की सरकारी जमीन पर बरसों से काबिज होकर खेती कर रहे हैं। उनकी जमीन गई तो बिना कागजातों के ऐसे किसानों को एक्सचेंज में दूसरी जमीन मिलने पर संकट खड़ा होगा। इसलिए किसान अटल प्रोग्रेस-वे के लिए जमीन देने के मुद्दे पर विरोध की मुद्रा में हैं।

● प्रवीण कुमार

आदेश के इंतजार में अफसर

309 किमी लंबाई के अटल प्रोग्रेस-वे के लिए पहला काम किसानों की 489 हैक्टेयर जमीन के अधिग्रहण का है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश हैं कि प्रोग्रेस-वे के लिए किसानों से एक्सचेंज में जमीन ली जाए। किसान जमीन देने की सहमति नहीं देते हैं तो जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाए। राजस्व व एनएचएआई के अफसरों का कहना है कि भोपाल से बीते एक साल से अटल प्रोग्रेस-वे को लेकर कोई आदेश नहीं आया। आदेश आए तो उसका पालन क्रियान्वयन शुरू कराएंगे। संयुक्त कलेक्टर संजीव जैन का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के संबंध में शासन के आदेश का इंतजार है। उसी के अनुरूप कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रबंधक (तकनीकी) संजय वर्मा का कहना है कि अटल प्रोग्रेस-वे डेवलपमेंट का काम एनएचएआई को देखना है। जमीन उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन को एजेंसी बनाया गया है। प्रोग्रेस-वे का एलाइनमेंट तैयार करने व डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का जिम्मा भोपाल की कंसलटेंसी एलएन मालवीय को दिया है। कंसलटेंसी के लोग सर्वे के काम में लगे हैं। जल्द ही डीपीआर तैयार हो जाएगी। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ही प्रोग्रेस-वे की प्रक्रिया शुरू होगी।

इनामी नक्सलियों को सौंपी जाएगी मप्र की कमान...

पिछले एक दशक से नक्सली संगठन मप्र में अपनी पैठ बनाने के लिए तरह-तरह के प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यहां की पुलिस की सतर्कता के कारण नक्सली पैर नहीं जमा पा रहे हैं। ऐसे में अब नक्सली संगठनों ने मप्र में पैर जमाने के लिए देश के चुनिंदा इनामी नक्सलियों को मप्र की कमान सौंपने की तैयारी कर ली है।

भाकपा माओवादी संगठन मप्र में अपनी सक्रियता बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। प्रदेश में सालों की कोशिश के बाद भी नक्सलवाद पैठ नहीं बना पाया है। इसलिए नक्सली संगठन ने पुलिस और सीआरपीएफ की तर्ज पर प्रमोशन और ट्रांसफर की नीति को अपनाया है। इसके तहत इनामी नक्सलियों को प्रमोशन देकर मप्र में तैनात किया जाएगा। ताकि वे संगठन का विस्तार कर सकें।

गौरतलब है कि इस समय 7 राज्यों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भाकपा माओवादी संगठन काफी मजबूत स्थिति में है। लेकिन मप्र में संगठन को ताकत नहीं मिल पाई है। प्रदेश के बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, मंडला, डिंडौरी, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया जिले में नक्सली सक्रिय हैं। अब भाकपा माओवादी संगठन की कोशिश है कि इन जिलों के साथ ही अन्य जिलों में नक्सलवाद को मजबूत किया जाए। इसके लिए अन्य राज्यों के इनामी नक्सलियों का मप्र में ट्रांसफर किया जाएगा।

मप्र में संगठन को मजबूत करने के लिए भाकपा माओवादी संगठन ने बिहार के गया जिले के अपने दुर्दांत नक्सली संदीप यादव को प्रमोशन देते हुए उसका ट्रांसफर छत्तीसगढ़ कर दिया है। वह छत्तीसगढ़ में रहकर मप्र में नक्सली गतिविधियों पर नजर रखेगा। इसका खुलासा तब हुआ जब इस कुख्यात नक्सली ने अपने ट्रांसफर को लेकर नाराजगी जताई। वहीं, पुलिस ने भी संदीप यादव के प्रमोशन और छत्तीसगढ़ ट्रांसफर की सूचना मिलने की पुष्टि की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, संदीप ने छत्तीसगढ़ जाने से इंकार कर दिया है। उसका कहना है कि बिहार में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, जिसे पूरा करने के बाद ही आगे की सोची जाएगी। संदीप यादव मूल रूप से गया के बांके बाजार थाना क्षेत्र के लुटुआ गांव का रहने वाला है।

सूत्रों के मुताबिक, संदीप का संगठन के प्रति समर्पण देखते हुए प्रमोशन के साथ ट्रांसफर दिया है। वह बीते 15 वर्षों से बिहार व झारखंड में सक्रिय है। वह स्पेशल एरिया कोर कमेटी के सदस्य के साथ ही बिहार व झारखंड के मध्य जोन का मुख्य प्रभारी भी है। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पिछले कई सालों से इसे पकड़ने के लिए पसीना बहा रही है, लेकिन अब तक दबोच नहीं पाई है।

इस कुख्यात पर झारखंड सरकार की ओर से 30 लाख और बिहार सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। बिहार से लेकर झारखंड तक सीआरपीएफ व जिला पुलिस विशेष टीम वर्षों से इसके पीछे लगी है। वह अब तक किसी के हत्थे नहीं चढ़ सका है। वहीं, भाकपा माओवादी के शीर्ष सदस्य संदीप के इस फैसले से पसोपेश में पड़ गए हैं। वह अब आगे की रणनीति को धरातल पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि संदीप को प्रमोशन देते हुए पोलित ब्यूरो का सदस्य बनाकर उसे छत्तीसगढ़ भेजे जाने का फरमान जारी हुआ है। हालांकि, संगठन के सदस्य इस मसले पर कुछ भी कहने से फिलहाल परहेज कर रहे हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि संगठन का निर्णय सर्वोपरि है न कि कोई आदमी विशेष। संगठन का यह भी कहना है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति संदीप के सामने है, जिसकी वजह से वह इस तरह का फैसला लेने को विवश है। इस मसले पर भी संगठन के शीर्ष नेता अपने स्तर से छानबीन कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों ने कई नए कैंप खोले हैं। ऐसे में नक्सली महाराष्ट्र, मप्र और छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए अमरकंटक के जंगलों में नया बेस कैंप बनाना चाहते हैं। सीपीआई माओइस्ट ने अपनी 21 मेंबर्स की सेंट्रल कमेटी फिर से बना ली है, जो उनके पोलित ब्यूरो के बाद सबसे अहम है। ये सब संकेत है कि नक्सली खुद को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सबसे अधिक फोकस मप्र के 8 जिलों बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, मंडला, डिंडौरी, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया पर है।

● राकेश ग्रोवर

आर्थिक मजबूती के लिए गांजे की तस्करी

पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार नक्सली अपनी आर्थिक मजबूती के लिए गांजा और अफीम की तस्करी कर रहे हैं। इसके लिए मप्र को बेस बनाया गया है। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सली गांजे और अफीम की खेती कर रहे हैं। नक्सली क्षेत्रों से आने वाले गांजे की भारी भरकम खेपों को सागर लाया जाता है। पुलिस की नजर से बचने शहर के आसपास बाहरी बस्तियों में रखा जाता है। यहां से गांजे को दिल्ली, उप्र, राजस्थान के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों के साथ महाराष्ट्र तक पहुंचाया जाता है। गांजे के तस्कर नशे की खेप को सागर तक पहुंचाने लग्जरी कारों का उपयोग कर रहे हैं। इनके आगे-पीछे भी फॉलो वाहन दौड़ते हैं, जो पुलिस की सक्रियता की सूचनाएं देते हैं। माल शहरी क्षेत्र से बाहर बनाए गए गोदामों में उतार लिया जाता है। यहां गांजे की बड़ी खेप को अलग-अलग हिस्सों में दो-तीन स्थानों पर रखा जाता है, ताकि मुखबिरी की स्थिति में ज्यादा नुकसान न हो।

माफिया के निशाने पर अफसर

26 जिलों में ठेकेदारों ने रोकी मई की रॉयल्टी

मप्र के ज्यादातर रेत के ठेकेदारों ने खदान चलाने में असमर्थता जाहिर कर दी है। 37 में से 26 जिलों के ठेकेदारों ने मई की रॉयल्टी रोकने के साथ ही खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह से मिलकर एक साल पुरानी मांग पूरी करने का दबाव बनाया है। इसमें लॉकडाउन के दौरान वास्तविक रेत खनन के आधार पर रॉयल्टी लेने की बात के साथ किश्त में छूट देने को भी कहा है। इन 26 जिलों के ठेकेदारों पर मई की रॉयल्टी 68 करोड़ से अधिक बकाया है। सर्वाधिक 22 करोड़ रुपए होशंगाबाद के रेत ठेकेदार आरके ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन पर बाकी हैं। विभाग का कहना है कि ठेकेदार मांगों पर अड़े रहे तो ठेका निरस्त करने की नौबत आएगी। यह स्थिति बनी तो रेत के दाम बढ़ जाएंगे। इधर, मई की रॉयल्टी रोके जाने के बारे में बताया गया है कि कांट्रेक्टर ठेके की अवधि को 30 जून 2023 तक बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही जून 2020 तक की अवधि को शून्य वर्ष घोषित करवाकर पहले साल की गणना एक जुलाई 2020 से करने की बात कर रहे हैं। खनिज मंत्री ने कहा कि इस मामले की चर्चा के लिए मंत्री समूह है। रेत से राज्य सरकार को हर माह सवा सौ करोड़ रुपए रॉयल्टी के मिलते हैं। मई में ही 125 से 130 करोड़ मिलने थे, जिसमें से आधे से भी कम पैसा मिला है।

दतिया जिले के सेंवढ़ा अनुभाग में अवैध रेत उत्खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां आए दिन घटनाएं हो रही हैं। कभी हमला, तो कभी हमले की धमकी। डरे सहमे अफसर भी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। बावजूद जिम्मेदार प्रशासनिक अमले द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती। बता दें कि गत दिनों पहले ही खनिज ठेकेदार की फ्लाइंग स्कॉट गाड़ी पर हमला हुआ, जिसमें दो आरक्षकों को गोली लग गई। इसके पहले सेंवढ़ा रेंजर सीएस श्रोत्रीय द्वारा भी अवैध उत्खनन के मामले में अपना इस्तीफा देने की पेशकश की गई थी। खास बात यह है कि प्रशासन द्वारा इस दिशा में कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई। आने वाले दिनों में यह अवैध उत्खनन बड़ी घटनाओं की वजह बन सकता है। साथ ही मशीनों से हो रहे उस उत्खनन से सिंध नदी को बड़ा नुकसान हो रहा है।

सेंवढ़ा के कंदरपुरा घाट से खनिज ठेकेदार द्वारा बीते 4 माह से अवैध उत्खनन करवाया जा रहा था। इसी मामले को लेकर एक घटना हुई, जिसमें फ्लाइंग स्कॉट की गाड़ी पर हमला किया गया। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस द्वारा किसी को नामजद आरोपी नहीं बनाया है। पर लोगों में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। वहीं घटना के बावजूद प्रशासनिक चुप्पी भी सवालों को खड़ा कर रही है। भीषण गर्मी में सूखती सिंध के अंदर से रेत उठाती मशीनें अब भविष्य के लिए संकट की आहट बन चुकी हैं। विरोध को नजरअंदाज कर प्रशासन के अधिकारी मौन साधे हुए हैं। माफिया की आड़ में राजनीतिक रसूख वाले लोग भी सक्रिय हो रहे हैं। यही हालात रहे तो आने वाले समय में जल संकट के साथ-साथ जलीय जीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है।

सेंवढ़ा अनुभाग की सीमा से सिंध नदी निकली है। कुल 30 किलोमीटर का हिस्सा नदी से जुड़ा है। यही वजह है कि बारिश के वक्त नदी की धाराओं से आकर रेत तटीय इलाकों में खनिज का भंडार बन जाती है। पिछले साल बारिश अपेक्षा कृत कम हुई और जगह-जगह बने बांधों ने भी नदी का जलस्तर कम कर दिया। ऐसे में गर्मी आते ही नदी सूखने लगी। गर्मी के कारण इन दिनों में पानी का सिकुड़ता भाग रेत के ढेर में बदल गया है। यही रेत अब मााफिया के लिए सोना बन गई है। सेवढ़ा क्षेत्र में नदी के तल से रेत उठाने का यह कारोबार इन दिनों चरम पर है। प्रतिदिन लाखों रुपए की रेत उठाई जा रही है। खास बात यह है कि वैध खदानों की आड़ में दर्जनों अवैध खदानों का संचालन हो रहा है। माफिया रात होते ही मशीनों से उत्खनन कर रेत भरकर बेच रहे हैं। पूरे धंधे में खनिज विभाग के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है।

जिले के खनिज ठेकेदार द्वारा नियम के विरुद्ध रुहेरा खदान से ऐसे सर्वे नंबरों से उत्खनन किया गया जो कि स्वीकृत नहीं थे। वहीं बाहर से आई बड़ी-बड़ी मशीनों और पनडुब्बियों द्वारा नदी के अंदर 20 से 25 फीट गहराई तक जाकर रेत उठाई गई। नदी के तल से रेत उठाकर बाहर उसको डंप किया गया। मंगरोल चौकी के पास ही रेत के विशाल टीले बना दिए गए हैं। यहां से डंप की गई रेट लगातार बेची जा रही है। खास बात यह है कि लगभग 10 किलोमीटर के हिस्से में दिन-रात उत्खनन जारी है पर ना अधिकारियों ने इसकी सुध ली और न जनप्रतिनिधियों ने छलनी होती सिंध को लेकर कोई परवाह की। अवैध रेत उत्खनन से पुरातात्विक धार्मिक ऐतिहासिक स्थल को भी नुकसान पहुंचा रहा है।

बरसात में जमा रेत पानी को सोखने का कार्य करती है। और यही वजह है कि नदी से सटे इलाकों में रेत के यह ढेर पानी के स्रोत हो जाते हैं। गर्मी में रेत से रिसने वाला पानी न सिर्फ नदी को सूखने से बचाता है, वहीं समीपस्थ क्षेत्र के जलस्तर को भी मेंटेन करता है। इसीलिए शासन द्वारा जब भी खदानें दी जाती हैं, तो उनमें मशीन से उत्खनन को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाता है। क्योंकि मशीन अधिक गहराई तक उत्खनन कर रेत को समाप्त कर सकती है। खदानों की लीज देते वक्त केवल मजदूर से उत्खनन कराने तथा नदी से 500 मीटर की दूरी से उत्खनन के निर्देश रहते हैं, पर वर्तमान में जैसे ही सिंध सूखी तो लोगों ने अपने फायदे के लिए नदी के तल से ही रेत उठाना शुरू कर दिया। ऐसे में जो रेत पानी का स्रोत बनकर जल संकट से बचाती है, उसके स्थान पर कई तटीय इलाकों में मिट्टी, कंकड़, पत्थर ही बचे हैं। इस खनिज में पानी के स्रोत नहीं होते, वहीं आने वाले दो माह जब तक बारिश नहीं होगी, इससे क्षेत्र में सूखे की संभावना बढ़ सकती है। जलस्तर गिरने का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा।

● नवीन रघुवंशी

नक्सलियों के हाथ में सेना के हथियार

संस्कारधानी जबलपुर में स्थित सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो में चोरी हुए एके-47 नक्सलियों के हाथ में पहुंच गए हैं। इसका खुलासा हाल ही में एनआईए ने अपनी चार्जशीट में किया है। एनआईए के खुलासे के बाद एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में आ गया है।

देश का हृदय प्रदेश होने के कारण मप्र अपराधियों की राजधानी बनता जा रहा है। अपराधी, नक्सली, तस्कर, माफिया आदि मप्र को केंद्र बनाकर देशभर में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इन सबके बीच चौंकाने वाली खबर यह है कि मप्र के जबलपुर सेंट्रल ओर्डिनेंस डिपो से 70 रिजेक्टेड राइफल्स चोरी मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें खुलासा किया गया है कि स्टोर से 70 रिजेक्टेड एके-47 रायफल पार्ट्स के रूप में चोरी करके असेम्बल किए गए थे। एके-47 को बिहार के मुंगेर में बेचा गया था, जहां से ये नक्सलियों तक पहुंचाया गया है। एनआईए ने चार्जशीट में जबलपुर सीओडी के एक्स आर्मोरर को किंगपिन बताया। चार्जशीट में एके-47 रायफल मुंगेर होकर बिहार-झारखंड के बदमाशों और सक्रिय नक्सलियों को बेचे जाने की बात कही है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) ने 2 जून को पटना स्थित स्पेशल जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में 22 एके-47 रायफल की बरामदगी मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

जबलपुर सेंट्रल ओर्डिनेंस डिपो के स्टोर से 70 के लगभग रिजेक्टेड एके-47 रायफल पार्ट्स के रूप में चोरी किए गए। स्टोर कीपर अधारताल निवासी सुरेश ठाकुर इसे डिपो के पूर्व आर्मोरर गोरखपुर पंचशील नगर निवासी पुरुषोत्तम लाल रजक को देता था। पुरुषोत्तम लाल रजक उसे असेम्बल कर अलग-अलग तारीखों में बिहार के मुंगेर में तस्करों तक पहुंचाता था। पुरुषोत्तम मूलत: रीवा का रहने वाला है और 2008 में सीओडी से रिटायर हुआ था।

बिहार में मुंगेर जिले के जमालपुर थाने की पुलिस ने 29 जुलाई 2018 को जुबली बेल इलाके में मुफस्सिल थाना अंतर्गत मिर्जापुर बरदह गांव निवासी मोहम्मद इमरान आलम और शमशेर को दबोचा था। दोनों के पास से 5 एके-47 राइफल, 30 मैगजीन, एके-47 राइफल की 7 पिस्टन, 7 स्प्रिंग, 7 बॉडी कावर, 7 रीकॉइल स्प्रिंग, 7 ब्रिज ब्लॉक और अन्य पुर्जे जब्त हुए थे। यह हथियार उसे स्टेशन पर पुरुषोत्तम लाल रजक और उसकी पत्नी चंद्रवती ने दिया था। उनकी टिकट का बंदोबस्त बेटा शैलेंद्र करता था।

मुंगेर में हुई गिरफ्तारी के आधार पर जबलपुर की गोरखपुर और क्राइम ब्रांच पुलिस ने पुरुषोत्तम, पत्नी चंद्रवती, बेटा शैलेंद्र और अधारताल निवासी सुरेश ठाकुर को दबोचा था। गोरखपुर में अपराध क्रमांक 588/18 दर्ज है। पुरुषोत्तम से बड़ी मात्रा में एके-47 के पार्ट्स जब्त हुए थे। बाद में इस मामले में मुंगेर के 9 आरोपी और बनाए गए थे। 20 दिसंबर 2018 को 173 (8) में पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश कर दिया। अभी 9 आरोपी जबलपुर नहीं लाए जा सके। वहीं दो एफआईआर बिहार के जमालपुर में 29 जुलाई 2018 और मुफस्सिल थाना में 7 सितंबर 2018 को दर्ज हुआ था। इसमें 26 आरोपी बने हैं। बाद में 5 अक्टूबर 2018 को एनआईए ने इस मामले को टेकओवर कर लिया था। बिहार की मुंगेर पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाकर इस मामले की जांच आगे बढ़ाई। कुल 22 लोगों की गिरफ्तारी बिहार व झारखंड से हुई। 4 आरोपी जबलपुर से ले जाए गए। आरोपियों ने घर के आंगन स्थित कुंए, नाले में और घर में उक्त हथियार छुपा रखे थे। शेष हथियारों को बिहार-झारखंड के बदमाशों, कोल माफिया और नक्सलियों को बेच दिए गए थे।

एनआईए ने दो साल की जांच के बाद अब चार्जशीट दाखिल की है। 2 जून को एनआईए ने पटना के विशेष कोर्ट में 14वें आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 (बी), 380, 414, आर्म्स एक्ट 25 (ए), 25 (1 ए), 25 (1 ए ए), 25 (1 ए ए ए), 26 और यूएपी की धारा 39 के तहत चार्जशीट दाखिल की। इस पूरक चालान में आरोपी गया जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के तेतर गांव का मुखिया रह चुका राजीव कुमार सिंह उर्फ चुन्नू सिंह है। राजीव को 7 दिसंबर 2020 में गिरफ्तार किया था।

● **बृजेश साहू**

2002 में एसएलआर से शुरू हुई थी तस्करी

एनआईए की जांच में बताया गया कि आरोपी लांस नायक नियाजुल रहमान की 2002 में लखनऊ में पुरुषोत्तम से मुलाकात हुई थी। उसी दौरान तस्कर शमशेर व इमरान से भी परिचय कराया था। बाद में उसका तबादला सीओडी जबलपुर हो गया। 2002 में उसने पहली बार एसएलआर निकाला। उसने 15 एलएलआर जमालपुर स्टेशन तक पहुंचाए थे। वर्ष 2012 में उसने पहली बार एके-47 रायफल शमशेर और इरफान को पहुंचाया था। जबलपुर स्थित सीओडी से वर्ष 2002 से 2018 के दौरान एके-47 सहित अन्य हथियारों को पार्ट्स के तौर पर निकाला गया और उसे असेम्बल कर बेचा गया। जबलपुर के सेंट्रल ओर्डिनेंस डिपो सीओडी से 70 के लगभग एके-47 और 13 अन्य असलहों को पार्ट्स के रूप में चुराया गया। चोरी के बाद असेम्बल कर अधिकतर एके-47 हथियारों को मुंगेर के तस्करों के माध्यम से नक्सलियों और बदमाशों को 5 से 8 लाख रुपए में बेचे गए। इस मामले में सीओडी के वर्तमान और कुछ पूर्व अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। 29 जुलाई 2018 को मुंगेर में इमरान और शमशेर राणा की गिरफ्तारी के बाद 5 एके-47 की जब्ती से मामले का भंडाफोड़ हुआ था। बिहार और झारखंड के नक्सलियों के अलावा कोल माफिया को सेना की एके-47 राइफल बेची गई है।

अव्यवस्था का जंगलराज

पर्यावरण बनाने और बचाने के लिए सिस्टम कितना गंभीर है, उसकी छोटी सी झलक इस खबर में नजर आ सकती है। वन विभाग का दावा है कि मप्र में वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक 1638 करोड़ रुपए में 20 करोड़ 92 लाख 99 हजार 843 पौधे लगाए गए। यानी एक पौधा लगाने और उसके रखरखाव पर करीब 78 रुपए खर्च हुए। छह साल में से ज्यादातर का बड़ा हो जाना भी तय है, लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) की ताजा रिपोर्ट कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं 6 साल में प्रदेश में 100 वर्ग किमी से अधिक का वन क्षेत्र कम हुआ है।

इतना ही नहीं, मप्र में एक जनवरी 2015 से 5 फरवरी 2019 तक 12 हजार 785 हैक्टेयर वन भूमि दूसरे कामों के लिए दे दी गई। दो महीने पहले वन विभाग की बैठक में एफएसआई की रिपोर्ट का जिक्र भी हुआ है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2005 के मुकाबले 2019 में ग्रीन कवर 1469 वर्ग किमी बढ़ा है।

बहरहाल, अब फिर बारिश से पहले वन विभाग के अलावा उद्यानिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पौधे लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वर्ष 2021-22 में 4 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। कोरोना की वजह से अप्रैल और मई में अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं हुआ है, लिहाजा जून में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। बता दें कि प्रदेश में अभी कुल क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत फॉरेस्ट कवर है।

विभागीय सूत्रों की मानें तो सागौन के एक पौधे को नर्सरी में तैयार करने से लेकर प्लांटेशन तक 18 से 20 रुपए खर्च होते हैं। हर साल उसके रखरखाव पर डेढ़ से दो रुपए का खर्च होता है। एक हैक्टेयर पर प्लांटेशन है तो दो हजार रुपए खर्च आता है। जबकि विभाग प्रति पौधे 78 रुपए खर्च बता रहा है यानी तीन से चार गुना ज्यादा। पूर्व प्रधान वन संरक्षक आरएन सक्सेना कहते हैं कि वनाधिकार के तहत जो पट्टे बांटे जा रहे हैं, वह पेड़ घटने की बड़ी वजह हैं। लोग इसी आधार पर अतिक्रमण कर रहे हैं। जहां तक ग्रीन कवर की बात है तो जो पौधे लगते हैं, वह 6-7 साल में सैटेलाइट से दिखाई देते हैं। नमामि देवी नर्मदे अभियान के दौरान सवा सात करोड़ पौधे लगाने का विवादित मसला अब ठंडे बस्ते में है। ये पौधे वन विभाग के साथ उद्यानिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि समेत कई विभागों ने मिलकर लगाए थे। वन विभाग के सूत्रों का कहना है कि इस दौरान वन विभाग ने 3 करोड़ 32 लाख पौधे लगाए थे। 2019 में तत्कालीन वन मंत्री उमंग सिंघार ने कहा था कि इसकी जांच ईओडब्ल्यू को सौंपेंगे। आज तक जांच शुरू नहीं हो पाई। विभाग ने पौधों का परीक्षण कराया तो दावा किया कि 67 फीसदी पौधे जीवित हैं।

एक तरफ सरकार वन और पौधों के संरक्षण की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ छतरपुर के बकस्वाहा में हीरे के लिए हरे पेड़ काटे जाने की योजना है। इस जमीन के भीतर 3.42 करोड़ कैरेट हीरे हैं, जिन्हें निकालने के लिए 382.131 हैक्टेयर में 46 प्रजाति के 2,15,875 पेड़ काटे जाएंगे। इसके अलावा लाखों छोटे पेड़, झाड़ियां, घास के मैदान तबाह होंगे। इन्हें बचाने के लिए सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हुआ है लेकिन बेअसर साबित हो रहा है। मप्र सरकार ने यह जमीन 50 साल के लिए आदित्य बिड़ला समूह की एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी को लीज पर दे दी है। कंपनी अगले कुछ महीने में यहां काम शुरू कर सकती है। कंपनी ने पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन किया है। अब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिए भेजा है।

बकस्वाहा का जंगल पन्ना टाइगर रिजर्व और नौरादेही अभयारण्य के बीच में है। यह जंगल दोनों संरक्षित वन क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। यह जंगल तेंदुआ, बाज (वल्चर), भालू, बारहसिंगा, हिरण, नील गाय, मोरों का स्थाई आवास है। हीरे की खोज में सबसे पहले इस जंगल में पहुंची रियोटिंटो कंपनी की टीम को जंगल में बंदरों के कई झुंड मिले थे। इसी कारण इजीनियरों ने हीरा खनन परियोजना का नाम बंदर प्रोजेक्ट रख दिया। हॉन्गकॉन्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉ. एलेक्जेंडर कोख कहते हैं कि अब धरती के हर कोने पर पेड़ लगा दें, तो भी ग्लोबल वॉर्मिंग के दुष्प्रभाव रोकना मुश्किल है। सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन सोखते हैं। लेकिन पौधरोपण अकेला उपाय नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है खान-पान में बदलाव करना। मीट, डेयरी और ऐसे अनाज, जिन्हें उगाने और प्रोसेस करने में बहुत पानी लगता है, उनका इस्तेमाल हम सबको कम करना होगा।

लाइफस्टाइल के कारण तापमान बढ़ा है और उपाय भी हमारे बदलाव में ही है। दुनिया विकास को जीडीपी में नापती है। जीडीपी के विकास का मतलब है ज्यादा डिमांड और खपत। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए खपत कम करना जरूरी है। यहीं विरोधाभास है और यही असफलता का कारण है। टिकाऊ विकास के मॉडल की तलाश जारी है। बकस्वाहा के जंगल में आंखों के सुकून देने वाली हरियाली, झरने कब तक रहेंगे कहा नहीं जा सकता। क्योंकि 3.42 करोड़ कैरेट हीरे निकालने के लिए 382.131 हैक्टेयर का जंगल तबाह करने की तैयारी सरकार कर रही है। वहीं यदि जंगल को काटा जाता है तो औषधि देने वाले आंवला के 3311 और अमलतास के 2035 पेड़ नष्ट हो जाएंगे।

● **धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया**

2013 से 2017 तक घटे वन

फॉरेस्ट कवर को लेकर हर दो साल में रिपोर्ट जारी होती है। इसके हिसाब से वर्ष 2013 में फॉरेस्ट कवर 77 हजार 552 वर्ग किमी था, जो 2015 में घटकर 77 हजार 462 वर्ग किमी और 2017 में 77 हजार 414 वर्ग किमी हो गया। यह 2019 में थोड़ा बढ़कर 77 हजार 482 वर्ग किमी हुआ, लेकिन 2013 के फॉरेस्ट कवर के मुकाबले कम है। वन विभाग को उम्मीद है कि 2021 की रिपोर्ट में यह बढ़ जाएगा। 2005 में फॉरेस्ट कवर 76 हजार 13 वर्ग किमी रहा, जो 2019 में 77 हजार 482 वर्ग बताया।

> मौजूदा महामारी से पहले भी भारत में महिला संरपचों ने विशेष तौर पर आम आदमी को चिकित्सीय सेवाएं मुहैया कराने में मदद की और उन पर देखभाल करने का जो भरोसा कायम हुआ उस भरोसे का आज अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए।

गांवों को बचाना एक बड़ी चुनौती

अस्पताल जाने पर परिवार के बर्बाद होने का खौफ

कोरोना की पहली लहर में संक्रमण से बच गए गांव कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ गए थे। गांवों में लगातार बढ़ते कोरोना के केस ने स्थिति भयावह कर दी थी। हर साल गर्मियों में सूखे और पानी के संकट को झेलने वाले बुंदेलखंड इलाके में इस बार चुनौतियां डबल हो गई है। एक ओर पानी का संकट तो दूसरी ओर कोरोना का खौफ नजर आ रहा है। बांदा जिले के महुआ ब्लॉक में 100 से ज्यादा गांव आते हैं, लेकिन गांव के अधिकतर लोग जांच कराने से बच रहे हैं। ये कहना हैं महुआ ब्लॉक की आशा कार्यकर्ता मनोरमा बाजपेयी का। महुआ ब्लॉक में 100 से ज्यादा गांव आते हैं, लेकिन गांव के अधिकतर लोग जांच कराने से बच रहे हैं। हमें ऐसे लोगों की खबर भी मिलती हैं जो कई दिनों से सर्दी-खांसी, बुखार से बीमार हैं, लेकिन जब हम घर-घर सर्वे करते हैं, लोगों से लक्षण पूछते हैं, तो लोग सही जानकारी देने से बचते हैं। गांव के लोग सोचते हैं कि यदि वे कोराना पॉजिटिव निकले तो अस्पताल में रहना पड़ेगा और घर बर्बाद हो जाएगा। उनके घर को संभालने वाला कोई नहीं रहेगा।

बेशक कई राज्यों में कोविड महामारी की दूसरी लहर में गिरावट की प्रवृत्ति कई दिनों से जारी है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कई विज्ञानियों ने कुछ ही माह के बाद तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई है। यहां पर एक अहम बिंदु यह है कि यह ग्राफ भले ही फिलहाल नीचे जा रहा है, मगर देश के गांवों को मौजूदा महामारी व भविष्य के स्वास्थ्य संकटों से बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। खासकर बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र के गांवों की। बुंदेलखंड क्षेत्र में मप्र के 6 और उप्र के 7 जिले आते हैं। यहां के गांव पहले से ही गरीबी, अव्यवस्था, भूख, सूखा आदि से बेहाल हैं। ऐसे में कोरोना महामारी से इस क्षेत्र को बचाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। वैसे देखा जाए तो देशभर के गांवों में स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे अधिक चिंताजनक है। देश के करीब 6 लाख गांवों में लगभग 65 फीसदी आबादी बसती है। ऐसे में गांववासियों के स्वास्थ्य, कोविड की रोकथाम के लिए किए जा रहे चिकित्सीय प्रयासों की जानकारी उन तक पहुंचाते रहना व कोविड-रोधी टीकाकरण बाबत जारी दुष्प्रचार को रोकना और उन्हें हकीकत बताना आदि कार्य अल्पकालिक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक एंजेडा होना चाहिए।

यह एक कड़वी सच्चाई है कि ग्रामीण आबादी में साक्षरता दर बढ़ने के बावजूद आधुनिक चिकित्सा के प्रति भरोसा उस अनुपात में नहीं बढ़ा है। ऐसे में सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में राज्य सरकारों, केंद्र शासित राज्यों व स्थानीय ईकाइयों के द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम के लिए जमीनी स्तर पर जारी गतिविधियों के बारे में बताया और इस पर भी जोर दिया कि गांववासियों के साथ इस बाबत बराबर संवाद, संचार अभियान जारी रखने की जरूरत है। आदिवासी व कृषि केंद्रित पॉकेट पर विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा। गांवों में जागरूकता अभियान को गहन करना होगा। जागरूकता अभियान की रणनीति में सूचना, शिक्षा व संचार भी शमिल है।

केंद्र व राज्य सरकारें गांवों में स्थानीय भाषा में कोविड महामारी संबंधित सामग्री बांट रही हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस महामारी की गंभीरता को समझें। अपना बचाव करें और उन्हें मालूम हो कि संक्रमित होने पर क्या-क्या करना है। इसके साथ ही टीका भी लगवाएं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत सरकार का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है, उसके रास्ते में आज भी कई बाधाएं हैं जिनमें कई तरह की अफवाहें भी अपनी जगह बनाए हुए हैं।

हां, यह जरूर है कि सरकार ने कई बाधाओं पर सफलता हासिल कर बाल टीकाकरण की दर में सुधार कर लाखों बच्चों को असमय मरने से बचाया है। इसके लिए बराबर जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय शासन व प्रभावशाली हस्तियों की मदद ली जाती है। गांवों में पंचायत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम होती है। इन सब को गांववासियों की जीवनरेखा भी कहा जाता है। कोविड महामारी के दौर में ये सब बहुत बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। मौजूदा महामारी से पहले भी भारत में महिला संरपचों ने विशेष तौर पर आम आदमी को चिकित्सीय सेवाएं मुहैया कराने में मदद की और उन पर देखभाल करने का जो भरोसा कायम हुआ, उस भरोसे का आज अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि गांवों में कोविड संक्रमण से निपटने के लिए लोग हर तरह से तैयार हो जाएं। वैसे इस दिशा में कई गांवों ने मिसाल भी कायम की है, जहां गांव के लोगों ने अपने गांव में बाहर के लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया। यह काबिले तारीफ है।

भारत ने पोलियो उन्मूलन में सफलता हासिल कर विश्व में प्रशंसा हासिल की और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, वे कुछ हद तक आश्वस्त करती हैं कि कोविड रोधी टीके लगवाने की राह में जो अफवाहें खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में रुकावटें खड़ी कर रही हैं, वे अधिक लंबे वक्त तक जिंदा नहीं रहेंगी। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि ऐसी रूकावटों को रास्ते से हटाने के लिए सरकारी मशीनरी व स्वैच्छिक संस्थाएं अपनी गतिविधियों में कितनी निरंतरता बनाए रखती हैं। यह निरंतरता भी महामारी से लड़ने का एक औजार ही है व भविष्य के लिए निवेश भी।

● **सिद्धार्थ पांडे**

कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए जद्दोजहद करते लोगों और श्मशानों में लंबी कतारें चर्चा का विषय बनी रहीं। वहीं कोविड की दूसरी लहर अर्थव्यवस्था को लगातार कमजोर करती गई। आज स्थिति यह हो गई है कि सरकार के पास कोई ठोस नीति नजर नहीं आ रही है, जिससे डूबती अर्थव्यवस्था को उबारा जा सके। उधर, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से उद्योग-धंधे रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे हैं। यानी देश के सामने बड़ी चुनौती है।

• राजेंद्र आगाल

भारत 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को निर्णायक तौर पर पछाड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना था। वहीं 2026 में जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथी तथा 2034 में जापान को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद पाले हुए था। लेकिन कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को इस कदर धरातल पर ला दिया है कि अब इसे उबारने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत आन पड़ी है। कोरोना संक्रमण ने जहां देश में बेरोजगारी बढ़ाई है, वहीं महंगाई, गरीबी, भुखमरी ने देश को दशकों पीछे ला दिया है। कोविड की दूसरी घातक लहर ने पहले से लहूलुहान अर्थव्यवस्था की चूलें हिला दीं, उपभोक्ताओं का भरोसा, उद्योग-धंधों और रोजी-रोजगार की बहाली के लिए अब असाधारण नजरिए और कदमों की दरकार है। पूरे देश की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों पर टिकी हुई है।

देश अभी कोविड की पहली लहर से उबरना शुरू हुआ ही था कि दूसरी लहर ने जिस अप्रत्याशित प्रचंडता से हमला बोला, उसने पिछले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में देश में हुई थोड़ी-बहुत आर्थिक बहाली को भी पटरी से उतारने का खतरा पैदा कर दिया है। हालांकि इस बार देशव्यापी लॉकडाउन से बचा गया, लेकिन राज्य लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हुए। लिहाजा, देश को मई के हर हफ्ते करीब 8 अरब डॉलर या 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत चुकानी पड़ी। फैक्ट्रियों में बंदी और छटनी ने बेरोजगारी दर को दहाई अंकों में धकेल दिया। 23 मई को खत्म सप्ताह में यह 14.73 फीसदी पर पहुंच गई। लॉकडाउन की पाबंदियों के साथ नौकरियों के जाने और तनख्वाह में कटौतियों के चलते कई चीजों के साथ टीवी, रेफ्रिजरेटर, परिधान और फूटवियर सरीखे टिकाऊ उपभोक्ता सामान की बिक्री थम गई।

लेना पड़ रहा है उधार

कोविड महामारी की दूसरी लहर और इसके चलते लगाए गए लॉकडाउन ने पारिवारिक आमदनी को गहरी चोट पहुंचाई है। परिवारों ने उधार ले-लेकर अपना काम चलाया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े परिवारों द्वारा सोना गिरवी रखकर उधार लेने के मामलों में बड़ी वृद्धि बताते हैं। औपचारिक सेक्टर के अलावा अनौपचारिक सेक्टर से भी उधार लिए ही गए होंगे लेकिन उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कर्ज के बारे में रिजर्व बैंक के आंकड़े पर्सनल लोन में भारी वृद्धि दर्शाते हैं। अप्रैल में पर्सनल लोन में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें दहाई अंकों वाली वृद्धि वाहन के कारण लिए गए कर्ज में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि, क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए गए कर्ज में 17 प्रतिशत की और सोने के जेवरों को गिरवी रखकर लिए गए कर्ज में 86 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि के चलते हुई।

मार्च तक बैंकों ने जेवरों के ऊपर जो कर्ज दिया उसमें 82 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह 60,464 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसके अगले महीने अप्रैल में यह आंकड़ा 62,238 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे एक साल पहले इस तरह 33,303 करोड़ रुपए के कर्ज दिए गए थे। भारतीय परिवारों के बैलेंसशीट में भौतिक संपत्तियों की प्रमुखता है, जिनमें सोने का हिस्सा सबसे ज्यादा है।

बेलगाम महंगाई सरकार के लिए खतरे की घंटी

थोक कीमतों पर आधारित महंगाई दर का रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुंच जाना सरकार के लिए खतरे की घंटी बनना चाहिए, इसलिए भी कि थोक के साथ खुदरा महंगाई दर भी सिर उठाए हुए है। सरकार को महंगाई पर लगाम लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, अन्यथा आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दाम उसके लिए आर्थिक के साथ-साथ राजनीतिक रूप से भी चुनौती बन सकते हैं। सरकार के नीति-नियंता इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि महंगाई के बेलगाम होने से एक ओर जहां विरोधी दल सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने में मुश्किलें भी खड़ी होती दिख रही हैं। महंगाई बढ़ने का कारण है पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि और आवश्यक वस्तुओं की मांग एवं आपूर्ति में अंतर, जो लॉकडाउन के चलते बढ़ा है, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आम आदमी पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़े मूल्यों के साथ खाद्य तेल के बढ़ते दामों से भी परेशान है। निसंदेह इसके आसार हैं कि लॉकडाउन में रियायत और राहत से मांग एवं आपूर्ति में अंतर कम होगा, लेकिन सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भी कुछ करना होगा।

कर्ज में डूबे लोग

महामारी के कारण आए आर्थिक संकट ने ज्यादा से ज्यादा परिवारों को कर्ज में डुबो दिया है। अभी केवल पहली लहर के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि परिवारों का कर्ज जुलाई-सितंबर 2020-21 की तिमाही में जीडीपी के 37.1 प्रतिशत के बराबर था, जबकि इसी वित्तीय वर्ष की इससे पिछली तिमाही में यह 35.4 के बराबर था। दूसरी लहर में परिवारों से संबंधित ये आंकड़े कुछ तिमाही बाद उपलब्ध होंगे। परिवार के कर्ज का अनुमान बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए उसकी देनदारियों का जीडीपी में जो अनुपात है उससे लगाया जाता है। मासिक उधार के आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में कर्ज में बड़ी वृद्धि दिख सकती है। पर्सनल लोन के आंकड़े बताते हैं कि दूसरी लहर के दौरान परिवार कंज्यूमर ड्यूरेबल पर उस तरह खर्च नहीं कर रहे हैं जिस तरह पहली लहर के दौरान कर रहे थे। उदाहरण के लिए, अप्रैल में कंज्यूमर ड्यूरेबल के कारण लिए जाने वाले पर्सनल लोन में 18 प्रतिशत की कमी आई। चालू आंकड़े पिछले साल इसी अवधि (अप्रैल 2020) के, जब कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए कर्ज में करीब 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, इन आंकड़ों से बिलकुल उलट हैं। यह बताता है कि परिवारों ने आय में कमी के बीच जबरन कर्ज लिया। कई परिवारों ने जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए सोना गिरवी रखकर कर्ज लिया। यह महामारी से पहली की स्थिति से उलट है, जब कर्ज अपने रहन-सहन को सुधारने के लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदने के वास्ते लिया जाता था।

एमएसएमई भी दबाव में

व्यक्तियों और परिवारों के अलावा लघु उद्योग सेक्टर द्वारा लिए जाने वाले कर्ज में भी वृद्धि हो गई। लॉकडाउन के कारण मांग में कमी आई, फिर

भी हम पाते हैं कि लघु एवं मझोले उद्योगों के कर्ज में बढ़ोतरी हुई। कुल नॉन-फूड बैंक क्रेडिट में तो मामूली 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मझोले उद्योग को कर्ज में 43.8 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसमें 6.4 प्रतिशत की कमी आई थी। मझोले उद्योगों को कर्ज में सितंबर 2020 के बाद से दहाई अंकों में वृद्धि हुई है। इसकी बड़ी वजह यह हो सकती है कि महामारी के दौरान सरकार ने लघु उद्योगों को ही सहायता दी।

महामारी के कारण पड़े दबाव को दूर करने के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) की घोषणा की। इसका मकसद कार्यशील पूंजी उपलब्ध करना, संचालन संबंधी देनदारी पूरी करने और महामारी से प्रभावित कारोबार को शुरू करने में मदद करना है। इस स्कीम में एमएसएमई को पूरी तरह गारंटीशुदा कर्ज दिया जाता है। स्कीम का लक्ष्य बैंकों को प्रोत्साहन देना था कि वे महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित एमएसएमई के कर्जदारों को फंड दे सकें। फरवरी के अंत तक, बैंकों द्वारा एमएसएमई के 87 लाख कर्जदारों को 2.46 लाख करोड़ रुपए कर्ज दिया जा चुका था। सरकार ने हाल में ईसीएलजीएस स्कीम के तहत उधार लेने की शर्तों को आसान किया। रिजर्व बैंक ने एमएसएमई के लिए लोन के ढांचे में बदलाव के अलावा जो दूसरे उपाय किए हैं उनसे एमएसएमई को कर्ज में और वृद्धि हो सकती है।

50 खरब डॉलर का लक्ष्य चकनाचूर

अब जबकि कोविड की दूसरी लहर खत्म होने लगी है और लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, परिवारों और छोटी कंपनियों को ज्यादा कमाई करने और अपना बैलेंस शीट सुधारने का मौका मिलेगा। धीरे-धीरे, सावधानी के साथ छूट देना और लोगों का टीकाकरण करना ही उपाय है। परिवारों और फर्मों के बजट इस तरह सिकुड़ गए हैं कि अब वे और लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकतीं। उनकी भलाई लोगों के टीकाकरण की गति पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था के 50 खरब डॉलर के लक्ष्य पर पहुंचने की उम्मीदें तो खैर पक्के तौर पर चकनाचूर हो चुकी हैं, खासकर महामारी से पहले भी यह उम्मीद से कम 5 फीसदी की वृद्धि दर पर लड़खड़ा रही थी। मोदी सरकार ने पिछले साल गरीब और लाचार लोगों के लिए गारंटीशुदा कर्ज और सामाजिक योजनाओं में 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा झोंके, पर कई सारे सुधार अब भी अधर में अटके हैं।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए) के मुताबिक, कारों की बिक्री में मार्च के मुकाबले अप्रैल में 25 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई, जबकि दोपहिया वाहनों की बिक्री 27 फीसदी से ज्यादा गिरी। 2020 के सख्त लॉकडाउन से लहूलुहान ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र अब भी खस्ताहाल

महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ने से थोक महंगाई दर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के मुताबिक थोक महंगाई दर मई में 12.94 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह मई 2020 में -3.37 प्रतिशत रही थी। मंत्रालय ने सोमवार को मई में थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। होल सेल प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई दर लगातार 5वें महीने मई में चढ़ी है। इससे पहले अप्रैल में भी दर 10.49 प्रतिशत पर रही थी। सरकार की ओर से जारी थोक महंगाई में कहा गया कि क्रूड पेट्रोलियम, मिनिरल ऑयल्स के चलते महंगाई बढ़ी है।

महामारी ही नहीं, अर्थव्यवस्था को भी उबारेगी वैक्सीन

कोविड-19 की वैक्सीन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और गरीबी को तेजी से कम करने में एक महत्वपूर्ण उत्पाद बनकर उभरी है। इस लिहाज से यह एक ऐसा शक्तिशाली उत्पाद बन चुकी है, जिस पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीन, विकासशील देशों में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विषनाशक औषधि के तौर पर उभरी है। 90 फीसदी से ज्यादा देशों में कोरोना महामारी के चलते आर्थिक मंदी दर्ज की गई। आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन तक पहुंच और इसका वितरण किसी भी देश के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जरूरी शर्त बन चुकी है। कोरोना के बाद की वैश्विक परिस्थितियों में वैक्सीन को वही दर्जा हासिल हो चुका है, जो किसी मंदी या बड़ी आर्थिक दुर्घटना के बाद पूंजी को हासिल होता है। 'द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस 2021' का अनुमान है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था 'अप्रत्याशित तौर पर मजबूत' रिकवरी की ओर बढ़ रही है। 2021 में दुनिया की अर्थव्यवस्था 5.6 फीसदी की दर से वृद्धि करेगी, जो पिछले 80 सालों में मंदी के बाद सबसे मजबूत वृद्धि होगी। हालांकि इस अप्रत्याशित खबर के लक्षण संभावित ही हैं, यानी यह वृद्धि चंद विकसित देशों में ही दर्ज की जाएगी। भारत समेत दुनिया के अन्य विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को 2019 के स्तर पर लाने में कई साल लग जाएंगे। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, 'विकसित अर्थव्यवस्था वाले 90 फीसदी देशों के 2022 तक महामारी से पहले वाले प्रति व्यक्ति आय का स्तर पा लेने की उम्मीद है, जबकि उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले केवल एक तिहाई देशों के ऐसा करने के आसार हैं।' विश्व बैंक का विश्लेषण यह दर्शाता है कि जिन देशों में वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही है। विकसित देशों में महामारी ढलान पर है और वैक्सीनेशन की गति काफी तेज है। जबकि दूसरी ओर विकासशील देशों में कोरोना का भयावह दौर जारी है और उनके भविष्य में नई लहरों से प्रभावित होने की आशंका भी बरकरार है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अर्थशास्त्री इलियाट हैरिस के मुताबिक, 'देशों और क्षेत्रों के बीच वैक्सीन की असमानता पहले से असमान और नाजुक वैश्विक रिकवरी के लिए खतरनाक संकेत है।' उदाहरण के लिए अफ्रीका महाद्वीप में वैक्सीन की कवरेज दुनिया में सबसे कम है और वैक्सीन का डोज उपलब्ध न होने के चलते वहां वैक्सीनेशन रोकने की नौबत आ सकती है। दुनिया में जहां औसतन 11 फीसदी लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं, जबकि अफ्रीका के लिए यह संख्या केवल दो फीसदी है।

है। कई फर्मों ने देश की वृद्धि के 11-12 फीसदी के अनुमानों को घटाकर 8 फीसदी या उससे भी कम कर दिया है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग कहते हैं, 'वृद्धि में 3 फीसदी कमी का भी मतलब है अर्थव्यवस्था के लिए 6-6.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। पिछले साल हम 20 लाख करोड़ रुपए से हाथ धो बैठे थे।'

97 फीसदी की आमदनी घटी

रिसर्च फर्म सीएमआइई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी) के मुताबिक, फरवरी और अप्रैल के बीच 90 लाख वैतनिक नौकरियां चली गईं। 97 फीसदी परिवारों की आमदनियों में गिरावट आई। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने वाला मूल तबका मध्यम वर्ग भी बुरी तरह टूट चुका है। अमेरिका स्थित प्यू रिसर्च सेंटर की मार्च की शोध रिपोर्ट से पता चला कि पिछले साल कोविड ने करीब 3.2 करोड़ भारतीयों को मध्यम वर्ग के दायरे से नीचे धकेल दिया, जो रोजाना 10 डॉलर (724 रुपए) से 20 डॉलर (1,449 रुपए) कमाते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यम वर्ग एक-तिहाई तक सिकुड़ गया है। महामारी से पहले 9.9 करोड़ से अब 6.6 करोड़ पर आ गया है। ग्रामीण इलाकों में हालात और बदतर हैं। पहली लहर में तो ग्रामीण वृद्धि और रोजगार ने अर्थव्यवस्था की गिरावट को संभाल लिया था। मगर इस बार ग्रामीण इलाकों में बढ़ते संक्रमण और पाबंदियों की वजह से ग्रामीण भारत में बेरोजगारी दर 13.5 फीसदी पर पहुंच गई है, जबकि शहरी इलाकों में यह 17.4 फीसदी है। सीएमआईई के सीईओ और एमडी महेश व्यास कहते हैं, श्रम भागीदारी की दर 2016 से ही लगातार गिरती रही है।

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम कर रहे करोड़ों लोग अब मुश्किल में हैं, जो पहले अपने गांव और कस्बे छोड़कर शहर आ जाते थे और कम हुनर वाले काम-धंधों में, नाई की दुकान, ढाबे या किराने की दुकान सरीखे कामकाज में खपा लिए जाते थे। देश में मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ कहा जाने वाला एमएसएमई क्षेत्र सबसे नाजुक हालत में है। देश में 6.34 करोड़ एमएसएमई हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में 45 फीसदी और निर्यात में 40 फीसदी का योगदान और करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन के जून 2020 के एक सर्वे से पता चला कि देश के 35 फीसदी एमएसएमई और स्वरोजगार में लगे 37 फीसदी लोगों को महामारी की वजह से कारोबार बंद करने पड़े। इस बार नुकसान केवल आर्थिक नहीं है, कई उद्यमियों को कोविड की वजह से जान गंवानी पड़ी। एफआईएसएमई (फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) के सेक्रेटरी जनरल अनिल भारद्वाज कहते हैं, इस बार नुकसान दीर्घकालिक है।

मध्यम वर्ग में हुए 40 प्रतिशत गरीब

कोरोना संक्रमण में लगे लॉकडाउन के चलते अमीरों को छोड़कर देश के हर वर्ग का बुरा हाल है। मध्यम वर्ग पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। जनवरी और मई 2021 के बीच 2.5 करोड़ से अधिक मौजूदा नौकरियां खत्म हो गई हैं। इनमें रोजगार का सबसे बड़ा नुकसान (करीब 2.2 करोड़ नौकरियां) अप्रैल और मई में चली गईं। यह उस अवधि में हुआ जब भारत कोविड-19 की क्रूर और घातक दूसरी लहर से घिरा हुआ था जिसके कारण राज्यों में भिन्न-भिन्न डिग्री के राज्य-स्तरीय लॉकडाउन लगाए गए थे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा किए गए आवधिक सर्वेक्षणों के नवीनतम परिणामों से ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ऐसे समय में नौकरी छूटना कोई अनपेक्षित बात नहीं है क्योंकि लॉकडाउन का सीधा असर आबादी के उस बड़े हिस्से की कमाई के अवसरों पर पड़ता है जो अनौपचारिक क्षेत्र में दैनिक रोजगार और उससे होने वाली कमाई पर निर्भर होते हैं। हालांकि, महामारी के इस दौर में सरकार की पूर्ण उपेक्षा ने संकट को और गहरा कर दिया है, जैसा कि उसने पिछले साल किया था। जनवरी 2021 में रोजगार करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या (सीएमआईई के नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से) लगभग 40.1 करोड़ अनुमानित थी। फरवरी और मार्च में थोड़ा कम होकर यह संख्या 39.8 करोड़ हो गई थी। फिर अप्रैल माह में यह संख्या और गिर गई, खासतौर पर मई में इस गिरावट का खासा असर देखने को मिला। सीएमआईई के अनुमानों के अनुसार, निर्माण क्षेत्र जो ज्यादातर बड़े पैमाने पर अनौपचारिक श्रम को रोजगार और कम वेतन देता है, उसमें भी इन दो महीनों में करीब 88 लाख से अधिक श्रमिक रोजगार से बाहर हो गए।

मनरेगा से उम्मीद

पहली लहर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकटमोचन बनकर उभरी थी, जब अच्छी कृषि उपज और कुछ हद तक खपत ने संभाल लिया था। कामगार अपनी जेबों में बचत लिए शहरों से अपने गांवों में लौट गए थे और सरकार कमजोरों की मदद के लिए धन झोंक रही थी। कई ने लौटकर खेती-किसानी संभाल ली और दूसरों ने सरकार की ग्रामीण बेरोजगार गारंटी योजना मनरेगा में रोजगार पकड़ लिया। दूसरी लहर में देश के देहात में कोविड-19 के प्रकोप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तगड़ा धक्का लगा। राज्य सरकारों को नकदी की तंगी है और लोग अपनी बचत खर्च कर चुके हैं। कृषि में उपजों के दाम घट रहे हैं जबकि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। बहुत रोजगार देने वाला निजी निर्माण क्षेत्र ठहरा पड़ा है। मोदी सरकार ने 2020 में कुछ खास तबकों, प्रवासी कामगारों, रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, छोटे उद्योग-धंधों के लिए कई योजनाएं घोषित की थीं। मसलन, गरीब कल्याण रोजगार अभियान का लक्ष्य गांव लौट रहे मजदूरों को बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित 25 अलग-अलग किस्म के कामों में 125 दिन का रोजगार

प्रदेश में राजस्व बढ़ाने गठित होगा मंत्री समूह

मप्र में राजस्व बढ़ाने के तरीकों पर विचार-विमर्श के लिए मंत्री समूह का गठन किया जाएगा। यह मंत्री समूह जून के अंत तक अपनी रिपोर्ट देगा। पिछले ढाई महीने से प्रदेश का राजस्व बहुत कम आया है। अब कोरोना नियंत्रित है। ऐसे में सरकार की आय बढ़ाने के उपायों के साथ आत्मनिर्भर मप्र के रोडमैप पर भी चर्चा होगी। यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि सरकार रोजगार पर फोकस करेगी। बैठक में इसके लिए कई सुझाव आए। इसके बाद तय किया गया कि प्रदेश के रोजगार कार्यालय तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन काम कर रहे हैं। अब जिलों के रोजगार अधिकारियों की वर्कशॉप कर ट्रेनिंग दी जाएगी। स्वसहायता समूहों को रोजगार को तकनीकी तौर पर ट्रेंड किया जाएगा। उन्हें प्लंबर, फिटर जैसे छोटे-छोटे कामों की ट्रेनिंग दी जाएगी। बड़े उद्योगों के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे। कोरोना संक्रमण नियंत्रित होने बाद अब सरकार का पूरा ध्यान रोजगार और अर्थव्यवस्था को गति देने पर है। इसके लिए एक साथ कई कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश में प्रतिमाह एक लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसमें सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर दिलाने की कोशिश होगी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वैकल्पिक आय के स्त्रोत चिन्हित किए जाएंगे। इसके लिए मंत्री समूह का गठन किया जाएगा। एक से तीन जुलाई तक टीकाकरण के लिए महाअभियान चलाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। आय के अन्य स्त्रोत और वैकल्पिक व्यवस्था कर कमी पूरी की जाएगी। राजस्व संग्रहण विभागों में बेहतर वसूली सुनिश्चित की जाएगी। आय के अन्य स्त्रोतों को चिन्हित करने और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर सुझाव देने के लिए मंत्री समूह गठित किया जाएगा, जो जून अंत तक रिपोर्ट देगा।

मुहैया करना था। योजना में उप्र, मप्र, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा सरीखे राज्यों के 116 जिलों में लौटे 25,000 प्रवासी कामगारों को शामिल करना था।

प्रधानमंत्री रेहड़ी-पटरी आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) योजना का लक्ष्य रेहड़ी-पटरी वालों को सस्ती ब्याज दर पर 10,000 रुपए तक के कर्ज मुहैया कराना था। इसी तरह, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का लक्ष्य मैन्युफैक्चरिंग फर्मों को प्रोत्साहन देना था। पीएम-स्वनिधि में 27.3 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को कर्ज मिले। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, कंपनियों ने पीएलआई के तहत 1,300 करोड़ रुपए का निवेश किया और अपने कामकाज के पहले पांच महीनों में करीब 22,000 नौकरियों का सृजन किया। विशेषज्ञों का कहना है कि इन योजनाओं ने कुल मिलाकर भुखमरी के हालात पैदा नहीं होने दिए। मगर भारत जितने विशाल देश में इन समाधानों को ज्यादा दूरगामी और प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है।

हर माह एक लाख को रोजगार

मप्र सरकार ने भी अपनी अर्थव्यवस्था का मजबूत करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए गत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ सीहोर के पास रिजार्ट में अनौपचारिक बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण नियंत्रित होने बाद अब सरकार का पूरा ध्यान रोजगार और अर्थव्यवस्था को गति देने पर है। इसके लिए एक साथ कई कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश में प्रतिमाह एक लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसमें सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर दिलाने की कोशिश होगी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वैकल्पिक आय के स्त्रोत चिन्हित किए जाएंगे। इसके लिए मंत्री समूह का गठन किया जाएगा। एक से तीन जुलाई तक टीकाकरण के लिए महाअभियान चलाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर करीब 6 घंटे मंथन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा- नौकरियों के लिए सभी क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशी जाएं। ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं, जो युवाओं को रोजगार दिला सकें। पशुपालन, डेयरी विकास, लोहारी, उद्यानिकी के साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाएं। कोरोना संकट के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। दो माह में राजस्व काफी कम आया है, लेकिन गतिविधियों को बंद नहीं किया जा सकता है। जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते रहना है। इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि गरीब, किसान, माताओं, बहनों और बच्चों के कल्याण की योजनाओं पर भी सुझाव आमंत्रित हैं। प्रदेश में विकास गतिविधियां और जन-कल्याण के कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे। इनके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करना होगी। आय के अन्य स्त्रोतों और वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में विचार करना होगा। गरीबों के कल्याण और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने पर विचार करना होगा।

बड़े निवेश की संभावना

कोरोना संकट के बीच मप्र के लिए अच्छी खबर यह है कि चार औद्योगिक संस्थान यहां जल्द ही ढाई हजार करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने जा रहे हैं। सीमेंट, गारमेंट और स्टील के क्षेत्र से जुड़ी चार कंपनियां यह निवेश करेंगी। सर्वाधिक दो हजार करोड़ रुपए का निवेश बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना जिले में होगा। यहां जेके सीमेंट का कारखाना लगेगा। वहीं, भोपाल के अचारपुरा में रेडिमेड गारमेंट की इकाई लगाई जाएगी। चारों कंपनियों के माध्यम से प्रदेश के 5 हजार से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। वहीं, आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जब प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू था, तब सबसे बड़ी चिंता यही थी कि आर्थिक गतिविधियों को कैसे पटरी पर लाया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अधिकारियों से संवाद भी कर रहे थे। इसी दौरान उद्योग विभाग ने 40 से ज्यादा कंपनियों से संपर्क साधा, जिसका फायदा यह हुआ कि कुछ कंपनियों के प्रस्तावों पर सहमति बन गई।

क्षमता से अधिक भरे हुए जेल

देशभर की जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी भरे हुए है। देश के 15 राज्यों की जेल अपनी क्षमता से अधिक भरी हुई हैं। सबसे भीड़ भार वाली जेलों में दिल्ली और उप्र क्रमश: 175 प्रतिशत और 168 प्रतिशत ऑक्युपेंसी दर के साथ पहले और दूसरे स्थान पर हैं। साल 2016 में कैदियों की संख्या जहां 4,33,003 थी, वही साल 2019 में ये बढ़कर 4,78,600 हो गई। जबकि इसी समयावधि में कुल जेलों की संख्या में 4.39 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। कोरोना महामारी की वजह से कोर्ट का काम बाधित हो रहा है और जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है।

राष्ट्रीय स्तर पर तीन साल के खाली पदों के आंकड़ों के हिसाब से देशभर के जेलों में 30 प्रतिशत से ज्यादा की कमी है। मानव संसाधन की इतनी कमी की वजह से जेलकर्मी जेल में निगरानी और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कैदियों को कम जगह में एकसाथ रखने को मजबूर होते हैं। हमारी संसाधनहीन और क्षमता से ज्यादा भरी जेलें कोरोना को फैलने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर रही हैं। धूम्रपान, ड्रग्स का सेवन, साफ-सफाई की कमी, सही पोषण ना मिल पाना और बीमारियों की वजह से कैदियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। आम आबादी की तुलना में कैदियों में मधुमेह, रक्तचाप, एचआईवी, यौन संचारित रोग, टीबी, हेपेटाइटिस जैसे बीमारियों का खतरा 2 से 10 गुना तक ज्यादा रहता है।

भारत में कैदियों की मृत्यु दर 2001 में 311.8 प्रति दस लाख थी जो कि 2016 में बढ़कर 382.2 हो गई। प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया, 2019 के अनुसार 2019 में देश की जेलों में विभिन्न बीमारियों से मरने वाले कैदियों की संख्या 1466 है। इनमें हृदय से जुड़े रोग (406), फेफड़ो संबंधित रोग (190), टीबी (81) और कैंसर (78) आदि प्रमुख कारण थे। वहीं आत्माहत्या जेल में होने वाले अप्राकृतिक मौतों में सबसे बड़ा कारण है। साल 2019 में 116 कैदियों की जान आत्महत्या की वजह से हुई जो की टीबी (81) और कैंसर (78) से ज्यादा है। जेलों में बंद 7000 से ज्यादा कैदी किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रसित हैं। इससे जाहिर होता है कि कैदियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर एकसाथ ध्यान देने की जरूरत है।

कोरोना की दूसरे लहर से पूरे देश में जहां अफरातफरी और इलाज के अभाव में मौत की खबरें हम सभी को चिंतित कर रही हैं। ऐसे माहौल में क्षमता से ज्यादा भरे हुए जेलों में बंद कैदियों की मानसिक स्थिति की कल्पना करना कठिन है। पिछले साल कोरोना संकट के दौरान जेलों में हिंसा और अव्यवस्था फैलने की खबरें भी आईं। पहले से अकेलापन और लंबे तनाव के दौर से गुजर रहे कैदियों में कोरोना संकट मानसिक रोगों को उत्पन्न कर सकता है। बढ़ते कोरोना खतरे को देखते हुए कई राज्यों में परिजनों से मुलाकात बंद कर दी गई है और ज्यादा भीड़-भाड़ वाली जेलों से कैदियों को दूसरी जेलों में स्थानांतरित किया गया है। ऐसे में इनका परिवार से संपर्क टूट जाने का खतरा है। देशभर की जेलों में सुविधाओं और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी है।

देश की जेलों में ऐसे कैदी बड़ी संख्या में बंद है जिनके मामले पुलिस जांच या सुनवाई का इंतजार कर रहे है। देशभर की जेलों में बंद कुल कैदियों में से 68 प्रतिशत विचाराधीन कैदी हैं। जहां जेल अपनी क्षमता से ज्यादा भरे हुए हैं, वहीं जेलों में कर्मचारियों की भारी कमी है। कई राज्यों में 40-50 प्रतिशत चिकित्सा पदाधिकारी के पद खाली हैं। जबकि मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016 के अनुसार प्रति 300 बंदी पर एक चिकित्सा पदाधिकारी होना चाहिए। देश की विभिन्न जेलों में मनोचिकित्सक और काउंसलर के पद खाली पड़े हैं।

यदि सरकार जेलों में कोरोना संक्रमण फैलने से ना रोक पाई तो इस महामारी को रोकने के प्रयास असफल हो सकते हैं। यदि ठोस प्रयास नहीं किए गए और भीड़-भाड़ वाली जेलों में संक्रमण पैर पसारने में कामयाब रहा तो चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था पर और अधिक बोझ बढ़ सकता है। यह अकेले कोर्ट और जेल व्यवस्था के बस की बात नहीं है। जेल, न्याय और स्वास्थ्य व्यवस्था समन्वय स्थापित कर काम करने की जरूरत है। जेलों में संक्रमण रोकने के लिए जोखिम प्रबंधन रणनीति बनाकर संक्रमण फैलने के संभावित कारणों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उसी आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं जैसे आइसोलेशन बेड, कोरोना टीका आदि का वितरण किया जाना चाहिए। यह मूल्यांकन दो स्तरों पर किया जाना चाहिए। पहला कैदियों और जेल कर्मियों का रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन या जोखिम स्तरीकरण। रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन कैदियों के उम्र और अन्य स्वास्थ्य समस्या जैसे मधुमेह, रक्तचाप, एचआईवी, यौन संचारित रोग, टीबी, हेपेटाइटिस, गंभीर मानसिक रोग आदि के आधार पर किया जाना चाहिए। गंभीर शारीरिक या मानसिक रोगी कोरोना संक्रमण के लिए अति संवेदनशील होते है।

● विकास दुबे

भीड़ कम करने की जरूरत

न्याय व्यवस्था और जेलों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बड़े पैमाने पर जेलों से भीड़ कम करने की जरूरत है। कैदियों की रिहाई संबंधित निर्णय में उनके स्वास्थ्य जोखिम आंकलन के आधार पर हो ना कि उनके अपराध या कानूनी स्थिति के आधार पर होनी चाहिए। कैदियों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किए जाने की जरूरत है। जेल में बंद कैदियों को स्वास्थ्य का उतना ही अधिकार है जितना किसी जेल से बाहर रह रहे इंसान को। इस महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम सभी तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े इंसान की सुरक्षा सुनिश्चित ना हो जाए। देश की न्यायपालिका को कानूनी सुनवाई करते समय गैर हिरासत उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए। देश की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की बड़ी संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'अर्नेश कुमार बनाम बिहार सरकार' के मामले में जारी आदेश को गंभीरता से लागू करने की जरूरत है। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पुलिस और मजिस्ट्रेट को सात साल या उससे कम सजा वाले अपराधों में जल्दबाजी में गिरफ्तारी से बचना चाहिए।

‘ 2014 में सत्ता जाने के बाद कांग्रेस को कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसके पास युवाओं की एक ऐसी टीम थी जो भविष्य में कांग्रेस को बड़ा आधार दे सकती थी। लेकिन सोनिया और राहुल गांधी के उपेक्षा से युवाओं की यह टीम बिखरने लगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब जितिन प्रसाद ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं सचिन पायलट सहित कई युवा उपेक्षा से बगावत की राह पर हैं। ’

नहीं दिख रहा भविष्य

भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के बीच कांग्रेस को अपना घर संभालना मुश्किल हो रहा है। एक-एक करके उसके नेता या तो सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो रहे या फिर उदासीन होकर घर बैठ गए हैं। इसी कड़ी में जितिन प्रसाद ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। इससे पहले उनके मित्र और पूर्व सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले वर्ष मार्च में भाजपा में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी थी। खास बात यह है कि दोनों पूर्ववर्ती नेता यूपीए सरकार में मंत्री रहने के साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नजदीकी भी रहे हैं। माना जा रहा है कि आगे भी कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं।

पांच राज्यों के चुनाव में शिकस्त के बाद जितिन प्रसाद का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा सियासी झटका है। इसमें दो राय नहीं कि पार्टी के सबसे संकटपूर्ण दौर में ही युवा पीढ़ी के उसके चेहरे तितर-बितर होने लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जितिन कांग्रेस के बिखरते युवा नेतृत्व का आखिरी पन्ना नहीं हैं बल्कि इस सिलसिले के आगे भी जारी रहने की संभावनाएं हैं। राजस्थान में विद्रोह के मुहाने से लौटे सचिन पायलट, महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा से लेकर हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जैसे कांग्रेस के युवा चेहरे पार्टी की मौजूदा दशा-दिशा से परेशान होकर अपने राजनीतिक भविष्य की वैकल्पिक संभावनाओं पर गौर कर रहे हैं।

कांग्रेस से राजनीतिक पारी का आगाज कर अपनी पहचान बनाने वाले इन युवा चेहरों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला स्पष्ट तौर पर इस बात का संकेत है कि चाहे ज्योतिरादित्य हों या जितिन, इन नेताओं को कांग्रेस में अपना राजनीतिक भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। इस कारण वे भाजपा को अपना अगला पड़ाव बनाने में कोई संकोच नहीं कर रहे। जितिन तो पिछले लोकसभा चुनाव के समय से ही भाजपा में जाने को तैयार थे मगर प्रियंका गांधी वाड्रा के सियासत में आने के बाद हालात बदलने की उम्मीद में दो साल ठहर गए। पर अंततः राजनीतिक कैरियर की खातिर विचाराधारा के सियासी आवरण को उतार फेंक जितिन भाजपा के हो लिए। इसके साथ ही बीते डेढ़ दशक से कांग्रेस के युवा चमकते चेहरों की टीम का बिखराव तेज हो गया है। सचिन पायलट की नाराजगी दूर करने के लिए एक साल पहले किए गए वादे पर अभी तक अमल नहीं हुआ है और स्वाभाविक रूप से राजस्थान में एक बार फिर वे अपने असंतोष को छिपा नहीं रहे हैं।

जितिन के पार्टी छोड़ने के बाद हाईकमान इससे सबक लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पायलट और उनके समर्थकों को तवज्जो दिलाने के लिए गंभीर नहीं हुआ तो विद्रोह की चिंगारी कभी भी फूट सकती है। पार्टी नेतृत्व के लिए यह बात चिंतनीय है कि जिन युवा चेहरों को कांग्रेस के भविष्य की सियासत के लिए उसने तैयार किया उनका ही आज संगठन व लीडरशिप दोनों में भरोसा दिखाई नहीं दे रहा। वे भाजपा में अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं जबकि 2004 में संप्रग के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने इन सभी युवा चेहरों को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर पार्टी के शीर्ष संगठन में एक दशक तक अहम जिम्मेदारियां दीं। महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा बीते कुछ साल से लगातार कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाते हुए चिंता जाहिर करते रहे हैं और कुछ मौकों पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं। ऐसे में देवड़ा कब तक कांग्रेस को अपना सियासी घर बनाए रखते हैं इसको लेकर अटकलें तो लगाई ही जा रही हैं। इसी तरह हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाईकमान के साथ समीकरण दुरुस्त नहीं होने के कारण युवा दीपेंद्र हुड्डा भी सियासी बाउंड्री लाइन पर ही खड़े माने जा रहे हैं।

यूं तो पिछले कुछ महीनों में भाजपा में शामिल होने वालों की लंबी कतार होती थी और चुनावी माहौल में वह सब सामान्य था लेकिन गत दिनों जब भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने किसी लोकप्रिय चेहरे के पार्टी में आने की खबर दी तो अटकलों की बाढ़ भी आ गई। कांग्रेस में संदेह

दरबारी संस्कृति से दूरी

कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से दरबारी संस्कृति के बोलबाले का आरोप लगाया जाता रहा है। यहां तक कहा जाता है कि कांग्रेस को कमजोर करने में कुछ लुटियंस नेताओं और पत्रकारों का बड़ा हाथ रहा है, जो जमीनी सच्चाई से कोसों दूर रहे हैं। इन लोगों पर सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स पर भी कांग्रेस के दरबारी होने के आरोप लगते रहे हैं। माना जा रहा है कि ऐसे लोगों से खुद को दूर कर राहुल गांधी कांग्रेस में अंदर तक घर कर चुकी दरबारी संस्कृति को किनारे लगाना चाहते हैं। एक तरह से राहुल गांधी इन दिनों सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। 5 राज्यों में हुए हालिया विधानसभा चुनावों के नतीजे कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए, तो बाकी के 4 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पहले से ही तमाम मुश्किलों से घिरा हुआ है। जी-23 नेताओं ने पिछले साल से ही राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।

का साया गहरा गया। बलूनी के ट्वीट के जवाब में लोगों ने अलग-अलग नाम पेश कर दिए लेकिन सूत्रों की मानी जाए तो यह अटकल सबसे ज्यादा कांग्रेस खेमे में लगाई जाने लगी। पार्टी से नाराज जितिन प्रसाद पर तो सबकी नजरें थीं ही लेकिन सचिन पायलट से लेकर मिलिंद देवड़ा तक सब पर संदेह की सुई घूमती रही। सूत्रों के अनुसार अलग-अलग नेताओं को टटोलने और संपर्क साधने का जिम्मा भी दे दिया गया और हर किसी की वर्तमान लोकेशन का पता लगाया जाने लगा। अलग-अलग स्तर पर कई नेताओं की घंटी बजी। यह इतना गुप्त रखा गया था कि भाजपा कार्यालय के अंदर कई वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी अंतिम मौके पर ही इसकी भनक लगी कि शामिल होने वाले जितिन प्रसाद हैं। दरअसल, कांग्रेस से नेताओं के जाने का सिलसिला वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ था। उस समय हरियाणा के दिग्गज वीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह भाजपा में शामिल हो गए थे। दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट में मंत्री भी बने। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के एक वर्ष बाद असम कांग्रेस के दिग्गज हिमंता बिस्व सरमा भाजपा में शामिल हो गए। वर्ष 2016 में असम में भाजपा की सरकार आने पर वह कैबिनेट मंत्री बने। हाल में हुए विधानसभा चुनावों के बाद प्रदेश में जब भाजपा की दोबारा सरकार बनी तो सरमा पर मोदी और शाह ने विश्वास जताते हुए उन्हें मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया। वर्ष 2019 में असम में कांग्रेस को एक और झटका लगा। उस समय राज्यसभा में उसके मुख्य सचेतक भुवनेश्वर कलिता ने अचानक इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। वह अब असम से भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वालों में यूपीए शासन में विदेश मंत्री रहे एसएम कृष्णा भी हैं। इतना ही नहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे और विधानसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भी 2019 में भाजपा में शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया था। हाल के दिनों में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले प्रमुख चेहरों में तमिल अभिनेत्री खुशबू सुंदर और कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता टाम वड्डक्कन शामिल हुए हैं।

पूर्वोत्तर में कांग्रेस को उस समय झटका लगा जब मणिपुर में उसके पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री इबोबी सिंह के साथ मतभेदों का हवाला देते हुए भाजपा में शामिल हो गए। अरुणाचल प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी विधानसभा चुनाव से पहले 2016 में कांग्रेस छोड़ दी थी। उत्तराखंड में तो कांग्रेस के ढाई वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष यशपाल आर्य और पूर्व मंत्री सतपाल महाराज ने भी भाजपा में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी। उप्र में भी 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश कांग्रेस की पूर्व प्रमुख रीता बहुगुणा जोशी ने पार्टी छोड़ दी थी। फिलहाल वह प्रयागराज से भाजपा सांसद हैं।

फिर भी कांग्रेस ही वह ताकत है, जिससे मोदी-शाह की ताकतवर भाजपा आज भी सतर्क रहती है। ऊपर की घटनाओं से साफ है कि कांग्रेस की वास्तविक सक्रियता या सक्रिय दिखने की कोशिश से भाजपा की पेशानी पर बल पड़ जाता है। यही वजह है कि वह सबसे ज्यादा राहुल गांधी को लगातार घेरने की कोशिश करती रही है। भाजपा का आईटी सेल तो उन्हें ही सबसे ज्यादा अपने निशाने पर रखता है। शायद भाजपा में मौजूदा दबदबे वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी को अपने पुराने दिग्गज लालकृष्ण आडवाणी की वह बात याद है कि 'कांग्रेस उस महानद की तरह है, जिसमें लाखों नदी-नाले गिरते हैं। कभी ये नदी-नाले सूखे दिखते हैं और महानद का पानी उतरा हुआ दिखता है, मगर पता नहीं, कब बारिश हो जाए, नदी-नालों में धार बहने लगे और महानद में पानी उफान मारने लगे।' यह बात उन्होंने 2004 में एनडीए-1 की हार से चौंककर पार्टी की समीक्षा बैठक में कही थी।

कांग्रेस अगर भाजपा की आज की कमजोरी का लाभ भी नहीं उठा पाती है तो उसमें शायद ही जान लौट पाए। पार्टी का दुर्भाग्य है कि वह माकूल माहौल में भी अपना घर संभालने में ही ऐसी उलझी हुई है कि अस्थाई नेतृत्व और संगठन की मजबूती के लिए चुनाव की मांग करने वाले नेताओं से ही संवाद कायम नहीं कर पाती। बीमार सोनिया गांधी को भी जी-23 में से मनीष तिवारी और अन्य कुछ नेताओं की अलग-अलग समितियां बनाकर उनका पाला कमजोर करना ही बेहतर लगा। ये नेता शायद अध्यक्ष पद पर राहुल को चुनौती देना नहीं चाहते, बल्कि यह चाहते हैं कि पार्टी में उनकी भी सुनी जाए। उनकी यही शिकायत है कि पार्टी की कमान संभालने के बाद से ही राहुल उनसे कोई संवाद नहीं करते। इसलिए इन नेताओं का जोर पार्टी कार्यकारिणी का चुनाव कराने पर है, जो 1996 में आखिरी बार हुए थे। कार्यकारिणी के चुनाव के बाद समूह का जोर पार्टी के पुराने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के गठन पर है, **ताकि उन्हें फैसलों में हकदार** होने का मौका मिले। बहरहाल, इधर राहुल कुछ बदले हुए दिखे हैं। मसलन, 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के एक दिन पहले 1 मई को वे बोले, 'पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, निभाऊंगा।' शायद उन्हें असम और केरल में अच्छे नतीजों की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले साल उप्र, पंजाब सहित कई राज्यों के चुनाव हैं। वैसे, 10 मई की पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष के चुनाव कोविड दौर में टल गए हैं। अब पता नहीं अच्छे नतीजे कब आएंगे और कब दिन बहुरेंगे।

● रजनीकांत पारे

एक तीर से कई शिकार

अगर कांग्रेस अध्यक्ष के पद की बात करें, तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद लेने से इनकार कर दिया है। वह अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से ही लगातार कहते रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति आना चाहिए। अब तक राहुल गांधी को मनाने की जितनी भी कोशिशें की गई हैं, वो सब बेकार हो चुकी हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी बीते साल से ही ऐसे संकेत देती नजर आई हैं। कहा जा सकता है कि इस बार राहुल अपने फैसले पर अडिग हो चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी के करीबी कांग्रेस नेताओं में शामिल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली लाने की कवायद की जा रही है। राजस्थान की सियासी फिजाओं में घुलती जा रही तपिश को शांत करने के लिए अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बैठाकर एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिशें हो रही हैं। गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर राजस्थान में सचिन पायलट की ताजपोशी होना तय है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे के साथ अशोक गहलोत की सांठ-गांठ के आरोपों का अंत हो जाएगा।

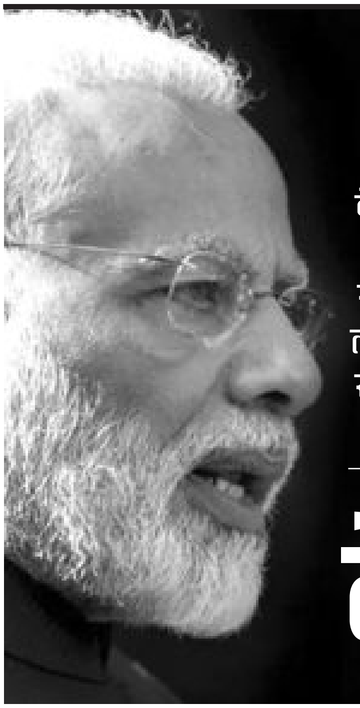

पिछले चार दशकों के दौरान केंद्र में चाहे जिस दल या गठबंधन की सरकार रही हो, सभी ने अपने विरोधी दलों की राज्य सरकारों को परेशान करने और दलबदल को बढ़ावा देकर उन्हें गिराने में राज्यपालों का भरपूर इस्तेमाल किया और राज्यपाल भी खुशी-खुशी इस्तेमाल हुए या केंद्र सरकार को खुश करने के लिए अपने स्तर पर ही राज्य सरकारों को तरह-तरह से परेशान करते रहे या उन्हें अस्थिर करने का खेल खेलते रहे। ऐसा ही वर्तमान में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और केंद्र की मोदी सरकार में टकराव देखा जा रहा है।

केंद्र बनाम राज्य

यह ठीक है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया था, अपनी पूरी टीम को चुनाव के मैदान में उतार डाला था, उसके बावजूद चुनौती को स्वीकार करके तृणमूल कांग्रेस ने उसे जिस तरह पटखनी दी, उस चोट को भाजपा शायद ही कभी भूल पाए। उधर, ममता बनर्जी भी भाजपा की करतूतों को नहीं भूली हैं। वे भाजपा को उसी की भाषा में जवाब देने लगी हैं। इस कारण केंद्र और राज्य में तनाव बढ़ता जा रहा है।

विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने टीएमसी के विधायकों और सांसदों को तोड़कर ममता को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब ममता बनर्जी भाजपा में तोड़फोड़ कर रही हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु रॉय के साथ आखिरकार 4 साल के बाद टीएमसी में वापसी कर गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए कहा कि मुकुल घर का लड़का है, घर ही वापस आया है। अभिनंदन है। इसी के साथ मुकुल रॉय और ममता बनर्जी की दूरियां खत्म हो गईं, लेकिन अब सवाल यह है कि 4 साल के बाद घर वापसी करने वाले मुकुल रॉय की भूमिका पार्टी में क्या होगी?

मुकुल रॉय ने जिन उम्मीदों के साथ 2017 में टीएमसी छोड़ी थी, वो भाजपा में रहने के दौरान पूरी नहीं हो सकी। भाजपा ने उन्हें विधानसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो बनाया, लेकिन चुनाव के दौरान कोई खास भूमिका नहीं रही। चुनाव के बाद प्रतिपक्ष के नेता के चयन का मामला आया तो मुकुल रॉय की जगह हाल ही में पार्टी में शामिल शुभेंदु अधिकारी को इस पद पर बिठा दिया गया। इसके बाद उनके पास भाजपा में बने रहने की कोई वजह नहीं बची थी। यही वजह रही कि मुकुल रॉय ने घर वापसी करना बेहतर समझा।

टीएमसी में शामिल होने के बाद मुकुल रॉय ने कहा कि मुझे पार्टी में वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। भाजपा से बाहर निकलकर अपने लोगों और पुराने लोगों से मिलकर बहुत संतुष्टि मिल रही है। मैं भाजपा में काम नहीं कर पाया, जिसके चलते **अपने पुराने घर वापस** आ गया। उन्होंने कहा कि भाजपा की बंगाल में जो हालत है, ऐसे में कोई भी नेता वहां नहीं रहेगा। मैं वहां नहीं रह सका। इसलिए घर लौट आया। उन्होंने ममता की जमकर तारीफ की।

मौजूदा समय में मुकुल रॉय की भूमिका टीएमसी में काफी अहम होने जा रही है। ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में आने के साथ ही अपनी पार्टी का विस्तार पश्चिम बंगाल से बाहर दूसरे राज्यों में भी करना चाहती है। खासकर ओडिशा और नार्थ ईस्ट के राज्यों में, जहां पहले भी टीएमसी एक दो सीटें जीतती रही है। ऐसे में मुकुल रॉय को इन राज्यों में टीएमसी जनाधार बढ़ाने और पार्टी का विस्तार करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान ही जिस तरह से मोदी सरकार और खिलाफ विपक्ष को एकजुट होने का ऐलान किया है, वो अभी भी उनके एजेंडे में है। ऐसे में देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने और उन्हें एकजुट करने की मुहिम में मुकुल रॉय को ममता बनर्जी लगा सकती हैं। मुकुल रॉय टीएमसी में रहते हुए केंद्रीय राजनीति ही किया करते थे और उनके तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ बेहतर

बंगाल भाजपा के अंदर खेला होबे

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश भाजपा में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस बात की भनक भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भी है। यही कारण है कि पिछले दो दिनों से दिल्ली में पश्चिम बंगाल और वहां पार्टी के हालात पर गहन मंथन का दौर जारी है। जिस तरह से चुनाव नतीजों के बाद भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, उसके बाद से भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी पर हल्ला बोल रखा है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती भाजपा नेतृत्व के सामने पार्टी को राज्य में एकजुट रखने और कैडर का मनोबल बनाए रखने की है। खासकर ऐसे माहौल में जबकि टीएमसी छोड़कर चुनावों से पहले भाजपा में आए कुछ नेताओं की घर वापसी को लेकर अटकलों का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी से भाजपा में आए ज्यादातर नेता चुनाव हार गए हैं। सूत्रों की मानें तो उन्हें डर सता रहा है कि बिना विधायक रहे ममता बनर्जी के खिलाफ राजनीति करना मुश्किल है। इसी बीच टीएमसी से आए कुछ नेताओ ने प्रदेश संगठन और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल, ये दिक्कत साल 2018 के बाद से ही टीएमसी से भाजपा में आए नेताओं की है।

संबंध रहे हैं। विपक्षी दलों को एकजुट करने में वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं।

दरअसल, टीएमसी छोड़ने से पहले मुकुल रॉय की हैसियत पार्टी में नंबर दो की हुआ करती थी। चुनावी प्रबंधन का काम मुकुल रॉय संभाला करते थे। बंगाल के कोने-कोने में टीएमसी संगठन को मजबूत करने में उनकी भूमिका बेहद अहम रही है। इसी वजह से मुकुल को बंगाल की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता रहा। टीएमसी में मुकुल की जगह अब भी खाली है। मुकुल रॉय के लिए टीएमसी में भाजपा से ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं। मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी से ना सिर्फ उनका रुतबा बढ़ेगा, बल्कि सत्ता, सम्मान और बेटे का भविष्य भी बनता दिख रहा है। ऐसे में राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी की वापसी को एक झटके में लिया गया फैसला नहीं मानना चाहिए। मुकुल रॉय की टीएमसी वापसी ने भाजपा को पश्चिम बंगाल में भारी झटका दिया है। मुकुल की वापसी टीएमसी के लिए कई लिहाज से अहम है।

साल 2017 में मुकुल रॉय टीएमसी छोड़कर भाजपा में जाने वाले पार्टी के पहले नेता थे। इसके बाद ही टीएमसी में तेजी से भगदड़ मची और देखेते ही देखते पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। यह भी कहा जाता है कि इन्हें भाजपा में लाने में मुकुल की अहम भूमिका थी। ऐसे में अब यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि मुकुल की वापसी से क्या फिर वैसी ही पुनरावृत्ति होगी। खासकर उन नेताओं की जो मुकुल के बाद टीएमसी छोड़कर भाजपा में गए थे।

बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से कई नेता ममता बनर्जी से दोबारा पार्टी की सेवा का करने की गुहार लगा चुके हैं। वहीं, टीएमसी महासचिव कुणाल घोष तो यहां तक दावा कर चुके हैं कि भाजपा के 10 विधायक और 3 सांसद पार्टी के संपर्क में हैं। पूर्व सिंचाई मंत्री राजीव बनर्जी भी भाजपा की नीति की आलोचना कर चुके हैं और माना जा रहा है कि वो घर वापसी के जुगत में है। हालांकि, ममता ने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बिना कहा कि चुनाव से पहले गद्दारी कर भाजपा का हाथ मजबूत करने वालों को पार्टी कभी वापस नहीं लेगी।

तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए लोगों की घर वापसी रोकने के लिए भाजपा एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि, पार्टी की यह कोशिश नाकाम होती दिख रही है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने गत दिनों राजभवन में पार्टी विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। इस दौरान करीब 24 विधायकों ने मीटिंग से दूरी बना ली। तभी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं अब बंगाल भाजपा में टूट तो नहीं होने जा रही। भाजपा नेताओं की बैठक का मकसद राज्यपाल को राज्य में हो रही कई हिंसक और गलत घटनाओं की जानकारी देना और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करना था, लेकिन भाजपा के 74 में से 24 विधायक शुभेंदु के साथ नहीं आए। ऐसे में पार्टी से रिवर्स माइग्रेशन की अटकलें शुरू हो गईं हैं। इसकी वजह यह भी मानी जा रही है कि सभी भाजपा विधायक शुभेंदु को नेता के तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहते।

ममता-टिकैत की मुलाकात

अब तक गैर राजनीतिक प्रदर्शन का दम भरने वाले किसान आंदोलन में राजनीतिक रंग और चटक होने लगे हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में तो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पहले ही भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार कर चुके हैं। अब वे उप्र विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। इसके साथ ही वे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए किसानों के उस धरना स्थल पर पॉलिटिकल मंच भी तैयार करेंगे, जहां पिछले 7 महीनों से धरना चल रहा है। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का साथ देने का भरोसा दिया है। ये सारी चर्चा 9 जून को कोलकाता में दोनों के बीच हुई मुलाकात के दौरान हुई। इसमें दीदी ने साफ किया कि हम किसानों का मुद्दा संसद में उठाएंगे और टिकैत ने कहा कि किसान उप्र के हर जिले में भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। बंगाल में जीत के बाद ममता के हौसले बुलंद हैं। अब वे दूसरे राज्यों में भी पैर जमाने की योजना पर काम कर रही हैं। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। सबसे बड़ा दांव उप्र में खेला जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा के कई विधायक तृणमूल के संपर्क में हैं। माना जा रहा है कि कई भाजपा विधायक वापस तृणमूल कांग्रेस में जा सकते हैं। पिछले हफ्ते मुकुल रॉय तृणमूल में लौट आए। माना जा रहा है कि राजीव बनर्जी, दीपेंदु विश्वास और सुभ्रांशु रॉय सहित कई अन्य नेता भी रॉय के पीछे-पीछे घर वापसी कर सकते हैं। रॉय भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और कृष्णानगर उत्तर सीट पर जीत हासिल की थी।

इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा था कि पार्टी उन लोगों के मामले पर विचार करेगी, जिन्होंने मुकुल के साथ तृणमूल छोड़ी थी और वापस आना चाहते हैं। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक, 30 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं। रॉय से पहले सोनाली गुहा और दीपेंदु बिस्वास जैसे नेताओं ने खुलकर कहा था कि वे पार्टी में वापस लौटना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष की बुलाई बैठक में पार्टी के सांसद शांतनु ठाकुर और तीन अन्य विधायक नहीं पहुंचे थे। प्रभावशाली मतुआ समुदाय के एक प्रमुख सदस्य सांसद शांतनु ठाकुर विधानसभा चुनाव से पहले ही बंगाल में सीएए कानून को लागू करने को लेकर भाजपा के रुख से असंतुष्ट हैं। इनके अलावा तीन विधायक बिस्वजीत दास (बगड़ा), अशोक कीर्तनिया (बोनगांव उत्तर) और सुब्रत ठाकुर (गायघाटा) के नाम की चर्चा हो रही है।

बंगाल की 294 में से 213 सीटें टीएमसी ने जीती हैं। 77 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है। चुनाव के चंद महीनों पहले टीएमसी के 50 से ज्यादा नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया था। इसमें 33 तो विधायक थे, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार भाजपा ही जीतेगी। कई की आस भाजपा में आने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि पार्टी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। नेताओं की भाजपा से दूरी बनाने की तीन बड़ी वजहें थीं। पहली वजह, उनका टिकट काटा या बदला गया था। दूसरी, वे पार्टी जिस ढंग से चल रही थी, उससे खुश नहीं थे। तीसरी, वे भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त थे और उन्हें भाजपा से टिकट मिलने की भी उम्मीद थी। पर नतीजों ने दल-बदलुओं को बड़ा झटका दिया। इसलिए अब ये नेता घर वापसी चाहते हैं।

● **इन्द्र कुमार**

कैंप के खिलाफ 40 गांवों के लोग

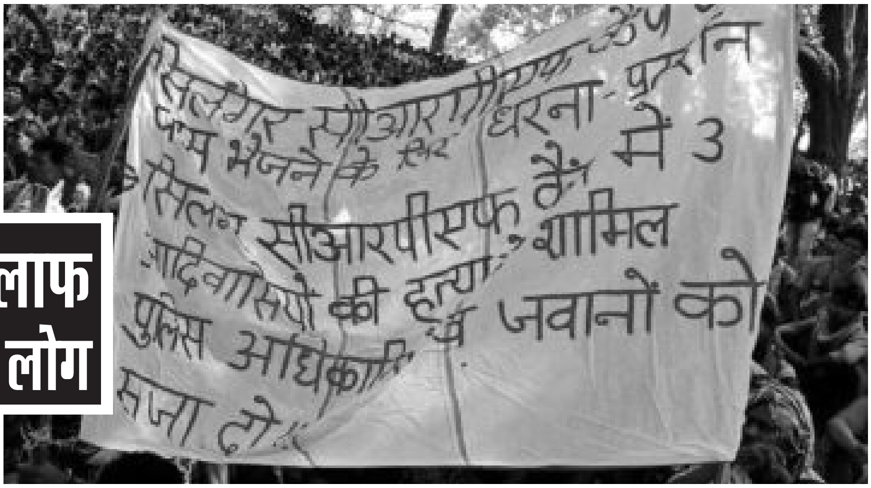

माओवाद प्रभावित सुकमा जिले के सिलगेर में पुलिस फायरिंग में तीन आदिवासियों की मौत के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। बीजापुर और सुकमा जिले के कलेक्टरों के साथ बैठक के बाद भी आदिवासी अपनी जमीन से कैंप हटाए जाने की मांग पर डटे हुए हैं। सिलगेर पंचायत के तीन गांवों के अलावा आसपास के कम से कम 40 गांवों के लोग केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) की 153वीं बटालियन के कैंप के खिलाफ सड़कों पर हैं।

प्रदर्शनकारियों में शामिल अरलमपल्ली गांव के सोडी दुला कहते हैं कि सरकार कहती है कि सड़क बनाने के लिए पुलिस का कैंप बनाया गया है लेकिन इतनी चौड़ी सड़क का हम आदिवासी क्या करेंगे? वो कहते हैं, हमें हमारी सुविधा के लायक सड़क चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए, स्कूल चाहिए, **अस्पताल चाहिए,** हैंडपंप चाहिए। क्या इसके लिए पुलिस कैंप की जरूरत होती है? सोडी दुला की बात खत्म भी नहीं होती कि पीछे से एक और आवाज आती है, हमारे भले के लिए कैंप बनाया जा रहा है तो हमें ही गोली क्यों मारी जा रही है? तीन लोगों को पुलिस ने गोली क्यों मारी? वहीं, जगदलपुर में पुलिस के आला अधिकारी यह बात बताते नहीं थकते कि माओवादियों के बहकावे में आदिवासी किसान, सुरक्षाबल के कैंप का विरोध कर रहे हैं।

बस्तर के आईजी पुलिस सुंदरराज पी का कहना है कि पुलिस कैंप के कारण माओवादियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है इसलिए वो गांव वालों को दबाव डालकर कैंप का विरोध करने के लिए बाध्य करते हैं। पुलिस का कहना है कि 17 मई की फायरिंग में मारे गए तीनों लोग भी माओवादी संगठन से जुड़े हुए थे। हालांकि पुलिस के दावे के उलट गोलीकांड की जांच के लिए पहुंचे सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर का दावा है कि मारे गए सभी तीन लोग और गोलीकांड में घायल लगभग दो दर्जन लोगों में से कोई भी माओवादी नहीं था। प्रकाश ठाकुर का कहना है कि इस इलाके से लोग बड़ी संख्या में पड़ोसी राज्य तेलंगाना में मिर्ची तोड़ने के काम में जाते हैं। मारे गए लोग भी कुछ दिन पहले ही मिर्च तोड़कर लौटे थे।

प्रकाश ठाकुर ने बातचीत में कहा, पुलिस अपने बचाव के लिए झूठ बोल रही है। पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई और गोली सीधे सिर्फ माओवादियों को लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? मारे गए लोग किसान मजदूर थे। आदिवासी महासभा के नेता और पूर्व विधायक मनीष कुंजाम भी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे और उन्हें गांव वालों ने बताया कि मारे गए तीनों आदिवासियों के परिजनों को जिला प्रशासन की ओर से 10-10 हजार रुपए के तीन लिफाफे दिए गए थे। अब ग्रामीण इन लिफाफों को सरकार को वापस करना चाहते हैं। ग्रामीणों का सवाल है कि अगर मारे गए लोग माओवादी थे तो सरकार ने मुआवजा क्यों दिया और अगर मारे गए लोगों को सरकार आदिवासी किसान मानती है तो फिर उन्हें माओवादी के तौर पर गलत ढंग से क्यों प्रचारित किया गया?

सुकमा और बीजापुर के सिलगेर में जब सीआरपीएफ का कैंप बनाए जाने की ख़बर इस महीने के शुरुआत में सामने आई तो गांव वाले विरोध के लिए पहुंचे। उनसे कहा गया कि अभी कोई कैंप स्थापित नहीं किया जा रहा है लेकिन 12 मई को कैंप बन गया। इसके दो दिन बाद आसपास के कुछ गांवों के आदिवासी विरोध प्रदर्शन के लिए कैंप के पास सड़क पर बैठ गए। उनका आरोप था कि जहां कैंप बनाया गया है, वहां ग्रामीणों की जमीन है।

ग्रामीणों का कहना है कि 17 मई को आदिवासियों और सुरक्षाबल के जवानों के बीच बहस शुरू हुई और सुरक्षाबल के जवानों ने लाठी चार्ज कर दिया। गांव के लोगों का आरोप है कि लाठी चार्ज के बाद भी जब वो नहीं माने और कैंप की ओर बढ़े तो जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि पुलिस का दावा है कि पहले भीड़ में शामिल माओवादियों ने फायरिंग की जिसके जवाब में सुरक्षाबलों ने बाद में फायरिंग की। पुलिस की इस गोलीबारी में तीन प्रदर्शनकारी मारे गए और दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इसके अलावा पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में भी लिया।

ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि 8 लोगों को पुलिस ने तीन दिन तक अपने कब्जे में रखा। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर दबाव बनाया कि जब वे आंदोलन खत्म करेंगे तभी ग्रामीणों को छोड़ा जाएगा। हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर बस्तर के आईजी पुलिस सुंदरराज पी ने मीडिया से कहा कि ग्रामीणों को पूछताछ के लिए रखा गया है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

गोली कांड पर कांग्रेस और भाजपा दोनों चुप

आलोक शुक्ला का मानना है कि यह अकारण नहीं है कि इस गोलीकांड पर भाजपा और कांग्रेस की तरफ से किसी एक भी नेता का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। उनका मानना है कि आदिवासी किसानों को माओवादी बताना इन आदिवासियों को माओवादियों के पाले में धकेलने की तरह है। शुक्ला कहते हैं, एक क्षण के लिए मान लें कि कैंप का विरोध माओवादियों के इशारे पर हो रहा था तो सरकार को तो खुश हो जाना चाहिए कि माओवादियों के इशारे पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हो रहा है। कैंप के लोकतांत्रिक विरोध को तो सरकार को अवसर की तरह देखना चाहिए। बस्तर में पिछले सालभर में सुरक्षाबलों के कैंप के खिलाफ दर्जनभर से अधिक आंदोलन हो चुके हैं। कई-कई दिनों तक चलने वाले इन प्रदर्शनों में हर बार पुलिस यही आरोप लगाती है कि यह माओवादियों के इशारे पर हो रहा है।

...पायलट को रोकना कांग्रेस के लिए चुनौती

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की टीम का एक के बाद एक विकेट गिरता जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। राहुल गांधी के करीबी सचिन पायलट उनसे किए गए वादे 10 महीने बाद भी पूरे नहीं होने पर नाराज हैं, जिनके समर्थन में पार्टी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह भी आ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बढ़ गया है। जितिन की खबर आने के बाद सचिन पायलट ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड में बने हुए हैं। देखना ये है कि सचिन पायलट को पार्टी अपने साथ कैसे साधकर रखती है?

जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होते ही सचिन पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। सचिन पायलट के साथ जो वादे किए गए थे, उन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया। सुलह के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने कोई बैठक नहीं की। हम लोग प्रियंका गांधी से दिल्ली में मिले थे, तब बात हुई थी कि हमारी सुनवाई होगी, लेकिन अभी तक हमें बुलाया नहीं गया। हम खुद दो बार दिल्ली जाकर अपना दर्द बताकर आए हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। बता दें कि पिछले साल अगस्त में सचिन पायलट के नेतृत्व में राजस्थान के कई कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया था। उस वक्त दोनों गुटों के नेताओं ने **कई दिनों तक होटल** में अपने समर्थक विधायकों को बंद रखा था। इसके चलते मुख्यमंत्री गहलोत ने पायलट को उपमुख्यमंत्री पद से और उनके दो समर्थकों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। गहलोत सरकार को अस्थिर देखकर भाजपा भी सक्रिय हो गई थी, लेकिन हाईकमान के दखल के बाद पायलट मान गए थे।

पायलट-गहलोत के बीच वर्चस्व की जंग खत्म करने के लिए एक सुलह कमेटी बनी, लेकिन अभी तक न तो पायलट के जिन सहयोगियों को मंत्री पद से हटाया गया उन्हें सरकार में वापस लिया गया और न ही सुलह कमेटी के सामने रखी गई मांगों पर कार्रवाई हुई। ऐसे में पायलट और उनके सहयोगियों के सब्र का बांध टूट रहा है। राजस्थान की राजनीति में अब 10 महीने बाद फिर से बगावत के सुर तेज हो रहे हैं। सचिन पायलट ने गत दिनों नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 10 महीने हो गए हैं और उनसे किए वादे पूरे नहीं किए गए हैं। मुझे समझाया गया था कि सुलह कमेटी तेजी से एक्शन लेगी, लेकिन आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे मुद्दे अब भी अनसुलझे ही हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए रात-दिन मेहनत की और अपना सब कुछ लगा दिया, उनकी सुनवाई ही नहीं हो रही है।

सचिन पायलट के बयान से एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत गर्मा गई है। पायलट का बयान ऐसे वक्त आया है जब उनके एक समर्थक हेमाराम चौधरी ने अपने इलाके के विकास के कामों की अनदेखी के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोई रास्ता नहीं निकलता देख कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट के समर्थन में आ गए हैं। भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट से जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए, ताकि पायलट अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर सकें। हालांकि, उन्होंने कहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने जैसी कोई बात नहीं है और न ही सरकार पर कोई खतरा है, लेकिन पायलट से किए गए वादे पूरे होने चाहिए।

पायलट के पुराने दोस्त और राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि यह हमारा पारिवारिक मामला है। राजनीतिक पार्टियों में इस तरीके की बातें चलती रहती हैं, लेकिन सरकार को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। सचिन पायलट के बयान पर कांग्रेस के सभी नेता बोलने से बच रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मामले पर नो कमेंट्स कहकर पल्ला झाड़ लिया। गहलोत गुट ने जितिन प्रसाद पर तो हमला बोला, लेकिन सचिन पायलट वाले बयान पर चुप्पी साध ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि ऐसे नेता आया राम-गया राम वाले होते हैं। जिन नेताओं की निष्ठा पार्टी के साथ होती है वह पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। कांग्रेस छोड़कर जो भी नेता भाजपा में गए हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला। भाजपा में जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मप्र में आज पांचवे-छठे नंबर के नेता भी नहीं हैं। जो कभी कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे।

सचिन पायलट ने इसी साल 14 अप्रैल को कहा था कि सुलह कमेटी में जिन तमाम मुद्दों पर सहमति बनी थी, उन पर अब कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा कारण है कि उस कमेटी के निर्णयों के क्रियान्वयन में और अधिक देरी हो। पायलट ने कहा था कि मुझे सोनिया गांधी पर पूरा विश्वास है, उनके आदेश पर ही कमेटी बनी थी।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

ढाई साल बाद भी वादे अधूरे...

सचिन पायलट ने कहा था कि जहां तक मेरा अपना मानना है कि सरकार को ढाई साल हो चुके हैं, घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, कुछ पूरे भी किए हैं और बचे हुए कार्यकाल में वादों को पूरा करने के लिए और गति से काम करना होगा। इसमें राजनीतिक नियुक्तियां हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है। उसमें पार्टी और सरकार मिलकर एकराय बनाएंगे। रमेश मीणा और अन्य विधायकों के दलित आदिवासी विधायकों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाने पर पायलट ने समर्थन किया। पायलट के बाद उनके समर्थक विधायक भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। ऐसे में देखना है कि राहुल टीम के दो विकेट गिरने के बाद कांग्रेस हाईकमान अब किस तरह से पायलट को साधकर रखता है।

महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार में रोजाना दांव खेला जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जहां भाजपा का मोह त्याग नहीं पा रहे हैं, वहीं एनसीपी नेता शरद पवार राज्य में अपने बूते पर सरकार बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं।

पवार की पावर पॉलिटिक्स

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी रणनीति के काम से ब्रेक ले चुके प्रशांत किशोर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के बीच गत दिनों तकरीबन 4 घंटे की लंबी मुलाकात हुई।

शरद पवार के मुंबई स्थित सिल्वर ओके बंगले में हुई इस मीटिंग के बाद महाराष्ट्र में फिर से कयासों का दौर शुरू हो चुका है। चर्चा यह है कि प्रशांत किशोर, एनसीपी के साथ बतौर रणनीतिकार अपनी दूसरी पारी शुरू कर सकते हैं। हालांकि, राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा पवार के यूपीए अध्यक्ष के साथ विपक्ष का चेहरा बनाने की भी है। बंगाल चुनाव के बाद पवार ने ममता को फोन कर बधाई दी थी।

2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा इसे लेकर विपक्षी दलों के बीच चर्चा हो रही है। इस बीच प्रशांत किशोर और पवार की मुलाकात अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात को ममता की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना के नेता संजय राउत ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के गठबंधन के गठन के लिए बातचीत शुरू होगी। प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच हुई मुलाकात को लेकर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे में कहा, प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। वे पवार साहब से अपने कुछ अनुभव साझा करने आए होंगे या फिर उनका कुछ और काम होगा। उन्होंने अब राजनीति का काम छोड़ दिया है। इसलिए जो भी चर्चा हो रही है वह निराधार है। अजित पवार ने आगे कहा, शरद पवार से विभिन्न क्षेत्रों के लोग मिलने आते हैं।' क्या यह मुलाकात 2024 के चुनावों को लेकर है, इस पर पवार ने कहा, प्रशांत किशोर ने खुद कहा कि बंगाल का चुनाव उनका आखिरी है। प्रशांत किशोर अब तक नरेंद्र मोदी, जगन मोहन रेड्डी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए बतौर चुनावी रणनीतिकार काम कर चुके हैं।

पीके और पवार की मुलाकात को लेकर मुंबई के राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राज्य के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि पीके और पवार के बीच बातचीत का मुख्य मुद्दा एंटी भाजपा मोर्चे के नेतृत्व का ही हो सकता है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो यह कि यूपीए का नेतृत्व सोनिया गांधी या कांग्रेस की बजाय शरद पवार को सौंपे जाने की मांग शिवसेना के सांसद संजय राउत पहले ही कर चुके हैं। दूसरी शरद पवार की संगठन क्षमता और देशभर की राजनीतिक पार्टियों में उनके संबंध उनकी स्वीकार्यता को बढ़ाते हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल के हालिया चुनाव में मोदी और शाह की अपराजेय समझी जाने वाली जोड़ी को ममता बनर्जी ने जिस तरह धोबी पछाड़ दी है, उससे ममता बनर्जी एंटी भाजपा मोर्चे की नई नेता के तौर पर उभरकर सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में प्रशांत किशोर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम कर रहे थे। एक और मुद्दा चर्चा का यह भी है कि अगर एंटी भाजपा कोई मोर्चा बनता है, तो उसमें कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? क्या कांग्रेस किसी ऐसे मोर्चे का हिस्सा बनना पसंद करेगी, जिसका नेतृत्व उसके पास नहीं होगा?

दूसरा मुद्दा महाराष्ट्र मॉडल और पश्चिम बंगाल मॉडल पर चर्चा का है। शरद पवार ने जिस तरह शिवसेना और कांग्रेस जैसे दो विपरीत विचारधारा वाले राजनीतिक दलों को गठबंधन में लाकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार की स्थापना की है, क्या उसी तरह का मॉडल पूरे देश में अप्लाई किया जा सकता है? दूसरा बंगाल का मॉडल है जहां ममता बनर्जी ने भाजपा को उतनी ही आक्रामकता से जवाब दिया है, जितनी आक्रामकता से भाजपा ने बंगाल में चुनाव प्रचार किया था। क्या यही मॉडल आने वाले लोकसभा चुनावों में कारगर हो पाएगा? चुनाव की नई तकनीकों की कारगरता, भाजपा के प्रचार तंत्र को मात देने की तकनीक, पेशेवर चुनाव प्रबंधन और उसकी विश्वसनीयता, भाजपा के धनतंत्र के मुकाबले में चुनावी खर्च का किफायती प्रबंधन आदि मुद्दों पर भी बात होने की बात कही जा रही है। बहरहाल, 2024 के चुनावों में अभी लंबा वक्त है, लेकिन उससे पहले उप्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उप्र में भाजपा की आंतरिक कलह इन दिनों काफी तेज है। इस पर भी दोनों नेताओं के बीच विचार-विमर्श होने की बात की जा रही है।

● बिन्दु माथुर

मुलाकात के बाद मोदी के प्रति शिवसेना के तेवर ढीले

इधर महाराष्ट्र में शासन कर रही महाविकास आघाड़ी में भी इन दिनों नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। गत दिनों पहले ही अपने दो वरिष्ठ मंत्रिमंडलीय साथियों के साथ प्रधानमंत्री से मिलने गए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने समय निकालकर प्रधानमंत्री मोदी से अलग से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री के प्रति शिवसेना के तेवर ढीले नजर आ रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद शरद पवार ने स्व. बालासाहब ठाकरे के इंदिरा गांधी से संबंधों का उदाहरण देते हुए शिवसेना के भरोसेमंद पार्टी होने का बयान दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस के निरंतर कमजोर होने के कारण शरद पवार अपने लिए राष्ट्रीय फलक पर भी नए अवसर तलाश रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राऊत उन्हें यूपीए का अध्यक्ष बनाने की मांग पहले ही उठा चुके हैं। प्रशांत किशोर के कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से संपर्क का लाभ उठाकर पवार अपने नेतृत्व में कोई महाविकास आघाड़ी की तर्ज पर कोई नया गठबंधन खड़ा करें तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए।

उप्र सहित देश की राजनीति में बसपा जिस तेजी से उभरी थी, उसी तेजी से उसका पतन भी हो रहा है। इसकी वजह है मायावती का अक्खड़पन। अब मायावती अकेली पड़ती जा रही हैं।

अकेली पड़तीं मायावती

बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने गत दिनों जिस समय दो वरिष्ठ विधायकों राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी से निकालने का आदेश जारी किया उस वक्त ये दोनों विधायक आंबेडकरनगर जिले में अलग-अलग बैठकें करके जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए रणनीति तय कर रहे थे। मायावती ने अपने इन दोनों विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाया। आंबेडकरनगर के दो वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से बाहर निकालने के निर्णय से यह संदेश गया है कि बसपा के भीतर सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। आंबेडकरनगर जिला मायावती की राजनीति का केंद्रबिंदु रहा है। मायावती आंबेडकरनगर से लोकसभा चुनाव लड़ती रही हैं। सबसे पहले मायावती वर्ष 1989 में बिजनौर लोकसभा सीट जीत कर संसद में पहुंची थीं। उसके बाद वर्ष 1998, 1999 और वर्ष 2004 में मायावती अकबरपुर (वर्तमान में आंबेडकर नगर) सीट से चुनाव जीतकर सांसद बनीं थीं। मायावती जब यहां से चुनाव नहीं लड़ी उसके बाद भी वर्ष 2009 और 2019 में आंबेडकर नगर लोकसभा सीट से बसपा उम्मीदवार ने जीत हासिल की। इससे जाहिर होता है कि आंबेडकर नगर बसपा की राजनीति का एक बड़ा केंद्र है।

आंबेडकर नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत पांच विधानसभा सीटें आती हैं। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में इनमें से दो अकबरपुर विधानसभा सीट से राम अचल राजभर और कटेहरी विधानसभा सीट से लालजी वर्मा ने चुनाव जीता था। वर्ष 1984 में बसपा की स्थापना के समय से ये दोनों नेता पार्टी के साथ थे। आंबेडकर **नगर में इन दोनों** बसपा नेताओं के बीच बेहतर तालमेल था। वर्ष 2017 में बसपा ने लालजी वर्मा को विधानमंडल दल का नेता बनाया था। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने राम अचल राजभर को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। विधानसभा चुनाव में बुरी हार के बाद मायावती ने राजभर को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर बसपा का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया था। आंबेडकर नगर में बसपा की अंदरूनी राजनीति में उस वक्त खींचतान शुरू हुई जब जुलाई 2020 में मायावती ने बसपा नेता और पूर्व सांसद घनश्याम चंद खरवार का कद बढ़ाते हुए उन्हें गोरखपुर मंडल के साथ फैजाबाद (अयोध्या) मंडल का भी मुख्य सेक्टर प्रभारी बना दिया। आंबेडकर नगर के रहने वाले डॉ. राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद में इतिहास विभाग के पूर्व जयकरन वर्मा बताते हैं, 'पिछले 30 वर्षों में आंबेडकर नगर में राम अचल राजभर और लालजी वर्मा बसपा के दो बड़े नेता थे। मायावती ने जैसे ही घनश्याम चंद खरवार का पार्टी के भीतर कद बढ़ाया, आंबेडकर नगर में बसपा संगठन का संतुलन गड़बड़ा गया।' संगठन में हुए बदलाव का असर आंबेडकर नगर में अप्रैल में संपन्न हुए जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में देखा जा सकता है। आंबेडकर नगर में जिला पंचायत सदस्य की 23 सीटों पर घनश्याम चंद खरवार ने अपने करीबियों को बसपा का समर्थित उम्मीदवार घोषित किया था। पंचायत चुनाव में अपने करीबियों को तवज्जो न मिलने से लालजी वर्मा और राम अचल राजभर नाराज थे। इसी कारण लालजी वर्मा की पत्नी और आंबेडकर नगर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा वर्मा ने बसपा के समर्थित उम्मीदवार के रूप में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था। मायावती ने इसे अनुशासनहीनता माना। नाराज मायावती ने लालजी वर्मा और रामअचल राजभर को पार्टी से निकाल दिया।

वर्ष 2007 के उप्र विधानसभा चुनाव में कुल 403 विधानसभा सीटों में से 206 सीटें जीत कर सरकार बनाने वाली बसपा वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर सिमट गई थी। पिछले चार वर्षों के दौरान अनुशासनहीनता के आरोप में बसपा से 9 विधायक निलंबित हो चुके हैं। वर्ष 2019 में आंबेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा सीट हारने के बाद अब दो विधायकों के निष्कासन से बसपा के पास विधायकों की संख्या 7 बची है। लखनऊ में विद्यांत पीजी कालेज में अर्थशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और दलितों के आर्थिक-सामाजिक ढांचे का अध्ययन करने वाले मनीष हिंदवी बताते हैं, 'बसपा के संस्थापक कांशीराम के समय से पार्टी से जुड़े करीब सभी नेता मायावती का साथ छोड़ चुके हैं। इसके फलस्वरूप मायावती की सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति कारगर साबित नहीं हो पा रही है।'

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

नाराज बसपा नेताओं की पसंद सपा

बसपा से नाराज नेताओं की पहली पसंद साइकिल बनी है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन करने वाली बसपा और सपा की राहें चुनाव के बाद अलग हो गई थीं लेकिन इनके बीच तल्खी तब चरम पर पहुंची जब पिछले वर्ष 28 अक्टूबर को राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा से करीबी दिखाने वाली बसपा के विधायकों ने अपनी पार्टी से बगावत कर दी। बसपा विधायक चौधरी असलम अली, असलम राइनी, मुज्तबा सिद्दीकी और हाकिम लाल बिंद ने राज्यसभा चुनाव के चुनाव अधिकारी को बसपा प्रत्याशी के नामांकन में अपने हस्ताक्षर को फर्जी बताया और नाम वापस लेने की अर्जी दी। इन विधायकों ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। इससे गुस्साई बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सपा को हराने के लिए भाजपा का सहयोग करने की घोषणा कर दी थी। 16 जनवरी को बसपा से निष्कासित पूर्व विधायक योगेश वर्मा अपनी पत्नी सुनीता वर्मा जो कि मेरठ की महापौर हैं, के साथ सपा में शामिल हो गए। पश्चिमी उप्र की दलित राजनीति में पकड़ रखने वाले योगेश वर्मा अपनी पत्नी सुनीता वर्मा को मेरठ का मेयर निर्वाचित कराकर अपनी राजनीतिक क्षमता जाहिर कर चुके हैं।

बाहुबलियों के बेटों में पावर ट्रांसफर की दस्तक

बिहार में बाहुबली जेलों में रहकर चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। इस कारण यहां की राजनीतिक पार्टियों की कोशिश रहती है कि वे ऐसे लोगों को अधिक से अधिक टिकट दें, जो अपने बाहुबल से चुनाव जीतकर उनकी संख्या मजबूत करे। अब ऐसे ही बाहुबली नेताओं के पुत्र भी राजनीति में अपनी पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं।

राजनीति में पावर ट्रांसफर का प्रचलन बहुत पुराना है। बिहार में भी बहुत जल्द पावर ट्रांसफर होने वाला है। इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो ने अपने पावर को ट्रांसफर कर अपने दोनों बेटों को राजनीति में एंट्री दिलाई थी। यहां तक कि अपने छोटे बेटे को बिहार का उपमुख्यमंत्री बना दिया था। वहीं, रामविलास पासवान ने भी चिराग पासवान को अपना त्रिदंड दिया। अब राज्य में पावर की नई कहानी गढ़ी जा रही है। बिहार के तीन बाहुबलियों के बेटे राजनीति में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। उनमें एक आनंद मोहन के बेटे चेतन ने तो उनकी गैरहाजिरी में राजनीति में प्रवेश कर सफलता भी पा ली है। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन और पप्पू यादव के बेटे भी अब उस दहलीज पर हैं कि कभी भी उनकी ताजपोशी बिहार की राजनीति में हो जाएगी। ये तीनों बाहुबली नेता अलग-अलग जाति वर्ग से आते हैं और इनका दावा है कि इनकी जाति के लोग इनको पसंद करते हैं और आगे भी इनको अपना समर्थन देंगे।

गत दिनों बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की मौत कोरोना के कारण दिल्ली में हो गई। उसके बाद उनका कफन-दफन उनके बेटे ओसामा ने किया। ओसामा शहाबुद्दीन के इकलौते संतान हैं। 25 साल की दहलीज पार कर चुके ओसामा शहाबुद्दीन की गद्दी को संभालने को तैयार हैं। वजह है कि उनकी मां हिना शहाब शहाबुद्दीन के जेल में रहते लगातार चुनाव लड़ती रहीं, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब जब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं हैं तो उनकी गैरहाजिरी में सभी राजनीतिक दलों के नेता ओसामा से ही मिल रहे हैं और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। सूत्रों की मानें तो ओसामा भी अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने को तैयार है। सीवान और आसपास के इलाकों में शहाबुद्दीन का असर रहा है। साथ ही मुसलमानों का भी समर्थन शहाबुद्दीन के साथ रहा है। ऐसे में ओसामा को मरहूम शहाबुद्दीन की सहानुभूति जरूर मिलेगी। अभी शहाबुद्दीन का परिवार आरजेडी से ताल्लुक रखता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ओसामा तेजस्वी यादव के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं।

वहीं राजपूत समुदाय से आने वाले बाहुबली नेता आनंद मोहन की उम्रकैद की सजा पूरी हो गई है। लेकिन, वह अभी जेल में हैं। कुछ दिनों में वो बाहर भी आ जाएंगे। आनंद मोहन की गैरहाजिरी में उनके बेटे चेतन आनंद ने आरजेडी से विधानसभा का टिकट लिया और शिवहर से जीत हासिल की। चेतन 29 साल के हो चुके हैं और विधानसभा में भी इनको तेज-तर्रार विधायक के रूप में जाना जाता है। आनंद मोहन के जेल रहते चेतन की पूरी परवरिश उनकी मां और पूर्व सांसद लवली आनंद ने किया। लवली आनंद खुद राजनीति से ताल्लुक रखती हैं तो बेटे को भी उन्होंने राजनीति का ककहरा सिखा दिया है। आनंद मोहन जेल से जब बाहर आएंगे तो चेतन आनंद विधिवत अपने माता-पिता की विरासत को अपने हाथ में लेंगे। आनंद मोहन का असर कोसी के क्षेत्र में रहा है, लेकिन उनका प्रभाव राजपूत समुदाय पर भी ठीक-ठाक रहा है। तभी तो चेतन आनंद कोसी छोड़ शिवहर से चुनाव जीत गए।

उधर, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव मधेपुरा और कोसी क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं। यादव जाति से आने वाले पप्पू यादव को 32 साल पुराने अपहरण के केस में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। जब पप्पू को जेल हुई तो उनके बेटे सार्थक रंजन ने पहली बार सोशल मीडिया पर आकर पप्पू यादव को लेकर लोगों से समर्थन मांगा। सार्थक रंजन दिल्ली से क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन, जब वो सोशल मीडिया में अपने पिता के लिए सामने आए तो यह तय हो गया कि वो आने वाले समय में राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं। जिस तरह से सार्थक ने सूझबूझ के साथ अपने पिता के पक्ष में बातें रखी थी उस बात पर राजनीति के पंडित उन्हें आने वाले दिनों का नेता मान रहे हैं। पप्पू यादव की पत्नी और पूर्व सांसद रंजीत रंजन की देखरेख में पले-बढ़े सार्थक में अपने माता-पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के सभी गुण देखे जा रहे हैं। अब देखना है कि पप्पू यादव और रंजीत रंजन अपने बेटे को राजनीति में कब लॉन्च करते हैं।

● **विनोद बक्सरी**

ये तो होना ही है

राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय बताते हैं कि तीनों बाहुबली नेताओं का अपने-अपने क्षेत्र में काफी प्रभाव रहा है। इसके अलावा ये अपनी जाति में भी काफी पैठ रखते हैं। ऐसे में इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी खेल ली है। अब जब लालू यादव ने अपनी विरासत अपने बेटों को सौंप दी है और रामविलास पासवान ने भी अपने बेटे चिराग को राजनीति की बागडोर सौंप दी थी तो ओसामा, चेतन और सार्थक भी इसके हकदार हैं। हालांकि इन तीनों ने अपने बाहुबल का असर अपने बेटों पर नहीं पड़ने दिया है, लेकिन इनकी राजनीति को उनके बाहुबल का फायदा जरूर मिलेगा। ये तीनों अलग-अलग जाति से आते हैं तो ये आपस में कभी टकराएंगे भी नहीं। हर राजनीतिक दल इन्हें अपने खेमे में रखना चाहेगा।

'अब तक हम यह सुनते आए हैं कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है। इसलिए जब लोगों को यह पता चला कि चीन थर्ड चाइल्ड पॉलिसी कानून लागू करने जा रहा है तो हैरान होना लाजिमी है। दरअसल, चीन की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। इसकी वजह यह है कि यहां के लोगों में शादी करने और बच्चे पैदा करने की रुचि कम होती जा रही है।'

थर्ड चाइल्ड पॉलिसी क्यों?

जनसंख्या के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है जबकि अमेरिका तीसरे नंबर पर है। जहां एक तरफ भारत में बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है वहीं चीन में तीन बच्चों के जन्म के लिए परमिशन मिल गई है। असल में चीन सरकार ने परिवार नियोजन के नियमों में ढील देने का ऐलान कर दिया है। यानी अब चीन में कोई भी कपल तीन बच्चे पैदा कर सकेगा। इसके पहले यहां दो बच्चे पैदा करने की ही इजाजत थी। चीन की आबादी इस समय 144 करोड़ है जबकि भारत की जनसंख्या 139 करोड़ है।

एक बात और, चीन ही पहला ऐसा देश है जहां जनसंख्या नियंत्रण को लेकर 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी जैसे कड़े कानून बनाए गए, यह काफी विवादों में भी रहा। यह कानून 37 सालों तक लागू रहा जिस वजह से यहां 40 करोड़ बच्चों के जन्म को रोक दिया गया। यानी जन्मदर काफी घट गया। वहीं 2016 में चीनी सरकार ने सेकंड चाइल्ड पॉलिसी का नियम लागू किया। जिसके तहत कोई भी कपल दो बच्चे पैदा कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी चीन के जन्मदर में कोई खास बदलाव नहीं आया।

यानी की दो बच्चे पैदा करने की छूट के बाद तो जन्मदर बढ़ना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिन पहले ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टियों की एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक बैठक हुई। जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे। इस कमेटी में यह बात सामने आई कि चीन में राष्ट्रीय जन्म दर लगातार कम हो रही है। इस समय जन्म दर 1 प्रतिशत के आसपास ही रह गई है। इसके अपोजिट यहां बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है, यानी चीन तेजी से बूढ़ा हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चीन ने थर्ड चाइल्ड पॉलिसी को लागू करने का ऐलान किया जो जल्द ही लागू कर दी जाएगी।

चलिए आपको आंकड़े के अनुसार समझाते हैं। दरअसल, चीन की जनसंख्या दर में काफी तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि यह अब तक की ऐतिहासिक गिरावट है और चीन की आबादी का पीक वर्ष 2025 से 2030 के बीच देखने को मिलेगा। यानी इस दौरान जनसंख्या 145 करोड़ से 150 करोड़ के बीच बनी रहेगी, लेकिन इसके बाद भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस समय चीन में जन्मदर सिर्फ 1.3 प्रतिशत रह गई है। जो चीन के लिए टेंशन की वजह है। असल में 2020 में जन्म दर में कमी की वजह से सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख बच्चों ने ही जन्म लिया, ऐसा 60 वर्षों में पहली बार हुआ।

किसी भी देश में आर्थिक तरक्की तभी संभव हो सकती है जब वहां के अधिक से अधिक लोगों की उम्र 15 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो। कामगारों की घटती संख्या भी चीन में थर्ड चाइल्ड पॉलिसी की वजह है। चीन में जवानों की संख्या कम हो रही है और बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा। चीन में जन्म दर कम होने की वजह से बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है। चीन अपने इस लक्ष्य में तो सफल रहा लेकिन वहां की सरकार को 2016 में यह एहसास हुआ कि अगर ऐसे ही जन्म दर घटती रही तो वह एक बूढ़ा देश बन जाएगा।

इस वजह से सेकंड चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां के लोगों की शादी और बच्चे पैदा करने में दिलचस्पी खत्म होती जा रही है। वहां के युवाओं में शादी ना करने का क्रेज हावी होते जा रहा है। बढ़ती उम्र की वजह से वहां के लोगों में रोजगार की भी समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए चीन ने तीसरे बच्चे की परमिशन दी है ताकि वहां जन्म दर में बढ़ोतरी हो सके। चीन हर मामले में काफी आगे है लेकिन कभी-कभी अपनी ही नीति का खुद ही शिकार हो जाता है, यह भी उनमें से एक ही है।

● राजेश बोरकर

चाइल्ड पॉलिसी को लेकर हमेशा सख्त रहा है चीन

चीन इस वक्त भी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और उसके बाद भारत का नंबर आता है। 1970 के दशक में आबादी की बढ़ती रफ्तार पर काबू पाने के लिए चीन के कुछ इलाकों में वन चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी। तब कपल को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की इजाजत दी जाती थी, बाद में ये नियम जब पूरे देश में फैला तो इसका उल्टा असर हुआ। चीन में बच्चों के पैदा होने की रफ्तार कम होने लगी। एक लंबे वक्त के बाद साल 2009 में चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव किया और चिन्हित लोगों को दो बच्चे करने की आजादी दी। दो बच्चे सिर्फ वही कपल कर सकते थे, जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे। साल 2014 तक इस नीति को भी पूरे चीन में लागू कर दिया गया था। अब साल 2021 में चीन ने एक बार फिर अपनी नीति बदली है और एक कपल को तीन बच्चे पैदा करने की इजाजत दी है। आंकड़ों के मुताबिक, 2010 से 2020 के बीच चीन में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार 0.53 प्रतिशत थी। जबकि साल 2000 से 2010 के बीच ये रफ्तार 0.57 प्रतिशत पर थी। यानी पिछले दो दशकों में चीन में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है।

अमेरिका-चीन में बढ़ता तनाव

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपनी गुप्तचर एजेंसियों को आदेश दिया है कि वो 90 दिनों में जानकारी जुटाए कि कोरोनावायरस इंसानों तक कैसे पहुंचा। कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद जो बाइडन ने एक रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया था जिसमें कुछ अंश ऐसे हैं जो वायरस के प्रसार पर संदेह पैदा करते हैं इसीलिए उन्होंने अमेरिकी गुप्तचर एजेंसियों से इस मसले की छानबीन का आदेश दिया है। राष्ट्रपति बाइडन के अनुसार, 'हमारी गुप्तचर एजेंसियां दो संभावनाओं के करीब पहुंची हैं, मगर किसी निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंच पाई हैं। गुप्तचर एजेंसियों के दो हिस्सों का मानना है कि यह जानवर से इंसानों में आया जबकि एक हिस्से का मानना है कि यह लैब से फैला है। ज्यादातर का मानना है कि किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सूचनाएं नहीं हैं जिसके लिए जांच जरूरी है।'

जैसा कि अपेक्षित है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के इस आदेश के बाद चीन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चीन के सरकारी प्रवक्ता के अनुसार यह सब अमेरिका द्वारा महामारी के रोकथाम और लापरवाही की अपनी नाकामी को छुपाने की यह अमेरिकी कोशिश है। इससे पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई मौकों पर चीन पर इस आशय का आरोप भी लगाया था और कोरोनावायरस को चीनी वायरस तक कह डाला था। तब इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के इस आदेश के बाद ट्रंप ने यह बयान दिया है कि 'उनके चीन के बारे में ख्याल बिल्कुल दुरुस्त थे। जिसकी अब बाइडन ने भी पुष्टि कर दी है।'

फिलहाल यह सवाल उठना लाजिमी है कि चुनाव से पूर्व जो बाइडन और उनकी समर्थक मीडिया लॉबी और वैज्ञानिकों ने कोरोनावायरस के कृत्रिम उत्पत्ति और चीन के वुहान लैब से उसके लीक होने की कहानी को साजिश सिद्धांत कहकर हवा में उड़ा दिए थे तो अब उसके संदर्भ में पुनः जांच के आदेश देने का क्या तुक है? इसके जवाब में ऐसा माना जा रहा है कि हाल में अमेरिकी मीडिया के एक हिस्से जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात को

'कोरोनावायरस के मद्देनजर अमेरिका फिर एक बार चीन के पीछे पड़ गया है और दोनों मुल्कों के बीच राजनीति तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की बातों के बाद चीन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चीन के सरकारी प्रवक्ता के अनुसार यह सब अमेरिका द्वारा महामारी के रोकथाम और लापरवाही की अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश है।'

लेकर राष्ट्रपति बाइडन की आलोचना की है कि वह इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर नहीं है।

अमेरिकी मीडिया के अनुसार चीन की भूमिका को सिरे से नकार नहीं सकते हैं। साथ ही कई ऐसी रिपोर्ट भी आई जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि दिसंबर 2019 से पूर्व वुहान की लैब के कई कर्मी संक्रमित हुए जिनके लक्षण कोरोना से मिलते हैं। इसके अलावा अमेरिका के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाऊची ने वायरस की उत्पत्ति पर दिए गए अपने पुराने बयान से मुकरते हुए कहा कि चीन में जो कुछ हुआ, उसकी जांच जारी रखी जानी चाहिए। जबकि पूर्व में डॉक्टर फाऊची द्वारा वायरस के कृत्रिम रूप से किसी लैब में उत्पत्ति की बात को नकार दिया गया था। इस संदर्भ में यह भी ध्यान देने वाली बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहा गया था कि ये नहीं पता लगाया जा सकता कि चीन में इंसान इस वायरस से कैसे संक्रमित हुए लेकिन सभी सुबूतों से इशारे मिलते हैं कि ये वायरस जानवरों से आया और इसका निर्माण नहीं किया गया।

ये संभवतः चमगादड़ों में पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रिपोर्ट की अमेरिका ही नहीं बल्कि अन्य देशों द्वारा आलोचना की गई और यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि यह रिपोर्ट चीन के दबाव में तैयार की गई है। कुल मिलाकर इस समूचे घटनाक्रम के बाद कोरोनावायरस की उत्पत्ति का सवाल चीन और अमेरिका के बीच तनाव का विषय बन गया है। अब यह देखना होगा कि अमेरिकी गुप्तचर एजेंसियां 90 दिन में क्या रिपोर्ट देती हैं? क्या उन्हें कोई नए तथ्य मिलते हैं? अथवा चीन जैसे अमेरिका पर आरोप लगा रहा है यह सिर्फ अमेरिका द्वारा ध्यान भंग करने का और महामारी के नियंत्रण में अपनी कमी को ढांकने का स्टंट मात्र है। परिणाम चाहे जो हों उसके अपने कूटनीतिक मर्म होंगे। जिसका परिणाम हमें निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। वैसे भी साजिश सिद्धांत के पैरोकार कोरोना की इस वैश्विक महामारी को शुरुआत से ही बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों के बड़े खेल की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे जुमले भी फिट किए जा रहे हैं।

● कुमार विनोद

चीन में अकेले व्यवस्था को बदलने की ताकत

अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कहा कि चीन अकेला ऐसा देश है जो अमेरिका और उनके सहयोगी देशों से समर्थित सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से व्यवस्था की नियमावली को बदल सकता है। ब्लिंकन ने कांग्रेस सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि चीन के साथ अमेरिका का रिश्ता बेहद जटिल और परिणामस्वरूप मुश्किल भरा रहने वाला है। उन्होंने कहा कि चीन एक अकेला ऐसा देश है जो अमेरिका की स्थापित व्यवस्था को कायम रखने में मददगार है। इससे इतने सालों में सुरक्षा और समृद्धि बढ़ी है। वर्ष 2022 के बजट की सीनेट की कमेटी की सुनवाई चल रही है।

क्या ऐसा भी होता है...?

हमारे भीतर का वायरस

आस्था और अंधविश्वास में अंतर होता है, लेकिन अंधविश्वास का यह वायरस अपने देश से खत्म ही नहीं होता। कोरोनाकाल में भी महिलाओं से अपराध कम नहीं हुए। कोरोना पॉजिटिव के साथ रेप, पति के साथ अस्पताल पहुंची महिला के साथ छेड़खानी। फोन कॉल पर ठगी, ऑक्सीजन और एंबुलेंस के नाम धोखाधड़ी खूब चली। अस्पतालों में भी लापरवाही के मामले सामने आए। समझ नहीं आता कि जब गंगा में लाशें बह रही थीं। जब रेत और मिट्टी में शव दफनाए जा रहे थे, तब शवों से कफन चुराने वाले वे लोग कौन थे। आपकी बात सही है सरकार नाकाम रही, कोरोनावायरस के रोकथाम में फेल रही, लेकिन इस वायरस को फैलाने वाले लोगों ने भी कोरोनाकाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार को कोसने के लिए आप आजाद हैं लेकिन इनकी गलतियों पर पर्दा कौन डालेगा?

सास-बहू की नोंक-झोंक तो पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन ये वाला किस्सा एकदम अलग है। सुनकर कितना अच्छा लगता है कि सास ने बहू को गले लगाया लेकिन जिस वजह से गले लगाया वो काफी अजीब है। आज कल तो टीवी सीरियल में भी सास के कैरेक्टर को पॉजिटिव दिखाते हैं। कई घरों में सास अपनी बहू को बेटी की तरह ही प्यार करती है, लेकिन इस खबर के बाद आपको लगेगा कि आज भी ऐसी सास मौजूद हैं जो बहू को इस हद तक प्रताड़ित कर सकती हैं कि उसकी जान पर बन आए। यानी टीवी सीरियल वाली वैम्पायर सास की प्रजाति आज भी पाई जाती हैं। चलिए बताते हैं कि माजरा क्या है?

असल में मामला कोरोना से जुड़ा हुआ है। तेलंगाना के सोमरीपेटा गांव की एक महिला कोरोना पॉजिटिव थी। इसलिए घरवालों ने उसे एक कमरे में आइसोलेट कर दिया था। उससे घर के सभी सदस्य दूरी बनाते थे। वह इस बात से परेशान हो गई थी कि कोरोना संक्रमित होने के बाद उससे कोई मिलजुल नहीं रहा है। उसके पोता-पोती भी पास में नहीं जाते थे और उसे खाना भी अलग दिया जाता था। वह अकेले कमरे में रहने की वजह से नाराज थी। इसलिए उसने अपनी बहू को जबरदस्ती गले लगा लिया ताकि वो भी पॉजिटिव हो जाए।

परिवार वाले इसलिए दूरी बना रहे थे ताकि वे भी संक्रमित न हो जाएं लेकिन यही बात कोरोना पॉजिटिव महिला को नागवार गुजरी। दरअसल, कोरोनाकाल में अब तक करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं ज्यादातर लोग डॉक्टर की सलाह को फॉलो कर अपने घर में ही आइसोलेट होकर ठीक हो चुके हैं। यह बात इस महिला को समझ नहीं आई और जब बहू कोरोना संक्रमित हो गई तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद बहू की बहन उसे राजन्ना सिरसिल्ला जिले के तिम्मापुर मायके ले गई, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बहू ने बताया कि मेरी सास इस वजह से परेशान थी कि उन्हें अलग रखा जाता है। उन्होंने मुझे यह कहते हुए जबरन गले लगाया कि 'तुझे भी कोरोना संक्रमित होना चाहिए। क्या मेरे मरने के बाद तुम सब सुखी रहना चाहते हो?' सोचिए घर में बाकी भी सदस्य थे, लेकिन सास को बहू से दिक्कत क्या थी। आखिर एक महिला दूसरी से जलती क्यों है। क्या इसका जवाब है किसी के पास। क्या ये जन्मजात होता है या फिर यह स्त्री के स्वभाव का हिस्सा है?

माना जाता है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियां जलन यानी ईर्ष्या जैसी चीजों के बारे में ज्यादा सोचती हैं। यही नहीं, वे अपनी फ्रेंड्स से कॉम्पिटीशन करने में भी नहीं हिचकिचाती। उनके लिए लुक, मेकअप और यहां तक कि लाइफ पार्टनर भी कंपटीशन का हिस्सा बन जाते हैं। महिलाएं अपनी इस आदत की वजह से अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी कंपेयर करती हैं। किसी प्रतिद्वंदी के हस्तक्षेप से महिलाओं के रिश्ते में खटास पैदा होनी शुरू हो जाती है। यह ईर्ष्या महिलाओं में इसलिए हावी हो जाती है क्योंकि वो वह भी पाना चाहती है जो सामने वाले में है। अक्सर सास-बहू एक-दूसरे को अपना कंपटीटर मान लेती हैं और बीच में फंस जाता है बेटा। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। इम्तिहान के समय अगर एक लड़की दूसरी लड़की से किसी सवाल का जवाब पूछती है तो वह भले डायरेक्ट मना ना करे लेकिन बताएगी भी नहीं। उसे ऐसा लगेगा कहीं मेरी सहेली का नंबर मुझसे अधिक ना आ जाए।

वहीं अगर किसी लड़के से मदद मांगते हैं तो वह शायद जवाब दे भी दे। ऐसा शायद कई लड़कियों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। ऐसा भी नहीं है कि महिलाएं आपस में मिलजुलकर नहीं रहतीं, लेकिन जलन की भावना शायद उनके नेचर का एक हिस्सा है। इस सास-बहू की कहानी से तो यही लगता है। वरना कौन नहीं चाहेगा कि उसके गुजर जाने के बाद उसका परिवार सुखी रहे। उधर कोरोना के इलाज के लिए लोगों ने इतने तरह का अंधविश्वास फैलाया कि विज्ञान भी शर्मा गया। कभी गोमूत्र पार्टी तो कभी गोबर स्नान। कहीं कोरोना को देवी माई बताकर पूजा गया तो कहीं कोरोनासुर बताकर भस्म किया गया। आपको केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का नारा 'गो कोरोना गो' तो याद ही होगा। बेचारे नारा देने वाले मंत्रीजी खुद पॉजिटिव हो गए। कहीं भीड़ में बिना मास्क लगाए कलश यात्रा निकाली गई तो कहीं पानी पिलाकर इसका इलाज खोजा गया, लेकिन हार मानकर अंत में सबने विज्ञान की ही शरण ली।

● ज्योत्सना अनूप यादव

पांडवों से सीखें जिंदगी जीने और जीत के सूत्र

पांडवों ने जब भी अपने से बड़े या छोटों से बात की तो संयमित भाषा का ही प्रयोग किया। उन्होंने अपनी ओर से कभी किसी को कटु वचन नहीं कहे, बल्कि जब भी उन्हें कौरवों की ओर से कटु वचन सुनने को मिले तो उसका जवाब भी उन्होंने संयमित रहकर ही दिया। उन्होंने कभी भी कौरवों की भाषा को उपयोग नहीं किया।

पहले हमने बताया कि किसी तरह श्रीकृष्ण और श्रीमद्भागवत गीता से मैनेजमेंट के गुण कैसे सीखें। इस बार पढ़िए कि किस तरह सीखें आप महाभारत के पांडवों से जिंदगी जीने का गुर या सूत्र। दरअसल, महाभारत हमें बहुत कुछ सिखाती है परंतु हम उससे कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। महाभारत में सीखने के लिए काफी कुछ है। जिसमें घटित घटनाक्रम को यदि वर्तमान में संदर्भ के रूप में देखें, तो काफी कुछ समस्याओं का समाधान हम स्वयं ही निकाल सकते हैं। महाभारत की हर कहानी कुछ न कुछ सीख देती है। आओ अब सीखें जिंदगी का मैनेजमेंट।

पारिवारिक एकता: आपने पांडवों का जीवन तो देखा ही होगा। पांचों पांडवों में एक-दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और एकजुटता थी। पांडव जहां जाते थे साथ रहते थे। यही कारण था कि वे 100 कौरवों को पराजित कर सके।

सभी के प्रति विनम्रता: पांचों पांडव अपने से बड़ों के प्रति विनम्र थे। वे कभी भी अपने से बड़े को अपमानित नहीं करते थे। उनमें घमंड नहीं था और ना ही वे खुद को दूसरों से शक्तिशाली मानकर व्यवहार करते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को अपने पिता समान ही दर्जा दिया और भीष्म पितामह के समक्ष सदा सिर झुकाकर ही बात की। उन्होंने द्रोणाचार्य के प्रति अपनी भक्ति को भी प्रदर्शित किया और श्रीकृष्ण की शरण में रहकर सदा उनकी आज्ञा का पालन किया।

विषम परिस्थिति को बनाएं अपने अनुकूल: जब पांडवों को वनवास हुआ तो उन्होंने वनवास की विषम परिस्थिति में भी समय को व्यर्थ नहीं गवांया। इस दौरान उन्होंने जहां अपने लिए राज समर्थन बढ़ाया, वहीं उन्होंने तप और ध्यान करके खुद को शक्तिशाली भी बनाया। इसी वनवास में उन्हें वह सबकुछ हासिल हुआ जो महल में रहकर कदापि नहीं हासिल हो सकता था। इसीलिए यह जरूर जानें कि परिस्थिति कैसी भी हो परंतु उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है।

सकारात्मक सोच से लोहा भी बन जाता है सोना: जब कौरवों और पांडवों के बीच राज्य का बंटवारा हुआ तो कौरवों की ओर से धृतराष्ट्र ने पांडवों को वीरान पड़ा खांडववन जंगल दे दिया, परंतु पांडवों ने इसे सकारात्मक रूप से लिया और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए भगवान श्रीकृष्ण की इच्छा से उन्होंने जंगल में इंद्रप्रस्थ जैसा सुंदर नगर का निर्माण कर दिया।

संयमित भाषा का प्रयोग: पांडवों ने जब भी अपने से बड़े या छोटों से बात की तो संयमित भाषा का ही प्रयोग किया। उन्होंने अपनी ओर से कभी किसी को कटु वचन नहीं कहे, बल्कि जब भी उन्हें कौरवों की ओर से कटु वचन सुनने को मिले तो उसका जवाब भी उन्होंने संयमित रहकर ही दिया। उन्होंने कभी भी कौरवों की भाषा को उपयोग नहीं किया।

धैर्य और साहस का प्रयोग: पांडवों ने विषम परिस्थिति में भी हमेशा धैर्य के साथ काम लिया और साहस के साथ उसका मुकाबला किया। चाहे वह लक्ष्यागृह से बचना हो या युद्ध में कौरवों के द्वारा उनकी सेना के हजारों सैनिकों का एक ही दिन में सफाया करना हो। कौरवों के समक्ष कमजोर होने के बावजूद उन्होंने धैर्य और साहस से युद्ध को जीता।

गलतियों से सीखा: पांडवों ने अपनी गलतियों से सीखा और उस सीख को कभी भूले नहीं। उन्होंने कभी भी गलतियों को दोहराया नहीं और हमेशा नए प्रयोग किए।

मन में नहीं रखा कभी भ्रम: यदि आपके मन में भ्रम या विरोधाभाष होगा तो आपमें निर्णय लेने की क्षमता का पतन हो जाएगा। पांडवों के मन में कभी भी किसी भी बात को लेकर भ्रम नहीं रहा। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो युधिष्ठिर ने रथ से उतरकर यह कहा कि यह धर्मयुद्ध है। इस युद्ध में एक और धर्म है तो दूसरी और अधर्म है। निश्चित ही किसी एक ओर धर्म है। जिन्हें यह लगता है कि हमारी ओर धर्म है उनके लिए अभी भी अवसर है कि वे हमारी ओर आ जाएं और मेरी सेना में जिन्हें लगता है कि कौरवों की ओर धर्म निवास करता है वे कौरवों की ओर चले जाएं क्योंकि हम चाहते हैं कि युद्ध में अपना पक्ष स्पष्ट हो, जिससे किसी भी प्रकार का भ्रम ना रहे।

सदा सत्य के साथ रहो: कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानीजन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा हैं, ज्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है, जहां ईश्वर है और ईश्वर हमेशा वहीं है, जहां सत्य है इसलिए सत्य का साथ कभी न छोड़ें। अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े करो। पांडव हमेशा सत्य के साथ ही रहे थे।

अच्छे दोस्तों की कद्र करो: ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्रीकृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्रीकृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता, तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता।

● **ओम**

कविता

पवन, सलिल, भू, गगन, अनल ये,
पंचतत्व कहलाते हैं।
सृष्टि सृजन के कारक ये ही,
पर्यावरण बनाते हैं।
कभी स्वच्छ थे पवन और जल,
शोर कहीं ना होता था।
रहती ऋतु अनुकूल कृषक तब,
खेत समय पर बोता था
आज अवर्षा अति वर्षा की,
घोर त्रासदी आती है।
कभी अचानक ठंडी, गरमी,
कभी उमस बढ़ जाती हैं।
वायु प्रदूषण नहीं नियंत्रित,
स्वच्छ हवा का संकट है।
बिषम परिस्थिति आज विपुल है,
मानो अब प्रलय निकट है।
तापमान बढ़ रहा निरंतर,
हिमगिरि वर्फ पिघलती है।
प्रकृति आपदा हुई निमंत्रित,
प्रस्थिति नित्य बदलती है।
उद्वेलित हो रहे सिंधु सब,
चक्रवात नूतन उठते।
बदल रहे ऋतु चक्र सभी अब,
मापदंड हैं नित मिटते।
नहीं लगाते वृक्ष आज हम,
जंगल जितने काट रहे।
अपने प्रिय जन, परिजन सबको,
नित्य हलाहल बांट रहे।
जनसंख्या पर नहीं नियंत्रण,
प्रतिदिन बढ़ती जाती है।
हृदय और आवास आयतन,
नित्य अल्पता आती है।
कोरोना सी महामारियां,
हर वर्ष नहीं आती थी।
दवा, चिकित्सा की कमियां,
ऐसे नहीं बताती थीं।
मानव अब भी नहीं आचरण,
यदि परिवर्तित कर पाया।
असमय काल ग्रास बनने का,
सब पर संकट है छाया।
पर्यावरण दिवस पर मित्रों,
हम सब यह संकल्प करें।
वृक्षारोपण कर बहुसंख्यक,
सकल प्रदूषण अल्प करें।

***

स्वरचित
डॉ आर पी तिवारी
उज्जैन
9425174459

भविष्यवाणी

खलिहान में दंवरी शुरू थी। हीरा और मोती लगातार पुआल पर गोल-गोल चल रहे थे और उनके खुरों से कुचलकर पुआल से अनाज के दाने अलग हो रहे थे। कठिन श्रम करते हुए सूखे पुआल को देखकर मोती की भूख बढ़ गई थी लेकिन वह मजबूर था। मालिक ने उनके मुंह को जालीदार ढक्कन से बंद कर रखा था। उसकी मजबूरी को महसूस कर हीरा ने उसे आश्वासन दिया, मायूस न हो मोती! भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। एक दिन वह भी आएगा जब सब कुछ रहकर भी इंसान को अपनी कारगुजारियों की वजह से खुद ही अपना मुंह इसी तरह बंद करने को मजबूर होना पड़ेगा, तब उसे अपनी गलती का अहसास होगा।

आखिर हीरा की भविष्यवाणी सच साबित हुई और आज महामारी के दौर में गांव में सभी इंसानों को मास्क लगाकर घूमते देख हीरा ने जोर से मोती से कहा, देखा! मैं कहता था न, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं!

– राजकुमार कांदु

अपना-पराया

जैसे ही मैंने डोरबैल बजाई भाभी दरवाजे पर थी। कोरोना से सावधानी रखते हुए सम्मान पूर्वक नमस्ते कर अंदर ले गई। चाय पीते हुए मैंने कहा- भाभी अभी पहले हास्पिटल ही चलते हैं। पिता जी की तबीयत न जाने कैसी होगी। मन घबरा रहा है।

भाभी ने सहमति में सिर हिलाया। और गाड़ी की चाबी उठा ली। कहा तुम्हारे भैया तो रात से वहीं हैं और मम्मी जी को नाश्ता देकर मैं छोड़ आई थी। पिता जी के स्वास्थ्य में सुधार नहीं है, इसलिए तुम्हें बुला लिया। आगे का ट्रीटमेंट क्या होगा आज बताएंगे।

मैं गुमसुम बैठी किसी तरह अपनी भावनाओं को संयत कर रही थी। मुझे देखकर पापा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन कमजोरी का भाव स्पष्ट झलक रहा था। मैंने हौसला बढ़ाते हुए कहा- चिंता मत कीजिए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं वापस नही जाऊंगी। कह कर भैया को साथ लेकर डॉक्टर के परामर्श कक्ष में चली गई।

डॉक्टर ने बताया कि आप लोग जल्दी ब्लड का इंतजाम कर लीजिए। बाईपास सर्जरी करनी होगी। डोनर से ही लेना होगा क्योंकि उनके ब्लड ग्रुप का खून हॉस्पिटल में नहीं है। उनके लिए दूसरा अटैक घातक सिद्ध हो सकता है। चिंतित मुद्रा में हम बाहर आ गए। भैया ने बताया कि उनका और भाभी का ब्लड ग्रुप मेल नहीं करता। मम्मी को डायबिटीज है अत: अब तुम अपना टेस्ट करवा लो। मेरा और भैया का तो एक ही ब्लड ग्रुप था। कमरे में आकर मैंने कहा- भैया आप रात से यहीं हैं, थक गए होंगे। चिंता मत कीजिए। आप और भाभी घर जाइए। डॉक्टर से कहिए कि कल आप्रेशन कर लें, ब्लड का प्रबंध हो जाएगा।

कैसे होगा मैं और शुभ्रा अपने सभी परिचितों, मित्रों से पूछ चुके हैं।

मैं करती हूं कुछ, आप डॉक्टर से कल के लिए कंफर्म कर लीजिए और घर जाइए। कहकर मैं फोन लगाने में व्यस्त हो गई।

शाम को ठीक 7 बजे सुधीर घर पहुंच गए आते ही बोले विकास भैया चिंता न करें। मेरा ब्लड ग्रुप पापा के ब्लड ग्रुप से मेल खाता है। आप्रेशन हो जाएगा। ब्लड मैं दूंगा।

सभी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान की यह कैसी लीला है कि एक पराए कुल के व्यक्ति का खून मिल रहा है और अपने कुल का नहीं मिला। शायद इसीलिए कहते हैं कि जोड़ियां भगवान ही तय करता है। हम तो केवल मात्र माध्यम हैं। ऐसे अवसरों पर ही अपने-पराए की पहचान होती है। दामाद को पराए कुल का समझते हैं। भगवान की सृष्टि रहस्यमयी है।

– डॉ. मनोरमा शर्मा

आईपीएल की राह में चुनौतियां

कोरोना की दूसरी लहर के चलते बीती 4 मई को सस्पेंड हुए इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन पर लगा सवालिया निशान अब हट चुका है। बीसीसीआई की मीटिंग में आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों का आयोजन यूएई में करवाने का फैसला लिया गया है। बीसीसीआई ने बचे हुए 31 मैचों को सितंबर-अक्टूबर में पूरा करने की घोषणा कर दी है। हालांकि, बीसीसीआई ने अभी आईपीएल 2021 की तारीख पर फैसला नहीं किया है। आईपीएल के सस्पेंड होने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इसका आयोजन यूएई में किया जा सकता है। दरअसल, बीते साल भी कोरोना महामारी के दौरान आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में ही हुआ था। खैर, बीसीसीआई का इंडियन प्रीमियर लीग को पूरा कराने के ऐलान के साथ क्रिकेटप्रेमियों को मनोरंजन का डोज मिलना तय माना जा रहा है। लेकिन, अभी भी आईपीएल की राह में कई कांटें हैं, जिनसे बीसीसीआई को बचना होगा।

इस साल भारत में अक्टूबर-नवंबर में टी-20 विश्व कप 2021 खेला जाना है। कोरोना की वजह से टी-20 विश्व कप के आयोजन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अक्टूबर-नवंबर में हालात कैसे होंगे, इसका अंदाजा अभी से नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन, एक बात तय है कि आईपीएल 2021 के पहले चरण में 'बायो बबल' टूटने की वजह से टूर्नामेंट में शामिल होने वाली अन्य देशों की टीमों में डर जरूर रहेगा। बीसीसीआई अपनी ओर से बायो बबल को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करेगी, लेकिन आईपीएल 2021 के पहले चरण की तरह इसके भी टूटने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

बीसीसीआई की मीटिंग में भारत में होने वाले टी-20 विश्व कप को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से भी बात करने की बात कही गई है। बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा है कि टी-20 विश्व कप 2021 की मेजबानी पर उचित फैसला लेने के लिए आईसीसी से समय बढ़ाने का अनुरोध किया है। दरअसल, टी-20 विश्व कप 2021 के रूप में आईपीएल 2021 के सामने एक बड़ी दीवार खड़ी है। बीसीसीआई के लिए ये दोनों ही टूर्नामेंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर टी-20 विश्व कप 2021 की मेजबानी और आईपीएल 2021 में कोई भी बीसीसीआई के हाथ से निकलता है, तो उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

आईसीसी अगर टी-20 विश्व कप 2021 के आयोजन को आगे बढ़ा देता है, तो बीसीसीआई के लिए कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन, भारत में कोरोना महामारी को देखते हुए इसे भी यूएई में आयोजित किया जा सकता है। यूएई में दुबई, आबु धाबी और शारजाह के स्टेडियम में ही आईसीसी टी-20 विश्व कप 2021 का आयोजन होगा। लेकिन, इन स्टेडियम पर पहले से ही आईपीएल 2021 के बचे हुए 31 मैच खेले जा चुके होंगे। जिसकी वजह से इन स्टेडियम में मौजूद पिचों की फिटनेस को सुधरने में कुछ समय लगेगा। लेकिन, टी-20 विश्व कप अक्टूबर महीने के बीच में शुरू होगा। इस हिसाब से टी-20 विश्व कप के आयोजन में मुश्किल आ सकती है। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड होने के बाद भी बीसीसीआई को आईसीसी के फैसले का ही इंतजार करना होगा।

आईपीएल का सितंबर-अक्टूबर में आयोजन होगा और इस दौरान 28 अगस्त से कैरेबियन प्रीमियर लीग 2021 भी शुरू हो जाएगी। सीपीएल 2021 का फाइनल 19 सितंबर को खेला जाएगा। अगर आईपीएल की शुरुआत 19 सितंबर से पहले होती है, तो कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले कई खिलाड़ी आईपीएल के शुरुआती दिनों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उन्हें क्वारैंटीन नियमों का पालन करना पड़ेगा। वेस्टइंडीज के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल क्रिस ग्रेल, कीरोन पोलार्ड, शिमरॉन हेटमायर, निकोलस पूरन, आंद्रे रसेल के बिना आईपीएल फीका नजर आएगा। वहीं, कैरेबियन प्रीमियर लीग में फाफ डु प्लेसिस, इमरान ताहिर, क्रिस मॉरिस जैसे खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे, जो आईपीएल की टीमों में खेल रहे हैं। इन खिलाड़ियों को आईपीएल में कैसे खिलाया जाएगा, ये बीसीसीआई के लिए एक बड़ी चिंता का कारण हो सकता है।

कैरेबियन प्रीमियर लीग से इतर आईपीएल में इंग्लैंड के खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी भी एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। आईपीएल 2021 में कुल 14 इंग्लिश खिलाड़ी 6 टीमों में खेल रहे हैं। हालिया सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ इंग्लैंड टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर एश्ले जाइल्स ने कहा है कि आईपीएल के लिए इंग्लिश खिलाड़ियों को रिलीज नहीं किया जाएगा। दरअसल, इंग्लैंड को भारत के साथ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, जो 14 सितंबर को खत्म होगी। भारत के साथ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद इंग्लैंड की टीम को बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड के अलावा न्यूजीलैंड को भी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलनी है। इस हिसाब से आईपीएल में कई दमदार विदेशी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

● **आशीष नेमा**

वेन्यू से होगी दिक्कत

कोरोना महामारी की वजह से दुनियाभर में हालात काफी खराब हैं। इसका असर टीमों के साथ ही खिलाड़ियों पर भी पड़ा है। बायो बबल की वजह से खिलाड़ियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगे होते हैं। जिसकी वजह से खिलाड़ियों में थकावट काफी बढ़ जाती है। इसका असर भी आईपीएल 2021 पर पड़ सकता है। वहीं, कैरेबियन प्रीमियर लीग और अन्य सीरीज खेलकर आईपीएल में जुड़ने की कोशिश करने वाले खिलाड़ियों को यूएई में क्वारैंटीन नियमों का पालन करना पड़ेगा। यूएई के देशों में क्वारैंटीन के अलग-अलग नियमों की वजह से बीसीसीआई के सामने खिलाड़ियों को आईपीएल शुरू होने से पहले ही इकट्ठा करने की चुनौती होगी। आईपीएल का आयोजन जितना सरल लग रहा है, उतना होने वाला नहीं है।

16 साल की उम्र में शिल्पा शेट्टी ने मॉडलिंग से शुरू किया था कैरियर

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का जन्म 8 जून, 1975 को मेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। शिल्पा आज एक्ट्रेस के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेस वुमन के तौर पर भी जानी जाती हैं।

शिल्पा ने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी। कम ही लोग जानते होंगे कि तब उनकी उम्र केवल 16 साल थी, जब 1991 में उन्होंने पहली बार लिम्का ब्रांड के लिए मॉडलिंग की थी।

शिल्पा शेट्टी की जिंदगी के दो विवाद हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। एक जब वे साल 2007 में रियलिटी शो बिग ब्रदर की कंटेस्टेंट थीं, तब हॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल जेड गुडी ने उन पर नस्लीय टिप्पणी की थी। हालांकि, शिल्पा ने यह शो जीतकर विदेश में भारत का परचम फहराया था। दूसरा विवाद शिल्पा के साथ तब जुड़ा जब 2007 में ही मुंबई में आयोजित एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेर ने उन्हें सरेआम बाहों में भरकर किस किया। इसके बाद शिल्पा को काफी क्रिटिसाइज किया गया। वैसे, जब आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स पर फिक्सिंग के आरोप लगे, तब भी शिल्पा का नाम खूब उछला था, क्योंकि वे इस टीम की को-ऑनर हैं।

शिल्पा ने 22 नवंबर, 2009 को लंदन बेस्ड बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी कर ली। राज कुंद्रा तलाकशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम कविता था। कविता और राज की एक बेटी भी है, जिसका नाम डेलिना कुंद्रा है। अब शिल्पा और राज दो बच्चों के पेरेंट्स बन चुके हैं, बेटे का नाम उन्होंने विवान राज कुंद्रा रखा है जबकि बेटी का नाम समीषा है जिसका जन्म सरोगेसी से हुआ है।

डेब्यू के वक्त 86 किलो की थीं सोनम कपूर, सांवरिया के लिए घटाया 30 किलो वजन

बॉलीवुड स्टार सोनम कपूर की गिनती ऐसी एक्ट्रेसेस में होती है, जिन्हें डेब्यू फिल्म में तो नाकामी मिली, लेकिन बाद में वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गईं। 9 जून 1985 को अनिल कपूर और सुनीता के यहां जन्मी सोनम ने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'सांवरिया' से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। ये फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी। इसके लिए उन्हें अपना वजन करीब 30 किलो कम करना पड़ा था क्योंकि संजय लीला भंसाली ने उन्हें वजन कम करने के लिए कहा था। बता दें, जब वे सिंगापुर से एक्टिंग का कोर्स करने के बाद भारत लौटी थीं, तब उनका वजन 86 किलो था। रोचक बात है कि एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले सोनम कपूर ने संजय लीला भंसाली के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। फिल्म थी 'ब्लैक'। इसी दौरान भंसाली ने उन्हें अपनी अगली फिल्म 'सांवरिया' में कास्ट करने की इच्छा जताई थी। सोनम कपूर ने 8 मई 2018 को दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन आनंद आहूजा से लव मैरिज की थी।

बॉबी से रातोंरात स्टार बन गई थीं डिंपल, राजेश खन्ना के कहने पर छोड़ी थी एक्टिंग

बॉलीवुड एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया 64 साल की हो गई हैं। पर्दे पर हीरोइन की परम्परागत इमेज को बदलकर नया ट्रेंड सेट करने वाली एक्ट्रेस डिंपल का जन्म 8 जून 1957 को एक गुजराती परिवार में हुआ। अपनी खूबसूरती, आकर्षक हेयरस्टाइल और दमदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली डिंपल ने फिल्म बॉबी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। 1973 में प्रदर्शित इस फिल्म से वो रातों-रात स्टार बन गई थीं। डिंपल ने अपने सिने कैरियर में सागर, जांबाज, कब्जा, रामलखन, खून का कर्ज, अजूबा, रुदाली, क्रांतिवीर, मृत्युदाता, दबंग और कॉकटेल जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का हुनर दिखाया। राजेश और डिंपल की शादी 1973 में हुई। उस वक्त डिंपल महज 16 साल की थीं, और वो काका से उम्र में बहुत छोटी थीं। इन दोनों की दो बेटियां ट्विंकल और रिंकी खन्ना हैं। राजेश-डिंपल की शादीशुदा जिंदगी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। राजेश-डिंपल ने कुछ समय तो अच्छा गुजारा, लेकिन फिर दोनों में तकरार शुरू हो गई।

...नफे का पड़ोसी धर्म

नफे टीवी पर कोरोना महामारी और उससे पीड़ित लोगों की खबरों को सुनते-सुनते जब ज्यादा दुखी हो गया तो उसने टीवी बंद करके रिमोट को एक तरफ फेंका और अपना सर पकड़कर विचारमग्न हो सोफे पर बैठ गया। तभी उसकी पत्नी भागते हुए आई और चुगलाए अंदाज में बोली।

पत्नी - सुनते हो जी?

नफे - सुनाओ जी!

पत्नी - अपने पड़ोसी जिले भाई साहब के पूरे परिवार को कोरोना हो गया है। डॉक्टर ने उन्हें अपने घर में ही 14 दिन क्वारैंटाइन होने के लिए कहा है।

नफे - अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं जिले को फोन कर पूछता हूं कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो पहुंचा देंगे।

पत्नी - पागल मत बनो। पता भी है कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है। अगर लग गई तो फिर भगवान ही मालिक है। आप उनसे दूर ही रहना। समझे कि नहीं?

नफे - बहुत अच्छी तरह समझ गया। जिले की पत्नी और तुम तो बहुत अच्छी सहेलियां हो। आज जब दोस्ती निभाने का समय आया तो कृतघ्नता दिखाने लगीं।

पत्नी - अरे, दोस्ती, रिश्ते-नाते बाद में निभा लेंगे। अभी तो बस अपनी जान बच जाए।

नफे - तुम्हारा मतलब है कि जिले के परिवार की मदद करके हम सब मर जाएंगे।

पत्नी - ओहो, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे।

नफे - मैं तुम्हें और तुम्हारी नीयत को अच्छी तरह समझ रहा हूं। ठीक है मैं जिले के परिवार की कोई मदद नहीं करूंगा।

धीरे-धीरे समय बीता और नफे का पड़ोसी जिले और उसका परिवार क्वारैंटाइन का टास्क भली-भांति पूरा करके स्वास्थ्य के अखाड़े में दंड पेलने लगा। कुछ दिन बाद नफे की पत्नी उसके पास आई और बेजान आवाज में बोली।

पत्नी - सुनते हो जी?

नफे - सुनाओ जी!

पत्नी - हम लोगों ने जो कोरोना का टेस्ट करवाया था न।

नफे - हां तो?

पत्नी (सुबकते हुए) - उस टेस्ट में हम सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

नफे - (धीमे से) ओहो, तुम जैसी नेगेटिव नारी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई।

सूबे की पत्नी - आसमान सिर पर न उठाऊं तो और क्या करूं। तुम अपनी आदतानुसार नफे भाई साहब से गुटर-गूं किए बिना मानोगे नहीं। उस गुटर-गूं के बाद कोरोना तुम्हारे संग आकर अपने पूरे परिवार से गुटर-गूं करेगा।

पत्नी - कुछ कहा आपने?

नफे- मैं कह रहा था कि अब 14 दिन घर से बाहर निकलने से छुट्टी।

पत्नी - हां, अब अपने पूरे परिवार को 14 दिन तक क्वारैंटाइन रहना पड़ेगा।

नफे - हां, वो तो रहना ही पड़ेगा।

पत्नी - पर इतने दिन हमें जरूरत का सामान कौन लाकर देगा?

पति - अपना पड़ोसी जिले लाकर देगा।

पत्नी - पर जब उनका परिवार क्वारैंटाइन हुआ था। तब हमने तो उसकी कोई मदद नहीं की थी।

नफे - किसने कहा कि मदद नहीं की थी। तुम कृतघ्न हो गईं पर मैं नहीं हुआ। मैंने जरूरत पड़ने पर जिले के परिवार को सभी जरूरी सामान उपलब्ध करवाया था। अब मदद करने की बारी उसकी है।

पत्नी - इसका मतलब है कि आपने मेरी बात न मान कर जिले भाई साहब के परिवार की मदद की थी।

नफे - हां, की थी। क्या मैंने कुछ गलत किया?

पत्नी - कुछ भी गलत नहीं किया। गलत तो मैं ही थी। मुसीबत के समय एक-दूसरे के काम आना ही पड़ोसियों का सच्चा धर्म है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने अपना पड़ोसी धर्म अच्छी तरह निभाया। मुझसे जो इतनी बड़ी गलती हुई उसके लिए मुझे माफ कर देना।

नफे - अब आई न लाइन पर।

पत्नी - हां, और अब हमेशा लाइन पर रहूंगी।

तभी उन्हें अपने पड़ोस में रहने वाले सूबे के घर कुछ आवाज सुनाई दी। सूबे की पत्नी उससे जोर-जोर से चिल्लाकर लड़ने में लगी हुई थी।

सूबे की पत्नी - खबरदार जो नफे भाई साहब के घर की ओर झांक भी लिया तो तुम्हारी खैर नहीं।

सूबे - काहे को आसमान सर पर उठा रखा है।

सूबे की पत्नी - आसमान सिर पर न उठाऊं तो और क्या करूं। तुम अपनी आदतानुसार नफे भाई साहब से गुटर-गूं किए बिना मानोगे नहीं। उस गुटर-गूं के बाद कोरोना तुम्हारे संग आकर अपने पूरे परिवार से गुटर-गूं करेगा। इसलिए कृपा करके अपने परिवार की सलामती के लिए उनके घर से कुछ दिन के लिए दूर ही रहना।

सूबे - ठीक मेरी मां, मैं आज से नफे के घर की ओर मुंह करके सांस भी नहीं लूँगा।

नफे की पत्नी - सुन रहे हो? इस बदमाश औरत की जितनी मैंने मदद की होगी, उतनी तो इसके किसी सगे-संबंधी ने भी नहीं की होगी। फिर भी इसकी बातें हमारे लिए इतनी जहरीली हो रखीं हैं।

नफे - शायद सूबे की पत्नी पर तुम्हारी संगत का असर हो गया है।

नफे की पत्नी एक बार को गुस्से में नफे को देखती है और फिर ठहाका मार कर हंसने लगती है। नफे भी उस ठहाकों की दुनिया में ठहाके लगाते हुए शामिल हो जाता है। उन ठहाकों में नफे की पत्नी की आवाज सुनाई देती है 'काश! सूबे भाई साहब पर आपकी संगत का असर हो और वो भी आपकी तरह पड़ोसी धर्म निभाना न भूलें।'

'बिलकुल असर होगा।' ठहाकों के बीच नफे का जवाब गूंजा।

● **सुमित प्रताप सिंह**

PRISM® CEMENT
प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस
ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.
PRISM®
चैम्पियन सीमेंट
प्लस
PRISM CHAMPION PLUS
Portland Pozzolana Cement (Fly Ash Based)
PRISM JOHNSON LIMITED
Toll free: 1800-3000-1444
Email: cement.customerservice@prismjohnson.in
दूर की सोच®

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

Science House Medicals Pvt. Ltd.

17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbpl@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687